



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2003/आश्विन 8, 1925

No. 154]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2003/ASVINA 8, 1925

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2003

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

संख्या/1-सी०ए०(5)/54/2003.— चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (5) की व्यवस्थाओं के अनुसार 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद् की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) तथा अंकेक्षित लेखा की एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना हेतु एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

54 वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् को 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आई.सी.ए.आई.), जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी, इस वर्ष के दौरान अपनी स्थापना के 54वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। परिषद् इस सम्मान के लिए सदस्यों और छात्रों की प्रशंसा करती है जो चार्टर्ड लेखाकर्म वृत्ति को आज समाज में प्राप्त है। यह सम्मान सदस्यों और छात्रों द्वारा सर्वथा प्रदर्शित उत्कृष्टता, स्वाधीनता और सत्यनिष्ठ से हासिल हुआ है।

यह कहना अत्योशक्ति नहीं होगी कि यदि यह कहा जाए कि रिपोर्टाधीन वर्ष न केवल देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट वृत्ति के लिए जिसके लिए कारण आशय नहीं है बल्कि विश्व भर में लेखाकर्म वृत्ति की घोर निन्दा की गई और जिस प्रकार से तथ्यों और आंकड़ों को तोड़-मोड़ कर प्रस्तुत किया गया उससे वृत्ति को और सुदृढ़

करने के लिए अनुकूल सक्रिय उपाय किए गए। सदस्यों को समय-समय पर इसमें बराबर रखा गया है। सारांश में, सभी स्तरों पर पर्याप्त मूल्यांकन करने के लिए तथ्यों और महत्व के विकीर्णन पर संभावनाओं की दूरी को कम करने, तकनीकी और शिक्षा मानकों के सत्र को बढ़ाने और नए और सामान्य क्षेत्रों में वृत्ति की भूमिका को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था। संकट में चुनौती मिलती है और अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पूर्व की तरह ही, वृत्ति ने चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया और यह अधिक शक्तिशाली बन पर उभरी है।

रिपोर्ट में परिषद् और उसकी विभिन्न समितियों की महत्वपूर्ण कार्यकलापों को प्रमुखता से अंकित किया गया है। रिपोर्ट में, आयोजित की गई संगोष्ठियों/सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सदस्यों और छात्रों से संबंधित प्रासंगिक आंकड़ों एवं वर्ष 2002-03 के संस्थान के लेखाओं को भी समावेश किया गया। जुलाई, 2003 के अंत तक के आई.सी.ए.आई. के महत्वपूर्ण कार्यकलापों और प्रमुख पहलुओं का भी संक्षेप में वर्णन किया गया है।

1. परिषद्

अट्ठारहवीं परिषद् का गठन 4 फरवरी 2004 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 5 फरवरी 2001 को किया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसार परिषद् में 30 सदस्य होते हैं। 24 निर्वाचित सदस्यों और 6 सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। 5 फरवरी, 2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष 2003-2004 की परिषद् का गठन अलग से दर्शाया गया है।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में तीन स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों का गठन 5 फरवरी, 2003 को किया। उपरोक्त के अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान शिक्षा और प्रशिक्षण पद्धति की समीक्षा करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण मुनरीक्षण समिति का गठन भी किया गया जिससे कि परिवर्तशील माहौल में और वृत्ति की मांग के संदर्भ में सी ए अर्हता की सुसंगति और पर्याप्तता को सुनिश्चित किया जाए। 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 159 बैठकें आयोजित की गईं, जबकि 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के दौरान 154 बैठकें की गई थीं।

3. संपरीक्षक

श्री ए.सी. बब्बर, एस.सी.ए. और श्री राजीव रस्तोगी, एफ.सी.ए. वर्ष 2002-03 के लिए आई.सी.ए.आई. के संयुक्त संपरीक्षक थे। परिषद् उनकी सेवाओं की प्रशंसा करती है।

4. स्थायी समितियां

4.1 कार्य - समिति

यह समिति छात्रों/सदस्यों/फर्मों से संबंधित विभिन्न रजिस्टर रखने, सदस्यों के प्रवेश, हटाए जाने और उनके पुनः स्थापन के कार्य की देख-रेख करती है, जिसमें व्यवसाय प्रमाण-पत्र के निर्गमन समेत सदस्यों से संबंधित विषयों पर छात्रों से संबंधित सब विषयों पर जिनमें उन्हें अनुज्ञा

देना, छात्रों/सदस्यों/फर्मों की ओर से किए गए विलम्ब की माफी, भी शामिल हैं, शाखाओं से सम्बद्ध विषयों, जिनमें नई-नई शाखाएं खोलना, विदेश में नए चैप्टर खोलना तथा कर्मचारियों से संबंधित विषयों, लेखा रखने आदि विषयों पर भी यह समिति विचार करती है।

समिति द्वारा परिषद् को की गई कुछ सिफारिशें ये हैं :-

- ◆ इन्टरनेशनल इन्नोवेटिव नेटवर्क का संस्थापक सदस्य बनना
- ◆ चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए प्रशिक्षण गाइड का पुनरीक्षित प्रारूप
- ◆ पश्चिमी क्षेत्र में, अहमदनगर में प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की स्थापना हेतु
- ◆ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2001 के विनियम 43(8) के अनुसार सदस्यों को अतिरिक्त आबद्ध शिक्षार्थी नियोजित करने को अनुज्ञात करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
- ◆ 30 कर संपरीक्षाओं की सीमा के मानिटर करने के प्रयोजन के लिए कर संपरीक्षा अभिलेख का प्रारूप
- ◆ सी.पी.ई कार्यक्रम आयोजित करने के सीमित प्रयोजन के लिए प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं के अंतर्गत न आने वाले स्थानों पर भारत के भीतर चैप्टर बनाए जाने और उनके कार्यकरण के लिए मानक
- ◆ पीई-II परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रशिक्षण में आने वाले आबद्ध शिक्षार्थियों को संदेय वृत्तिका की दर में वृद्धि
- ◆ छात्र-संबंध पूछताछ के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
- ◆ परिषद् की बैठक पूर्ण होने के पश्चात् प्रेस की जानकारी में लाए जाने वाले मामलों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत
- ◆ परिषद् की विभिन्न समितियों की स्वायत्तता और अनुमोदन/नोटिंग के लिए कार्य-समिति को भेजे जाने वाले विषयों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत

- ◆ पारदर्शिता और अच्छे निगमित शासन के लिए संस्थान के लेखा प्रत्येक तिमाही के पश्चात् इस समिति के समक्ष प्रस्तुत करना
- ◆ प्रदेशिक परिषदों द्वारा समितियां गठित किए जाने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत
- ◆ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 204 “अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन” पर नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रारम्भ का संशोधन
- ◆ भारत के भीतर अध्ययन केन्द्र बनाना और उनके कार्यकरण के मानक
- ◆ देश में अच्छे निगमित शासन के संवर्धन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले निगमित शासन के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का संस्थापिक सदस्य बनने के लिए अनुमोदन
- ◆ एक नियोजक के पास से अन्य नियोजक को स्थांतरित किए जाते समय आबद्ध शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण के ग्राहक-वार ब्यौरे प्रस्तुत करने की अपेक्षा को समाप्त करना
- ◆ बीमा और जोखिम प्रबंध में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और तकनीकी परीक्षा फीस

4.2 परीक्षा समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं मई 2002 से दुबई और काठमांडु के अतिरिक्त 85 शहरों में क्रमशः 137 और 144 केन्द्रों पर आयोजित की गई और नवम्बर 2002 में दुबई और काठमाण्डु के अतिरिक्त 87 शहरों में क्रमशः 134 और 140 केन्द्रों पर आयोजित की गई। फाउंडेशन/वृत्तिक शिक्षा-I, मई 2002 में 129 केन्द्रों पर और नम्बर 2002 में 119 केन्द्रों पर आयोजित की गई। मई 2002 से बीकानेर और उड़िषी में नए परीक्षा, केन्द्र स्थापित किए गए। साथ ही, नवम्बर 2002 परीक्षा से भटिंडा और अकोला में भी परीक्षा केन्द्र स्थापित किए गए।

मई 2002 में आयोजित फाइनल, इंटरमिडिएट/वृत्तिक शिक्षा-II और फाउंडेशन/वृत्तिक शिक्षा-I परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल

संख्या क्रमशः 33817, 48822 और 19934 थी और नवम्बर 2002 में क्रमशः 32575, 56305 तथा 13794 थी।

मई 2003 में, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल और वृत्तिक शिक्षा -II परीक्षाएं दुबई और काठमांडु के अतिरिक्त 90 शहरों में 126 और 142 केन्द्रों पर आयोजित की गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन/वृत्तिक शिक्षा-I परीक्षा मई 2003 में 90 शहरों में 123 परीक्षा केन्द्रों पर और दुबई तथा काठमांडु में आयोजित की गई। मई, 2003 से गुडगांव और हुबली में भी नए परीक्षा केन्द्र खोले गए।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित सुविधाएं जारी रही -

- ◆ ओ.एम.आर. प्रारूप में परीक्षा आवेदन-पत्र जारी रखे गए और अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिए गए जिनमें उनके स्केण्ड फोटो चित्र और नमूना हस्ताक्षर थे। इससे अभ्यर्थियों को अलग से पहचान पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं रही।
- ◆ परीक्षा आवेदन पत्र संस्थान के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं के अलावा, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई महानगरों में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराए गए। ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा बताए गए निजी पहचान संख्यांक (पिन) का प्रयोग करके उन्हें दी जा सकती है।
- ◆ परीक्षाफल और अंक दिल्ली और मुम्बई महानगरों में विभिन्न स्थानों पर साथ-साथ उपलब्ध रहेंगे।
- ◆ परीक्षाफल संस्थान की आई.वी.आर. प्रणाली पर उपलब्ध कराए गए। परीक्षाफल और अंकों को नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर के वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। वेबसाइट पर योग्यता सूची को भी परीक्षाफल की घोषणा के साथ ही प्रदर्शित किया गया।
- ◆ संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय परीषदों की शाखाओं द्वारा परीक्षाफल और अंक

डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षाफल की घोषणा के साथ ही उपलब्ध कराई गई।

- ◆ मई, 2003 परीक्षाओं से, अभ्यर्थियों द्वारा उनके ओ.एम.आर/आई.सी.आर. परीक्षा फार्म में उपदर्शित निजी पहचान संख्यांक (पिन) का प्रयोग करके अंकों का विवरण ऑन लाइन मुद्रित करने की सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
- ◆ घोषणा होने पर, परीक्षा फल का पता लगाने के लिए अग्रिम अनुरोध दर्ज करने की सुविधा जारी रखी गई और उसे दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा फल की घोषणा के तुरन्त बाद इ-मेल से उनके परीक्षाफल उपलब्ध कराए गए।

परीक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में कुछ विदेशी संस्थाओं को बराबर परामर्श दिया जाता रहा। नेपाल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने आई.सी.ए.आई. की निरन्तर तकनीकी विशेषज्ञता के सहयोग से परीक्षाएं सफलतापूर्वक संचालित कीं।

4.3 अनुशासन समिति

यह समिति संस्थान द्वारा प्रदत्त वृत्तिक अर्हता का स्तर और मानक बनाए रखने में परिषद् की सहायता करती है। अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 की अवधि में उन सदस्यों के खिलाफ जिनके मामले प्रथम दृष्टतया राय पर परिषद् द्वारा उसके पास भेजे गए हैं, अनुशासनिक जांच करने के अपने कृत संकल्प उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए समिति ने देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर 49 दिन तक 28 अवसरों पर अपनी बैठकें की। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने 63 मामलों में अपनी जांच पूरी की। इसमें वे भी शामिल थे जो परिषद् द्वारा पूर्व वर्षों में भेजे गए थे।

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

उत्कृष्टता हासिल करने और उसे स्थिर रखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए परिषद् ने अपनी विभिन्न अस्थायी समितियों के माध्यम से तकनीकी अनुसंधान, वृत्तिक विकास सदस्यों की

निरन्तर वृत्तिक शिक्षा और छात्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर और अधिक जोर देना जारी रखा।

परिषद् द्वारा स्थापित तकनीकी समिति ने लेखांकन, संपरीक्षा और सम्बद्ध क्षेत्रों में अपना प्रयास जारी रखा।

जबकि अनेक शोध कार्यकलाप हाथ में लिए गए/पहचाने गए, लेखांकन मानक, संपरीक्षा मानक, विशेषज्ञ राय, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस्तेमाल के लिए आधार सामग्री पर अनेक प्रकाशन अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से निकाले। इन कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल है :-

5.1 लेखांकन मानक

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड का, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएस) के प्रायः समकक्ष हो जानेके पश्चात् यह सुनिश्चित करने के लिए बल दिया गया कि जारी किए गए नए लेखांकन मानकों को कारगर रूप से क्रियान्वित किया जाए जिससे कि इन मानकों को जारी करने का प्रयोजन अर्थात् अर्थपूर्ण और पारदर्शक वित्तीय रिपोर्टिंग, सिद्ध हो सके। इस दिशा में, इस अवधि के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड ने अनेक लेखांकन मानकों की बाबत बहुत से लेखांकन मानक, व्याख्या और सामान्य स्पष्टीकरण जारी किए हैं।

विश्वभर में लेखांकन में हो रहे विकास के साथ गति बनाए रखने की दृष्टि से बहुत से लेखांकन मानकों के पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी गई है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पुनरीक्षित लेखांकन मानक (एस) 11, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव जारी किए गए हैं जो 1.4.2004 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाली लेखांकन अवधियों की बाबत अनिवार्य हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से लेखांकन मानकों का पुनरीक्षण प्रगति पर है।

जहां लेखांकन मानक व्याख्याएं सामान्य स्पष्टीकरण और लेखांकन मानकों के पुनरीक्षण पर बल दिया गया है, वहीं आईएस से तत्समान नए लेखांकन मानक बनाने की भी उपेक्षा नहीं की गई है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान उपबंधों,

आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियों पर प्रस्तावित लेखांकन मानक का अपावरण जारी किया जा चुका है जबकि “वित्तीय लिखतें” पर प्रस्तावित लेखांकन मानक पर कार्य में काफी प्रगति हुई है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड द्वारा अपनी “सुधार परियोजना” के भाग रूप में, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएसबी) द्वारा जारी तेरह अपावरण प्ररूपों की जांच की गई। जांच के आधार पर, बोर्ड ने अपावरण प्ररूपों पर अपनी विस्तृत टिप्पणियां आई ए एस बी को प्रस्तुत कीं।

उपरोक्त के अलावा, कुछ और लेखांकन मानकों और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रगति पर है।

सरकारी निकायों के लिए लेखांकन मानकों पर बोर्ड की उप-समिति, सरकारी निकायों के लिए अवधारणात्मक रूप रेखा और लेखांकन मानक तैयार करने में लगी हुई है।

5.2 संपरीक्षा मानक

संपरीक्षा पद्धति समिति, जो मूलतः संस्थान की अनुसंधान समिति की उपसमिति के रूप में गठित की गई थी, सितंबर, 1982 में एक पृथक और स्वतंत्र अस्थायी समिति बना दी गई थी। सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के सतत प्रयास में, संस्थान की परिषद् द्वारा, इस समिति का गठन विद्यमान सर्वोत्तम संपरीक्षा पद्धति को संहिताबद्ध करने का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टेटमेंट्स ऑन स्टैंडर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसिज़ (सेप्स) बनाने के बुनियादी उद्देश्य से किया गया था। सेप्स, संस्थान की परिषद् के प्राधिकार के अंतर्गत जारी किए जाते हैं और ये आज्ञापक प्रकृति के हैं। तथापि, समिति, संपरीक्षा से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शक टिप्पण भी जारी करती है। अपने अस्तित्व की अवधि के दौरान, समिति 29 से अधिक सेप्स और बीस से अधिक मार्गदर्शक टिप्पण जारी कर चुकी है। दोनों ही संपरीक्षा से संबंधित विषयों पर प्रजातिगत और उद्योग-विशिष्ट हैं। गत वर्ष, संपरीक्षा पद्धति समिति के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष था। परिषद् ने, समिति द्वारा किए जा रहे कृत्यों की प्रकृति को स्पष्ट

करने के लिए समिति को संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड के रूप में 2 जुलाई, 2002 से पुनः नामांकित किया है। परिणामतः, स्टेटमेंट्स ऑन स्टैंडर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसिज़ की नामावली को भी बदल कर संपरीक्षा और आश्वासन मानक कर दिया गया। तथापि, परिषद् का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कदम, जो समिति के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया, विनियम को जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, उद्योग प्रतिनिधि उदाहरणार्थ भारतीय उद्योगों का परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, शैक्षिक क्षेत्र जैसे अनेक भारतीय प्रबंध संस्थानों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करना था।

परिषद् ने यह भी विनिश्चित किया कि समिति द्वारा जारी किए गए अपावरण प्ररूप की प्रतियां स्टाक एक्सचेंजों, भारत के महानियंत्रक और संपरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाएं और साथ ही अपावरण प्ररूपों की सार्वजनिक सुनवाई के लिए बैठकें आयोजित की जाएं।

गत वर्ष, शायद ए.ए.एस.बी. के कार्यकाल का सबसे अधिक व्यस्त वर्ष था जिसके दौरान संगोष्ठियों का आयोजन हुआ, अनेक नए और पुनरीक्षित ए.ए.एस. और दो मार्गदर्शक टिप्पण जारी किए गए। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

5.2.1 संगोष्ठियां

बोर्ड ने, जनवरी, 2003 में हैदराबाद में “आडिटर्स, आडिटीज एंड रेगुलेटर्स : ओल्ड रिलेशनशिप्स, न्यू रियलिटीज” विषय पर अखिल भारतीय संगोष्ठी आयोजित की। संपरीक्षकों की स्वतंत्रता, लेखांकन और संपरीक्षा मानक, वृत्ति का विनियमिकरण, बैंकिंग, बीमा, निगमित शासन आदि जैसे अनेक मुद्दों से संबंधित बहुत से विषयों पर भी चर्चा की गई। संगोष्ठी में लगभग 1200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

5.2.2 जारी किए गए दस्तावेज

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दस आडिटिंग एंड एश्योरेंस सेटेंडर्स (तीन पुनरीक्षित सहित) जारी किए गए। संपरीक्षा बैंकों पर मार्गदर्शक टिप्पण का पूरक भी जारी किया गया। बैंकों की संपरीक्षा पर एक अद्यतन मार्गदर्शक पूरक की व्यवस्था की गई। बोर्ड ने अप्रैल, 2002 में जारी संपरीक्षक रिपोर्ट का प्रूफ भी प्रकाशित किया और बाद में दिसंबर, 2002 में उसे पुनरीक्षित किया। (तथापि, एएएस 28 के जारी किए जाने के अनुसरण में प्रारूप वापस लिया गया)

ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा, संस्थान की परिषद द्वारा दूसरी अनेक दस्तावेजों का भी अनुमोदन किया गया जो शीघ्र ही प्रकाशित की जाएंगी।

5.2.3 सामान्य स्पष्टीकरण

वर्ष के दौरान, बोर्ड को स्टेटमेंट्स आन स्टैंडर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसेज (अब संपरीक्षा और बीमा मानक के रूप में नामित) से उत्पन्न विषयों पर सामान्य स्पष्टीकरण जारी करने के लिए भी सशक्त किया गया। तदनुसार, बोर्ड ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टेटमेंट आन स्टैंडर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसेज (सेप-9) “अन्य संपरीक्षा के कार्य का प्रयोग करना” पर सामान्य स्पष्टीकरण जारी किया।

5.2.4 संपरीक्षा उद्घोषणाओं की पुस्तिका

बोर्ड ने पहली बार अपने प्रकार की संपरीक्षा उद्घोषणाओं की पुस्तिका भी दो जिल्दों में निकाली है। पुस्तक में अन्य रूप से परिषद् की संपरीक्षा उद्घोषणाएं शामिल की गई हैं, जैसे द स्टेटमेंट्स आन स्टैंडर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसेज और संपरीक्षा से संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शक टिप्पण। 1 जुलाई, 2002 तक जारी किए गए सभी सेप्स सम्मिलित करने वाली कम्पेक्ट डिस्क के रूप में अन्य नई संकल्पना प्रारम्भ की गई। यह सीडी पुस्तिका का भाग है।

5.2.5 आईआरडीए के साथ संयुक्त समिति

इस वर्ष के दौरान, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) तथा संस्थान की एक संयुक्त समिति का गठन बृहत् स्तर पर संपरीक्षा और बीमा उद्योग से संबंधित प्रमुख विषयों पर विचार करने और सुझाव देने के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म के रूप में किया गया। संयुक्त समिति की प्रथम बैठक जुलाई, 2003 को चैन्नई में हुई। विचारण का केन्द्र पूंजी निवेश से संबंधित मामले, लेखांकन विनियम और बीमाकिक विनियमों से संबंधित विषय थे।

5.2.6 भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पारस्परिक क्रिया

इस वर्ष में, समिति के प्रतिनिधियों ने इसके अध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों के साथ गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) और अनिगमित निकायों के विनियमन के मुद्दे पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। उक्त बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया जैसे कि एन बी एफ सी के भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रजिस्ट्रीकृत होने पर उनकी प्रास्थिति, ऐसी कंपनियों के अप्राधिकृत क्रिया कलाप जिनके रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र खारिज कर दिए गए हैं या जिन्होंने रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन नहीं किया, भारतीय रिज़र्व बैंक की संसूचनाओं का उत्तर न देने वाली कंपनियां, आवश्यक विधान पारित करने में सरकारी विलंब, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अवसंरचना की कमी, आई सी ए आई कंपनी कार्य विभाग, कंपनी विधि बोर्ड द्वारा एन.बी.एफ.सी. और अनिगमित निकायों को विनियमित करने के लिए इनके द्वारा किया गया अंशदान, विभिन्न निकायों के मध्य संयोजन की आवश्यकता आदि।

5.2.7 देश में महत्वपूर्ण विधायी विकास के संबंध में उत्तर

(i) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2003

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2003 के प्रति उत्तर था। बोर्ड ने संस्थान की निगमित विधि समिति के साथ जून, 2003 में एक संयुक्त बैठक आयोजित की जिसका बुनियादी प्रयोजन कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2003 पर चर्चा करना और उसमें मौजूद विसंगतियों की पहचान करना था। उक्त संयुक्त बैठक में कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 पर भी विचार किया गया। उक्त बैठक के बाद विधेयक पर गोलमेज पर चर्चा की गई जिसमें अन्यो के अलावा कंपनी कार्य विभाग के संयुक्त सचिव ने भाग लिया। उक्त बैठक और गोलमेज में विचार-विमर्श के पश्चात् जिन टिप्पणियों को अंतिम रूप दिया गया उन्हें कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2003 के संबंध में सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन में शामिल किया जाएगा।

(ii) कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003

कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 जारी किए जाने के उत्तर में जो विद्यमान विनिर्माणकारी और अन्य कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 1988 को प्रतिस्थापित करेगा, बोर्ड ने संस्थान के विनिर्माणकारी और अन्य कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 1988 संबंधी विवरण के पुनरीक्षण के लिए एक अध्ययन समूह का गठन भी किया है जिससे कि वह सदस्यों को कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 को समुचित रूप से समझने और इसकी रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को पूरा करने में भी समर्थ बना सके।

(iii) अंतरराष्ट्रीय विकास के प्रति जागरूकता

बोर्ड, इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (आई एफ ए सी) के इन्टरनेशनल आडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड (आई ए ए एस बी) में होने वाले विकास के प्रति जागरूक रहा है। हाल ही में, बोर्ड ने आई एफ ए सी द्वारा जारी किए तीन महत्वपूर्ण अपावरण प्ररूपों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, अर्थात् इन्टरनेशनल फरेमवर्क फार एश्योरेंस इंगेजमेंट्स, आई एस ए ई 2000 - एश्योरेंस इंगेजमेंट्स आन सब्जेक्ट मेटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनैन्शियल इन्फारमेशन और (पुनरीक्षित) इन्टरनेशनल आडिटिंग प्रेक्टिसेज स्टेटमेंट्स आन स्पेशल कनसिडरेशन्स इन एन आडिट आफ स्माल इन्टेटीज। इसके अलावा बोर्ड ने स्टैंडर्ड्स आन स्टैंडर्ड आडिटिंग प्रेक्टिसेज की प्रस्तावना को आई ए ए एस बी द्वारा जारी संपरीक्षा पर अंतरराष्ट्रीय मानक की प्रस्तावित प्रस्तावना के समरूप बनाने के लिए इसे पुनरीक्षित करने लिए भी कदम उठाए हैं।

(iv) प्रगति में परियोजनाएं

संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड ने चारों ओर वृत्तिक और विधिक क्षेत्र में होने वाले अद्यतन विकास से सदस्यों को अवगत रखने के लिए और समाज की बढ़ती हुई अपेक्षाओं के साथ गति बनाए रखने के लिए भी अनेक महत्वकांक्षी परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं।

5.3 अनुसंधान

अनुसंधान समिति, संस्थान के सदस्यों द्वारा उनके वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन में मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से और प्रदान की जा रही सेवा के मूल्य संवर्धन के लिए विनिर्दिष्ट उद्योगों के लेखांकन और संपरीक्षण पर मार्गदर्शक टिप्पणों, अनुसंधान अध्ययन, तकनीकी गाइड, विनिर्दिष्ट उद्योगों के लेखांकन और संपरीक्षण पर मार्गदर्शक टिप्पणों, अनुसंधान अध्ययन, तकनीकी गाइड, विनिर्दिष्ट उद्योगों की बाबत आंतरिक संपरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांतों, मोनोग्राफों आदि के रूप में

अनेक प्रकाशन निकालती है। इस वर्ष के दौरान समिति ने दो मार्गदर्शक टिप्पण बनाए हैं अर्थात् तेल और गैस उत्पादन क्रियाकलापों के लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण और प्रतिभूतिकरण के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण। इन्हें मार्च, 2003 में संस्थान की परिषद के प्राधिकार से जारी किया गया।

ऐसे लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे का सुझाव देने की दृष्टि से जो दुरस्त लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित हो और जो परिस्थिति का सच्चा और साफ दृश्य प्रस्तुत करे और वित्तीय विवरणों में क्रियाकलाप के परिणाम संचालित करे, समिति ने लाभ-के-लिए नहीं संगठनों के लिए लेखांकन और संपरीक्षा हेतु तकनीकी गाइड जारी की। ऐसी आशा है कि सेक्टर में दुरस्त लेखांकन पद्धति अपनाए जाने के संवर्धन में तकनीकी गाइड महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आंतरिक संपरीक्षा पर तकनीकी गाइड -टर्स एंड ट्रेवल सर्विसेज का भी समिति द्वारा लोकार्पण किया जा चुका है।

उपरोक्त के अलावा, इक्युटी इंडेक्स एंड इक्युटी स्टाक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन्स के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण और चिट फंड कारबार के लेखांकन और संपरीक्षा के लिए तकनीकी टिप्पण अंतिम चरण में हैं और उनके शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है।

कतिपय अनुसंधान परियोजनाओं प्ररूप, जिनके अंतर्गत डिमर्जस के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण, एम्पलाइज स्टाक ऑप्शन्स और एम्पलाइज स्टाक परचेज प्लान्स के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण निर्माण अवधि के दौरान ट्रीटमेंट आफ एक्सपेंडीचर पर पुनरीक्षित मार्गदर्शक टिप्पण और भावी रोकड़ और बट्टा दरों के प्राक्कलन की गाइड हैं, समिति के विचाराधीन हैं। वर्ष के दौरान समिति ने कुछ नए मार्गदर्शक टिप्पण निकालने का विनिश्चय किया है, जैसे - ब्याज दर फ्यूचर्स और ऑप्शन्स के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण और लायलिटी कार्यक्रमों के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण।

उद्योग - विशिष्ट मुद्दों पर सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से, समिति ने अनेक नए उद्योगों की बाबत लेखांकन और

संपरीक्षा पर विशिष्ट तकनीकी मार्गदर्शन और/या आंतरिक संपरीक्षा पर मार्गदर्शन निकालने का निश्चय किया है। इसके अलावा, समिति ने 1 जनवरी, 1995 के पूर्व प्रकाशित सभी अनुसंधान अध्ययनों को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है। साथ ही, अन्य परियोजनाओं की बाबत भी, जो पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं, महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

अनुसंधान समिति ने गत वर्ष, “मार्गदर्शक सिद्धांतों का सार संग्रह - लेखांकन” प्रकाशित किया जिसमें 1 जुलाई, 2002 तक लेखांकन पर जारी किए गए और जो आज भी विधिमान्य हैं, सभी मार्गदर्शक टिप्पण शामिल किए गए हैं। उक्त सार संग्रह, इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रति वाली सीडी के साथ जारी किया गया है। 1 जुलाई, 2003 तक का सार संग्रह तैयार किया जा रहा है और उसके शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है। 1 जुलाई, 2003 तक प्रकाशित अनुसंधान अध्ययन, जो वर्तमान में पुनरीक्षित नहीं किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रति वाली एक सीडी भी तैयार की जा रही है और इसे भी शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है।

इस वर्ष के दौरान, समिति के तत्वावधान में, रसायनिक उद्योग की बाबत प्ररूप लागत लेखांकन अभिलेख नियम पर टिप्पणियां कंपनी कार्य विभाग को भेजी गई है। प्रस्तुत की गई अधिकतर टिप्पणियां विभाग द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

प्रकाशित लेखाओं में सूचना प्रस्तुतकरण में बेहतर मानकों का विकास करने की दृष्टि से, अनुसंधान समिति की उप समिति शील्ड पेनल के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत लेखाओं के लिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत लेखा प्रतियोगिता 2001-02 के अन्तर्गत, विभिन्न प्रवर्गों के अधीन वर्ष 2001-02 के लिए अनेक उद्यमों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टें और लेखाओं पर न्यायधीशों के एक पैनल द्वारा विचार किया गया और पुरस्कार देने का विनिश्चय किया गया। पुरस्कार, माननीय केन्द्रीय खान राज्य मंत्री श्री रमेश बियास द्वारा 4 फरवरी, 2003 को आयोजित आई सी ए आई के वार्षिक समारोह में दिए गए।

उक्त प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए, हाल ही में, यह विनिश्चय किया गया है कि प्रतियोगिता के शीर्षक “वार्षिक सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत लेखा प्रतियोगिता” को बदल कर “वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आई सी ए आई पुरस्कार” कर दिया जाए। इस समय, दिए जाने के लिए प्रस्तावित पुरस्कार निम्नलिखित प्रवर्गों में हैं :

प्रवर्ग I - गैर वित्तीय लोक और निजी सेक्टर उद्यम (प्रवर्ग III के अन्तर्गत आने वालों से भिन्न)

प्रवर्ग II - लोक, निजी और सहकारी सेक्टरों में वित्तीय संस्थाएं जैसे - बैंक, बीमा कंपनियां, एन बी एफ सी, आदि।

प्रवर्ग III - लाभ-के लिए-नहीं संगठन, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियां शामिल हैं।

प्रस्तावित पुरस्कारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि पुरस्कार विजेताओं को इनाम वितरित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाए।

यह भी विनिश्चित किया गया है कि प्रवर्ग-I के अन्तर्गत एक रजत शील्ड और दो ताम्र पट्टिका दिए जाएं जबकि प्रवर्ग II और III में एक-एक रजत शील्ड और एक-एक ताम्र पट्टिका दिया जाए।

5.4 निगमित विधियां

वर्ष 2002-03 महत्वपूर्ण उपलब्धियों का दौर था और इसमें निगमित विधि समिति को अपने उद्देश्यों में एक कदम आगे सफलता प्राप्त हुई। समिति द्वारा प्रारम्भ की गई अनेक परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस समिति के तत्वावधान में गठित अध्ययन समूह ने व्यापक अध्ययन के पश्चात् एक मा ए ओ सी ए आर ओ (माओकारो) के पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। माओकारो का पुनरीक्षित अंतिम पाठ समुचित अधिसूचना के लिए कंपनी कार्य विभाग को प्रस्तुत

किया गया। समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के पुनरीक्षण के लिए भी पहल की है। इस वर्ष के दौरान निगमित विधियों से संबंधित अनेक समसामयिक विषयों पर संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किए गए। समिति ने, कंपनी कार्य विभाग के अधिकारियों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया।

5.5 राजकोषीय विधियां

अतीत की भांति राजकोषीय विधि समिति ने संघीय बजट 2003 पर एक कार्यशाला की। अन्य व्यक्तियों के अलावा कार्यशाला में वरिष्ठ सरकारी प्राधिकारियों ने भाग लिया। पोस्ट बजट मेमोरैंडम-2003 सरकार को प्रस्तुत किया गया। उससे पूर्व समिति ने अपना पूर्व बजट ज्ञापन 2003 भी सरकार को प्रस्तुत किया था। बहुत से सुझावों को स्वीकार कर सरकार द्वारा वित्त विधेयक 2003 में समाविष्ट किया गया। बाद में पोस्ट बजट ज्ञापन-2003 में कुछ और सुझाव भी वित्त विधेयक, 2003 के पारित होकर अधिनियम बनाते समय स्वीकार कर लिए गए।

समिति ने “इशूज़ आन टेक्स आडिट” का दूसरा पुनरीक्षित संस्करण निकाला। समिति ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेख के अधीन संपरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पण पुनरीक्षित किया। समिति ने एक ऐतिहासिक प्रकाशन “डेप्रीसिएशन - अकाउंटिंग, टेक्सेशन एंड कंपनी लॉ इशूज़ - ए स्टडी” निकाला। यह प्रकाशन लेखांकन, कराधान और कंपनी विधि के क्षेत्रों में अवक्षयण अनेक पहलुओं की आलोचनात्मक समीक्षा है।

समिति ने डा. विजय केलकर की अध्यक्षता में बनाई गई राष्ट्रीय टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर अपने सुविचारित विचार प्रस्तुत किए। समिति के प्रतिनिधि, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा गठित अवसंरचना पर टास्क फोर्स से मिले और समिति के सुझाव प्रस्तुत किए। इसी प्रकार, संस्थान के प्रतिनिधि ने अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से भेंट की और वृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श किया। समिति ने सी बी डी टी द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह को महत्वपूर्ण आगत (निवेश) प्रदान किए ताकि आय-कर अधिनियम, 1961 की

धारा 285खक के अधीन निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली वार्षिक सूचना विवरणी के लिए नियम और प्रारूप बनाए जा सकें।

समिति ने चैन्नई में कराधान पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी आयोजित की। इसके अलावा इसने दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद की मंगलोर शाखा के सहयोग से, मंगलोर में राजकोषीय और सहबद्ध विधियों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की।

5.6 वित्तीय बाजार और निवेशकर्ता संरक्षण

आधारिक वास्तविकताओं, निगमित सुशासन के लिए बढ़ती हुई चिंता और जरूरत तथा निवेशकों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, समिति ने इस वर्ष के लिए महत्वाकांक्षी कार्य योजना तैयार की है। मोटे तौर पर की गई पहल और प्राप्य कार्य योजना और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए एक केन्द्रित योजना को ध्यान में रखा गया है। बाजार विनियामकों अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) कंपनी कार्य मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श करके क्रियात्मक गति बनाए रखने के प्रयास किए गए हैं। वित्त विशेषज्ञता की मुख्य धारा में वृत्ति को शामिल करने की दृष्टि से भी, समिति ने ये प्रयास किए हैं कि कार्य को प्रारंभ करने की पहल की जाए। इस प्रयोजन के लिए समिति अर्होत्तर स्तर पर एक समुचित पाठ्य विवरण की संरचना अनुध्यात कर रही है। यह सोच, महत्वपूर्ण रूप से, वृत्ति के सदस्यों को वित्त वृत्तियों के बराबर लाने में सुकर बनाएगी - चालू वर्ष के दौरान की गई प्रहलें निम्नानुसार हैं :-

5.6.1 बाजार विनियामकों के साथ विचार-विमर्श

समिति और इसके अध्यक्ष ने सेबी की अनेक सलाहकार भारतीय कंपनियों और अनुषंगी बाजार द्वारा समकालिक भेंटों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा समिति और पारस्परिक निधि से विचार-विमर्श किया।

निवेशकर्ता संरक्षण के विशिष्ट निर्देश से समिति ने कंपनी कार्य विभाग के साथ डिबेंचर न्यासी निवेशकर्ता संरक्षण पर

अनेक बैठकें कीं।

5.6.2 लघु निवेशकर्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम

निवेशकर्ताओं को शिक्षित करने और उनमें जागरूकता लाने के प्रयास में, समिति ने संपूर्ण भारत में 10 चयनित निवेशकर्ता केन्द्रों पर लघु निवेशकर्ता जागरूकता कार्यक्रम के संचालक के लिए एक विशिष्ट कार्य योजना तैयार की है। ये कार्यक्रम निम्नलिखित प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के सहयोग से संचालित किए जाएंगे।

प्रदेश	शाखाएं/स्थान
पश्चिमी	मुम्बई वदोदरा
दक्षिणी	बंगलौर चैन्नई
मध्य	जयपुर आगरा
पूर्वी	कोलकाता गुवाहाटी
उत्तरी	नई दिल्ली

उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा, सेबी, डी सी ए और आर बी आई की सहायता और समर्थन से लघु निवेशकर्ताओं के एक दो दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन बुलाए जाने का प्रस्ताव है।

5.6.3 प्रबंध लेखांकन में अर्होत्तर पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना

समिति यह उचित समझती है कि वर्तमान में सी पी ई समिति द्वारा शासित प्रबंध लेखांकन में विद्यमान अर्होत्तर पाठ्यक्रम की पूर्णतया पुनः संरचना की जाए और यदि आवश्यक हो तो पाठ्यक्रम का नाम समुचित रूप से वित्त के क्षेत्र के निर्देश में परिवर्तित कर दिया जाए जिससे कि यह विशेषज्ञता के लिए वृत्ति के सदस्यों को अधिक अवसर प्रदान कर सके। व्यवसाय की व्यापक संभावनाओं और उपलब्ध क्षेत्र तथा वित्तीय प्रबंध क्षेत्र में इस समय चार्टर्ड अकाउंटेंटों

द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को तथा भविष्य में पैदा होने वाली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए समिति यह उचित समझती है कि एक समुचित पुनर्संरचित पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाए। इससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति में वित्त वृत्ति के बराबर सुधार आएगा।

इस संबंध में, समिति पाठ्यक्रम को पुनःसंरचना का कार्य और परीक्षाओं का संचालन स्वयं ही कर रही है।

5.6.4 प्रकाशन

वृत्ति के सदस्यों की सहायता करने की दृष्टि से समिति ने आर बी आई परिपत्रों का सार-संग्रह दो जिल्दों में निकाला है।

5.6.5 वित्तीय बाजार सेवाओं में चार्टर्ड अकाउंटेंटों से संबंधित बहुत से मामलों पर अध्ययन सामग्री

- (i) निगमित, वित्तीय और अन्य संबंधित विधियों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए व्यवसाय के उपलब्ध क्षेत्र
- (ii) भारतीय वित्तीय बाजारों के लिए स्व विनियामक तंत्र का मॉडल तैयार करना

5.6.6 पारस्परिक निधि कंपनियों के मुख्य कार्यपालिक अधिकारियों के साथ गोल मेज चर्चा

पारस्परिक निधि कंपनियों के मुख्य कार्यपालिक अधिकारियों के साथ गोल मेज चर्चा पारस्परिक निधि से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन समूह गठित किया गया था। अध्ययन समूह की रिपोर्ट पर विचार किया गया और अंतर्बलित अनेक गम्भीर मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, भारत में सभी पारस्परिक निधियों के मुख्य कार्यपालिक अधिकारियों के साथ एक गोल मेज पर चर्चा करना प्रस्तावित है जिससे कि उद्योग, निवेशकर्ताओं और विनियामकों से संबंधित आपसी मुद्दों पर विचार किया जा सके।

5.7 विशेषज्ञ राय

लेखांकन और संपरीक्षा के सिद्धांतों और संबंध क्षेत्रों वाले विषयों पर संस्थान से सदस्यों की आशंकाओं का उत्तर देने के उद्देश्य से विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति के पास भिन्न-भिन्न अनेक विषयों पर आशंकाएं आती हैं। रिपोर्ट की अवधि में, समिति ने 42 आशंकाओं पर राय को अंतिम रूप दिया। समिति ने खंड रिपोर्टिंग, उधार-खर्च, विनिधान, राजस्व स्वीकृति, आस्थगित कराधान, आदि जैसे लेखांकन मानक, मार्गदर्शक टिप्पण आदि के रूप में स्थापित लेखांकन सिद्धांतों से संबंध मुद्दों पर राय को अंतिम रूप दिया। इस प्रकार समिति की राय स्थापित लेखांकन और संपरीक्षा सिद्धांतों की व्याख्यात्मक रूपरेखा ही प्रदान नहीं करती है अपितु उन क्षेत्रों में सिद्धांत भी निर्धारित करती हैं जिनके संबंध में अब तक कोई अधिकारिक निर्णय प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में आई.सी.ए.आई. द्वारा अनेक लेखांकन मानक जारी करने के साथ, समिति की स्पष्टीकारक भूमिका का महत्व और भी बढ़ गया है।

वर्ष के दौरान अंतिम रायों को मत संग्रह के एक खंड में प्रकाशित किया जाता है। अभी तक, जनवरी 2002 तक समिति द्वारा अंतिम रायों से युक्त मत संग्रह के 21 खंड बिक्री के लिए जारी किए जा चुके हैं। फरवरी, 2002 और फरवरी, 2003 के बीच समिति द्वारा अंतिम राय से युक्त मत संग्रह के खंड 22 का संकल्प किया जा रहा है।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय, समिति में सम्मिलित सदस्यों की राय को दर्शाती है न कि अनिवार्य रूप से आई.सी.ए.आई. के परिषद की राय को। ये राय आशंकितकर्ता द्वारा उठाई गई आशंकाओं के तथ्यों और परिस्थितियों, लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों और प्रैक्टिस तथा उस तारीख को, जिसको समिति विशिष्ट राय को अंतिम रूप देती है, लागू सुसंगत विधि पर आधारित होती है। राय को अंतिम रूप देते समय, समिति संबंध क्षेत्रों में राष्ट्रीय गतिविधियों को ही ध्यान में नहीं रखती

अपितु विषय पर उभरते विचारों सहित सुसंगत अंतरराष्ट्रीय साहित्य को भी ध्यान में रखती है।

समिति द्वारा अंतिम रूप से दी गई कई रायों को अधिकांश सदस्यों की जानकारी के लिए संस्थान की पत्रिका चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जा रहा है।

5.8 अनवरत वृत्तिक शिक्षा

सार्वत्रिक ग्राम के युग में, निरन्तर वृत्तिक अद्यतन होने की जरूरत सर्वोत्तम है। सूचना प्रौद्योगिकी में विकास और व्यापार में गतिवाद तथा औद्योगिक पर्यावरण वृत्ति के सदस्यों के लिए नई-नई चुनौतियों और अवसरों के लिए महत्वपूर्ण है। सदस्यों की वृत्तिक सेवाओं का उच्च स्तर रखने में सुकर बनाने के लिए अनवरत वृत्तिक शिक्षा समिति (सी पी ई समिति) संगोष्ठियों, व्याख्यानों, आधार सामग्री और प्रबंध अकाउंटेंसी, कारपोरेट प्रबंध और कर प्रबंध में पश्य अर्द्धता पाठ्यक्रम संचालित करने के अलावा इलेक्ट्रानिक सीडिया का उपयोग करके निरन्तर उनका ज्ञानवर्धक कर रही है। समिति वृत्तिक कौशल को और बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है जिससे कि “चार्टर्ड अकाउंटेंट” शब्द सेवाओं में उत्कृष्टता का पर्याय हो जाए।

अनवरत वृत्तिक शिक्षा (सी पी ई) के महत्व को बढ़ाने और सी पी ई गतिविधियों की तीव्रता के स्तर को, उस परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन करके जिसके अंतर्गत वृत्तिक चार्टर्ड अकाउंटेंट विभिन्न हैसियत से अपने आपको क्रियाशील करते हैं और काम में लगाते हैं, बढ़ाने की दृष्टि से, संस्थान की परिषद् ने अनवरत वृत्तिक शिक्षा पर एक विवरण जारी किया है जो संस्थान द्वारा सी पी ई गतिविधियों और उसके सदस्यों के लिए विभिन्न साधनों के कार्यान्वयन के सन्निधिम विहित करता है।

अनवरत वृत्तिक शिक्षा, जो 1.1.2003 से प्रभावी है, के कथन के अनुसार :-

- ◆ प्रैक्टिस वाले सभी सदस्यों को (अपवादी सहित) प्रत्येक कलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 घंटे के साथ तीन वर्षों के ब्लाक में न्यूनतम 25 सी पी ई घंटे के उनके क्रेडिट को अभिप्राप्त करना आवश्यक है।

- ◆ उद्योग वाले सभी सदस्यों या प्रैक्टिस से भिन्न कार्यों में लगे सभी सदस्यों के लिए प्रत्येक कलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 घंटे के उनके क्रेडिट को अभिप्राप्त करने की सिफारिश की गई है।

उपरोक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए, संस्थान के सदस्यों को अवसर प्रदान करने के लिए, संस्थान के सभी सी पी ई कार्यक्रम आयोजक यूनिटों को सलाह दी गई है कि वे यथासंभव संपूर्ण देश में अनेक सी पी ई कार्यक्रम संचालित करें।

परिषद् ने भारत के भीतर सी पी ई कार्यक्रम आयोजित करने और साथ ही भारत में अध्ययन सर्किल बनाने और उनको कृत्यकारी बनाने के लिए सन्निधियों के सीमित प्रयोजन के भीतर न आने वाले स्थानों पर चैप्टरों को बनाने और उनको कृत्यकारी बनाने के लिए संनयम जारी किए हैं। सदस्यों को सी पी ई चैप्टरों और सी पी ई अध्ययन सर्किलों को बनाने के लिए उत्साहित किया जा रहा है जिससे कि सी.पी.ई. कार्यक्रम देश के प्रत्येक संभावित स्थान पर संचालित किया जा सके।

जैसा अनवरत वृत्तिक शिक्षा संबंधी कथन के अंतर्गत आवश्यक है, सी पी ई समिति ने निम्नलिखित पहलुओं पर सी पी ई एडवाइजरीज जारी किए हैं जिससे कि कार्यक्रम डिजाइनरों, विकासकर्ताओं और आयोजकों तथा सभी अन्य ऐसे व्यक्तियों को समर्थ बनाया जा सके जो निम्नलिखित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए सी पी ई गतिविधियों से जुड़े हों :

- ◆ कार्यक्रम विकास
- ◆ अधिगम तकनीकी का उपयोग
- ◆ मानीटर और पर्यवेक्षण
- ◆ सी पी ई प्रलेखन
- ◆ कार्यक्रम लागत प्रबंधन
- ◆ आधारभूत सामग्री का विकास
- ◆ नगरेत्तर क्षेत्रों तथा सुदूर स्थानों में सदस्यों को सी पी ई समर्थन।

जैसा सी पी ई एडवाइजर आन मानीटर्स और सुपरवाइजर्स के अंतर्गत अपेक्षित है, सुसंगत सी पी ई परामर्शों के अनुसार, सी पी ई कार्यक्रम आर्गेनाजिंग यूनिटों (पी ओ यू) के लिए मानीटरों और पर्यवेक्षणों को नामनिर्दिष्ट किया जा रहा है।

समिति ने सभी प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के लिए सी पी ई क्रेडिट घंटों की रिकार्डिंग और रिपोर्टिंग करने के लिए एक कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकसित किया है और उसे वितरित किया है। उस साफ्टवेयर का प्रयोग मुख्यालय द्वारा केन्द्रीय सी पी ई डाटाबेस के रख-रखाव के लिए किया जाएगा। संस्थान के वेबसाइट में केन्द्रीय सी पी ई डाटाबेस होस्ट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि सदस्य अपने सी पी ई क्रेडिट के बारे में जान सकें।

समिति ने संस्थान के प्रादेशिक स्तर पर सी पी ई से संबंधित गतिविधियों को मानीटर करने के लिए प्रादेशिक सी पी ई मानीटरिंग समितियों का गठन किया है।

चूंकि समिति का व्यापक आधार है और संस्थान के सदस्यों के लिए उनकी पोस्ट-अर्हता शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए है इसलिए समिति ने ऐसे पोस्ट अर्हता कार्यक्रमों को, जो समिति द्वारा चलाए जा रहे हैं, पुनः आरंभ करने की पहल की है।

तदनुसार, प्रबंध लेखांकन पाठ्यक्रम के स्थान पर वित्तीय प्रबंध पर प्रस्तावित पोस्ट-अर्हता पाठ्यक्रम को, वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में सदस्यों की उत्कृष्ट विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जा रहा है।

समिति कारपोरेट प्रबंध पाठ्यक्रम और कर प्रबंध पाठ्यक्रम कोर्स पाठ्यक्रम को पुनः आरंभ करने का कार्य भी कर रही है। समिति इन पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए समुचित उपाय कर रही है। पोस्ट अर्हता पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षित पाठ्यक्रमों को अनवरत वृत्तिक विकास पर आई एफ ए सी की आवश्यकता के साथ समकालिक बनाया जा रहा है।

संस्थान के उन सदस्यों की सी पी ई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए टेली क्रांफ्रेंसिंग

कार्यक्रमों को पुनः आरंभ किया जा रहा है जो साधारणतया विशिष्टतया नगरेतर और सुदूर स्थानों में निवास करते हैं।

समिति ने संस्था के समुचित वित्तीय समर्थन से संपूर्ण देश में सी पी ई रिसोर्स परसन्स बेस विकसित करने के लिए “प्रशिक्षक के लिए प्रशिक्षण” कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

लेखांकन, संपरीक्षा, प्रबंधन, अर्थशास्त्र और संबंध क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दृष्टि से, समिति ने ‘मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग रिसर्च’ नामक त्रैमासिक शोध पत्रिका प्रकाशित करना जारी रखा है और इसे विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। यह पत्रिका भारत में और विदेश से विशेषज्ञों के तकनीकी लेख प्राप्त कर प्रकाशित करती है।

समिति के निम्नलिखित अनुकूल बिन्दुओं पर भी कार्य कर रही है :-

- ◆ आधार सामग्री के निर्माण की प्रणाली को सुदृढ़ बनाना जिससे कि सदस्य ठीक समय पर उसे प्राप्त कर सकें। सी पी ई निदेशालय ने लेखकों से सी पी ई आधार सामग्री को तैयार करने के लिए हित की अभिव्यक्ति को आमंत्रित किया है जिससे सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में सी पी ई आधार सामग्री को प्रकाशित किया जा सके।
- ◆ उन क्षेत्रों में पोस्ट-अर्हता पाठ्यक्रम शुरू करने के बजाय संस्थान के सदस्यों के लिए सर्वोच्च विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों पर 100 घंटे /200 घंटे का माड्यूलर (प्रमापीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन।
- ◆ अपने संस्थान को या तो डीम्ड विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता देने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया।
- ◆ सदस्यों के अनवरत वृत्तिक शिक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ज्ञान पोर्टल (ज्ञान प्रवेश द्वार) को ऊंचा उठाया।

- ◆ संस्थान के निदेश निबंधन और विजन प्रलेख सहित संबद्धता में कार्यान्वयन योजना को पुनरीक्षित किया जिससे कि समिति के कृत्यों की आज्ञापक उपलब्धि में सह क्रियात्मकता प्राप्त हो सके ।
- ◆ संस्थान के सदस्यों के लिए अनुध्यात और भावी सुसंगतता के विषयों पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के सहयोग से कैम्पुल माड्यूलर कार्यक्रम संचालित किया ।
- ◆ सी पी ई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उद्योग में सदस्यों को समर्थ बनाने हेतु तथा अन्य वृत्तियों को संस्थान के ज्ञान और प्रज्ञा में भागीदारी का अवसर प्रदान करने के लिए संगठनात्मक लेबल सी पी ई कार्यक्रम आयोजित किया ।
- ◆ प्रादेशिक परिषद् मुख्यालयों और शाखाओं में सी पी ई कार्यक्रमों के सदस्यों की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए कार्ड रीडर्स लगाकर स्मार्ट कार्ड को शुरू किया ।

5.9 वृत्तिक विकास

वृत्तिक विकास समिति ने ऐसे नए/विद्यमान क्षेत्रों का पता लगाकर/अनुसरण करके, जहां सदस्यों की विशेषज्ञता का इस्तेमाल रचनात्मक और उपयोगी रीति से किया जा सके, सदस्यों को उपलब्ध वृत्तिक अवसर बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे । इस प्रक्रिया के भाग के रूप में इसने भारत में और भारत के बाहर दोनों के साथ विनिमयमक अधिकरणों, और वृत्ति की सी सेवाओं से प्रयोक्ता के लिए, विचार-विमर्श करना जारी रखा ।

वर्ष के दौरान समिति की प्रमुख उपलब्धियां/प्रयास नीचे वर्णित हैं :-

- ◆ विभिन्न राज्यों के मूल्य वर्धित कर अधिनियमों/प्ररूप मूल्य वर्धित कर अधिनियमों के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखाओं की आज्ञापक संपरीक्षा करने की अपेक्षा पर एक अध्ययन किया गया था और इस अध्ययन के आधार पर “मूल्य वर्धित कर आरंभ करने से उद्भूत वृत्तिक अवसर” नामक लेख संस्थान

की पत्रिका दि चार्टर्ड अकाउंटेंट के अप्रैल, 2003 के अंक में प्रकाशित किया गया था । चार्टर्ड अकाउंटेंट या व्यवहारियों द्वारा वृत्तिक संपरीक्षा के विचार को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश और अन्य सहित विभिन्न राज्यों से मूल्य वर्धित कर के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई । जिसके परिणामस्वरूप, अधिकांश ऐसे राज्यों को, जिन्हें उनके मूल्य वर्धित कर अधिनियमों के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया उन्हें बाद में ऐसे उपबंधों में सम्मिलित किया गया ।

- ◆ आई.एस.ए. अर्हित संपरीक्षकों के सेवाओं का उपयोग करने संबंधी विषय को इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया गया था और जिसके परिणामस्वरूप, अब अनेक बैंकों ने संस्थान से आई एस ए अर्हित सदस्यों के लिए अनुरोध करना आरंभ कर दिया है।
- ◆ प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की संपरीक्षा करने के लिए क्रमबद्ध रीति से पारिश्रमिक के मापमान पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट उपलब्ध कराने पर नबार्ड के साथ विचार-विमर्श करने के अनुसरण में, नबार्ड ने अब इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए एक कार्यकारी समूह स्थापित किया है जिसमें संस्थान भी एक सदस्य है ।
- ◆ मार्च, 2003 में कार्य की मात्रा और विस्तार में वृद्धि के कारण कानूनी संपरीक्षा के लिए संपरीक्षा पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया था और इस संबंध में, विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किए गए थे । यह प्रतीत होने की संभावना है कि प्रस्ताव के अनुकूल प्रत्युत्तर होगा ।
- ◆ समवर्ती संपरीक्षा की प्रक्रिया के व्यवस्थापन और समवर्ती संपरीक्षकों के नियोजन में समान प्रणाली स्थापित करने, समवर्ती संपरीक्षा के संबंध में सभी बैंकों के लिए समान मार्गदर्शन

सिद्धांत बनाने, समवर्ती संपरीक्षकों के पारिश्रमिक आदि संबंध विषय के बारे में इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ चर्चा की गई और अब इन सभी मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी समूह बना दिया गया है। समूह विभिन्न बैंकों के साथ-साथ स्वयं भारतीय बैंक एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

◆ केन्द्रीय सरकार के स्तर पर, बैंकिंग विभाग और बीमा विभाग से विचार-विमर्श किया गया जहां अनेक मुद्दों को निरन्तर समीक्षा के लिए पहचाना गया जो निम्नलिखित हैं :-

- राष्ट्रीय बैंक के निर्देशक बोर्ड पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अनिवार्य नाम निर्देशन के लिए उपबंध का जारी रखना।
- पब्लिक सैक्टर बैंकों की शाखाओं के लिए संपरीक्षकों के पैनल पर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को पब्लिक सैक्टर बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा में हिस्सा लेना।
- समवर्ती निरीक्षण, राजस्व और क्रेडिट मानीटरिंग संपरीक्षा आदि सहित बैंकों की सभी अपेक्षाओं के लिए एकल क्रमबद्ध ढांचों की संकल्पना का प्रस्तुत करना।
- गैर कारपोरेट उधार लेने वालों की संपरीक्षा के लिए मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना करना।
- बैंकों की आंतरिक/समवर्ती संपरीक्षा के लिए सूचना प्रणाली संपरीक्षा, कौशल को अधिमानता देने की आवश्यकता।
- बीमा कंपनियों की शाखाओं की समवर्ती संपरीक्षा के लिए अपेक्षाओं को अधिकथित करने की आवश्यकता।
- चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा निपटाए गए बीमा दावों की संपरीक्षा आरंभ करने पर विचार करना।
- बैंकों की वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने में आई सी ए आई द्वारा निभाई जा रही भूमिका।

◆ क्रेडिट बीमा स्थापित करने की समस्याओं और निक्षेप बीमा और क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन से संबंधित साधारण समस्याओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निरन्तर आधार पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से सहमत हुआ कि ये समस्याएं संपरीक्षा समितियों और बैंकों के स्वतंत्र निर्देशकों की जानकारी में लाई जानी चाहिए तथा इस बात से भी सहमत हुआ कि संस्थान द्वारा बैंकों को संपरीक्षा समितियों के अध्यक्षों और स्वतंत्र बैंक निर्देशकों के लिए आयोजित किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम में भाग लें। इसके अलावा दो अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया गया था - पहला "जोखिम आधारित प्रयवेक्षण" जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में परिपत्र जारी किए थे, और दूसरा प्रमुख मुद्दा जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया गया था वह था 'कपट' तथा इनका समाना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अन्य मुद्दे जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया गया था वे थे - (क) जोखिम आधारित प्रीमियम के परिकल्पना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को संस्थान की विशेषज्ञता प्रदान करना, और (ख) संबंधित अभिकरणों के माध्यम से आर आर बी और कोआपरेटिव बैंकों में अच्छी कारपोरेट शासन प्राप्त करने की पद्धतियां।

◆ भारतीय रिजर्व बैंक को यह अनुरोध करने के लिए अभ्यावेदन किया गया था कि वह सभी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करे जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सेवाओं में लगे असंपरीक्षित शाखाओं के प्रबंधक इस संबंध में आवश्यक प्रमाणक के प्रयोजनों के लिए कर संपरीक्षा करे। इस विषय को आर बी आई की पश्चात्वर्ती बैठक में उठाया गया और संगतता को हटाना इसके विचारधीन विषयों के अंतर्गत हैं।

◆ इसके परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब प्रोद्भव आधार के लिए नगरपालिका

लेखाओं के संपरिवर्तन का कार्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों को देने के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नगरपालिका संपरीक्षा का कार्य भी दे दिया है।

♦ आंध्र प्रदेश नगरपालिका संपरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा पहले ही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब यह विनिश्चय किया है कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उसके राजकोष की आंतरिक संपरीक्षा का कार्य भी कराएगा।

♦ वृत्तिक विकास समिति की केरल राज्य टास्क फोर्स ने “इम्प्रूवमेंट आफ अकाउंटिंग सिस्टम इन पंचायती राज इंस्टिट्यूशन्स” के संबंध में 6 नवम्बर, 2002 को राज्य प्लानिंग बोर्ड, केरल के उपाध्यक्ष और सदस्यों के साथ एक बैठक की थी। यह बैठक केरल के स्थानीय निकायों में वित्तीय प्रबंध प्रणाली में सुधार में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की पूर्व अंतर्ग्रस्तता हेतु कदम उठाने के लिए की गई थी।

♦ नियमित आधार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के भिन्न पदाधिकारियों के साथ सदस्यों के प्रत्यक्ष हित के अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई।

♦ निम्नलिखित क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सेवाओं के उपयोग के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को अभ्यावेदन भेजे गए और प्रस्तुतिकरण किया गया :-

- (i) - नकद से लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर लेखाओं का संपरिवर्तन।
 - बिक्री कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा।
 - सहकारी सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के नियोजन पर टिप्पण।
 - मूल्य वर्धित कर प्रणाली में अंतर्ग्रस्तता।
 - ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की संपरीक्षा।
 - फारेस्ट्री संबंधित गतिविधियों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका।

- खनन संबंधित गतिविधियों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका।
- ऐसे अन्य क्षेत्र जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

- (ii) - पर्यावरणीय लेखांकन और संपरीक्षा।
- (iii) - सरकारी अनुदान के उपयोग के लिए अंतिम-उपयोग प्रमाणन।
- (iv) - वित्तीय और कारपोरेट पुनर्संरचना।
- (v) - शैक्षिक संस्थानों की संपरीक्षा।
- (vi) - स्वास्थ्य कार्यक्रमों की संपरीक्षा।
- (vii) - सत्कार कर संगृहीत करने के लिए दायी विभिन्न इकाईयों की संपरीक्षा।
- (viii) - ऊर्जा संपरीक्षा।
- (ix) - आपदा प्रबंधन।

5.10 पीयर रिव्यू बोर्ड

2002 में संस्थान की परिषद् ने एक पीयर रिव्यू बोर्ड गठित किया जिसमें रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, नियमित आधार पर अनेक बैठकें की।

स्पष्टीकरणों, प्रक्रियाओं, प्रैक्टिस यूनिट द्वारा भरी जाने वाली प्रश्नावलियों, प्रैक्टिस यूनिट आदि द्वारा रखे जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पीयर रिव्यू प्रक्रिया का ब्यौरे वाला पीयर रिव्यू मैनुअल को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसे जारी कर दिया गया है। वर्ष के दौरान किए गए अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :-

- ♦ 1800 से अधिक आवेदकों से समीक्षक के रूप में पैनलित करने के लिए पत्र भेजे गए तथा 1600 आवेदकों को पैनलित करने के पत्र भेजा गए। समीक्षकों के पैनलित करने को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- ♦ 1000 से अधिक आवेदकों से समीक्षक के रूप में पैनलित करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की गई।

- ◆ बोर्ड, पीयर रिव्यू प्रक्रिया उसकै फायदों और संस्थान की पत्रिका में लेख देकर बोर्ड की बाध्यताओं के संबंध में सदस्यों को नियमित रूप से निवेश प्रदान कर रहा है।
- ◆ यह सुनिश्चित करने की वृष्टि से की पीयर रिव्यू विश्व की एक नंबर-क्वालिटी है, “पीयर रिव्यूयर्स के लिए प्रशिक्षण माड्यूल” संबंधी पुस्तिका पुनर्विलोकन कार्य देने से पूर्व समीक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम शहरवार अनेक पैनलित समीक्षकों पर निर्भर रहते हुए संपूर्ण देश में चलाए जाएंगे।
- ◆ बोर्ड द्वारा 18 जुलाई, 2003 को पहचाने गए उपाय कुशल व्यक्तियों के लिए, एक प्रभावी कार्यशाला आयोजित की गई थी। उपाय कुशल व्यक्ति बाद में उपरोक्त उल्लिखित कार्यक्रमों पर समीक्षकों को प्रशिक्षण देंगे।
- ◆ जागरूक कार्यक्रम/सेमिनार दिल्ली, इंदौर, बड़ोदा, गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद में आयोजित किए गए और सदस्यों और प्रेक्टिस यूनिटों के बीच पीयर रिव्यू के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए अनेक और कार्यक्रम/सेमिनार आयोजित करने की योजना है।
- ◆ बोर्ड समय अनुसूची के अनुसार, पीयर रिव्यू कार्य को आरंभ करने के लिए अपेक्षित ढाँचा तैयार कर रहा है जैसा “पीयर रिव्यू संबंधी कथन” द्वारा अनिवार्य किया गया है।
- ◆ बोर्ड पीयर रिव्यू प्रक्रिया के भाग के रूप में उच्चतर क्वालिटी मानकों की स्थापना के माध्यम से, व्यवसाय करने वाले अनेक ऐसे सदस्यों, जो समीक्षकों के रूप में कार्य करें, को सम्मिलित करके सामुदायिक क्वालिटी वृद्धि कार्यक्रम के रूप में विश्व की एक विलक्षण पीयर रिव्यू प्रणाली बनाने का प्रयास कर रहा है।

5.11 उद्योग में सदस्यों के लिए समिति

जब कि संस्थान के परिषद की विभिन्न समितियां ऐसे उद्योगों में से कैरियर अवसर चाहने

वाले सदस्यों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए या उन उद्योगों के निर्देश के साथ साक्षात्कृत कृत्यों को आरंभ करने इच्छुक सदस्यों के लिए उद्योग के विनिर्दिष्ट प्रकाशनों को विकसित करने का प्रयास कर रही है, इसलिए उद्योग संबंधी सदस्य समिति, कैपस साक्षात्कार संचालित करने पर उनका ध्यान आकर्षित करने के अलावा, उद्योग में सदस्यों की योग्यता और कौशल को अद्यतन और मजबूत बनाने के एकमात्र उद्देश्य से नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करती है।

5.11.1 कैपस साक्षात्कार

सितंबर, 1995 में शुरू कैपस साक्षात्कार, नियोजन संगठनों (पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी सम्मिलित हैं) और ऐसे नव अर्हित सदस्यों, जो उद्योग में अपना पोस्ट अर्हता कैरियर बनाने में रुचि रखते हों, दोनों से प्रचुर मात्रा में प्रतिक्रिया बराबर मिलती रही है। वर्ष के दौरान, नियोजकों के 99 दलों ने लगभग 6,311 युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बायोडाटा का परीशीलन किया। इस स्कीम की अच्छी प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित आई सी ए आई ने उद्योग में सदस्यों के लिए अपनी समिति के माध्यम से युवा सदस्यों के लिए अधिक विश्वास से साथ साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष जाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न साक्षात्कार केन्द्रों पर अभिनवीकरण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त “साक्षात्कार बोर्ड का सामना कैसे करें” और “साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का प्रश्न बैंक” की दो पुस्तिकाएं कैपस साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को उनके उपयोग के लिए भेजी गईं।

5.12 सूचना प्रौद्योगिकी

5.12.1 1 अप्रैल, 2002 और 31 मार्च, 2003 के बीच आई एस ए रजिस्ट्रीकरण की संख्या

यह अनुभूति की गई कि बढ़ते हुए अवसरों का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका

संपरीक्षा और लेखांकन में टेक्नोलॉजी आधारित विश्वस्त कौशल परम्परावादी दक्षता को परिवर्तित कर देता है इसलिए इसमें बड़ी संख्या में आई एस ए पाठ्यक्रम में भाग लेकर के अद्यतन ज्ञान चाहने वाले वृत्तिक सदस्यों को प्रेरित किया है । इसे निम्नलिखित द्वारा विस्तारित किया जाता है:-

31.3.2002 को आईएसए 2892
रजिस्ट्रीकरण की संख्या

1.4.2002 से 31.3.2003 के 6558
बीच आईएसएस रजिस्ट्रीकरण
संख्या

31.3.2003 को आईएसए 9450
रजिस्ट्रीकरण की कुल संख्या

1.4.2003 और 1.8.2003 2520
के बीच आईएसए रजिस्ट्रीकरण
की कुल संख्या

1.8.2003 को आईएसए 11970
रजिस्ट्रीकरण की कुल संख्या

5.12.2 1 अप्रैल, 2002 और 31 मार्च 2003 के बीच निर्धारण परीक्षा की उत्तीर्ण प्रास्थिति पर आईएसए

आईएसए निर्धारण परीक्षण प्रत्येक में संचालित किए जा रहे हैं । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण किया,

31.3.2002 को आईएसए 260
निर्धारण परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों
की संख्या

1.4.2002 और 31.3.2003 के 1717
बीच आईएसए निर्धारण परीक्षा
उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों
की संख्या

31.3.2002 को आईएसए 1977
निर्धारण परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों
की संख्या

5.12.3 आईएसए रिपोर्ट व्यक्ति/फैकल्टी का अधिवेशन

आईएसए रिपोर्ट व्यक्ति/फैकल्टी का अधिवेशन 8 और 9 जुलाई, 2003 को चेन्नई में हुआ था जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया है और अनुकूल कार्रवाई प्लान तैयार किया गया:-

- ◆ आईएसए पाठ्यक्रम सामग्री का पुनरीक्षण
- ◆ प्रश्न बैंक
- ◆ नई फैकल्टी की मानीटरिंग
- ◆ सूचना प्रणाली विशेषज्ञ संबंधी नए पाठ्यक्रम के लिए नियत कार्य सामर्थ्य ।

5.12.4 सूचना प्रौद्योगिकी हारमोनी न्यूजलेटर, प्रौद्योगिक पर संस्थान की राय :

जनवरी, 2003 से प्रारंभ सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी हारमोनी न्यूजलेटर, 2003 आरंभ किए हैं जो अंतर्वस्तु, डिजाइन और विषयवस्तु संबंधी विवेचन के लिए उच्चतर रूप से अनुकूल बनाए भी हैं । मुद्रित पाठ तिमाही में एक बार प्रकाशित किए जा रहे हैं और शेष महीनों में न्यूजलेटर ई-मेल के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं । जनवरी, 2003 के अंक के पहले मुद्रित पाठ में ई-कामर्स अप्रैल, 2003 के अंक के दूसरे पाठ में कोर-बैंकिंग पर बल दिया गया है । विषय-वस्तु और समसामयिक कवरेज के अलावा अन्य प्रमुख विशेषताओं में सरकार कारबार, प्रौद्योगिकी संस्थानों के नेताओं के साक्षात्कार होते हैं ।

5.12.5 ई-लर्निंग के माध्यम से आन लाइन परीक्षण और अनुसंधानात्मक आन- लाइन अध्ययन सामग्री (आर ओ एस एम)

पदाभिहित प्रबंधकों के माध्यम से पोर्टल सेवा, टिवन सेवाएं, अर्थात् आन-लाइन प्रेक्टिस परीक्षण और अनुसंधानात्मक अध्ययन सामग्री आई एस ए के भाग लेने वालों के फायदे के

लिए सात दिन के सप्ताह में 24 घंटे उपलब्ध रहती है।

5.12.6 17 मई, 2003 को शनिवार इंपोसिस कैम्पस में हैंड्स आन टेक्नोलाजी एक्सपोजर आफ फिनासिल एप्लीकेशन प्रोग्राम :

17 मई, 2003 को 30 आई एस ए उत्तीर्ण सदस्यों ने इंपोसिस कैम्पस बंगलौर में हैंड्स आन टेक्नोलाजी एक्सपोजर आफ फिनासिल एप्लीकेशन प्रोग्राम में भाग किया। आई एस ए उत्तीर्ण ऐसे सदस्यों, जो सूचना प्रौद्योगिक समिति की पहल के लिए रिसोर्स व्यक्तियों के रूप में सेवा करने का विचार रखते थे/से वेबसाइट के माध्यम से आवेदन मांगे गए थे/पहले 30 आवेदकों का, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयन किया गया था। सदस्यों को फिनासिल में संपरीक्षा साधनों को हैंड्स-आन-एक्सपोजर करने का फायदा हुआ था।

5.12.7 भारतीय बैंकर्स संस्थान के साथ संयुक्त उद्यम

आई सी ए आई द्वारा संचालित आई एस ए पाठ्यक्रम की सफलता से नए पाठ्यक्रम सी ई आई एस बी (सूचना प्रणाली, प्रतिभूति बैंकिंग में प्रमाणपत्र) के लिए अध्ययन सामग्री और प्रश्न बैंक विकसित करने में आई सी ए आई से समर्थन लेकर इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकर्स, मुम्बई जैसे प्रमुख संस्थान की स्थापना हुई थी। अध्ययन सामग्री तैयार करने और साथ ही निम्नलिखित क्षेत्रों में रिसोर्स व्यक्ति प्रदान करने के लिए आई आई बी के साथ पहले ही समझौता हो गया था :-

- ◆ बैंको में प्रौद्योगिकी
- ◆ प्रौद्योगिकी - प्रणाली, विकास, प्रक्रिया, कार्यान्वयन
- ◆ सिक्यूरिटी और नियंत्रण, बैंकिंग में मानक
- ◆ कारबार में निरन्तरता
- ◆ विधिक ढांचा

◆ सिक्यूरिटी नीतियां, प्रक्रिया और नियंत्रण
- II

- ◆ आई एस पुनर्विलोकन - विधितंत्र और उपगमन।

5.12.8 श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के साथ आई एस ए संयुक्त उद्यम कार्यक्रम

श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अनुरोध पर, आई सी ए आई द्वारा विकसित आई एस ए वृत्तिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 27 जनवरी, 2003 को श्रीलंका में शुरू किया गया था। आई सी ए आई और आई सी ए एस एल के बीच हुए करार के अनुसार, आई सी ए आई अध्ययन सामग्री, फैंकल्टी और परीक्षा सहयोग प्रदान करेगा।

आई सी ए आई द्वारा प्रदत्त फैंकल्टी में आई सी ए एस एल के लिए 12 वृत्तिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए जिनमें भाग लेने वालों की अच्छी उपस्थिति थी। पहले बैच के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, श्रीलंका में भाग लेने वालों के लिए दूसरे बैच संचालित करने का पुनः अनुरोध किया गया है।

5.13 शुरू किए गए सार्वजनिक संबंध क्रियाकलाप

यह वर्ष इस बात का साक्ष्य है कि लेखांकन वृत्तिक की भूमिका, चुनौतियों और मुद्दों पर विश्वव्यापी सार्वजनिक वाक-विवाद हुआ जिनमें मीडिया का ध्यान अधिकतर गया। विशिष्टतया संस्थान के दृष्टिकोण, भारत में लेखांकन वृत्तिक की सुदृढ़ता और अनुध्यात मुद्दों पर संस्थान के परिप्रेक्ष्य, गलतफहमी को दूर करने और वृत्तिकों की चिन्ता के बारे में सकारात्मक रणनीति अपनाई गई थी।

- ◆ मुख्यालय, प्रादेशिक कार्यालयों तथा देश के विभिन्न अन्य शहरों में पहल करने/की जाने वाली पहल, नीतियां और कार्यक्रम तथा वृत्तिक से संबंधित मुद्दों का उत्तर देने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित प्रेस सम्मेलन किए गए। इसमें ऐसे मुद्दों पर, जो

वृत्ति के सामने होते हैं, प्रसिद्ध पत्रकारों के साथ और टी वी चैनलों पर अध्यक्ष की बैठक भी सम्मिलित है।

- ◆ पत्रकारों, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संसद नेता, सरकारी पदाधिकारीगण, दृष्टिकोण रखने वाले विनियामकों के साथ प्रभावकारी विचार विमर्श किए गए तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वृत्ति से संबंधित मुद्दों पर संस्थान द्वारा पहल की जा रही है।
- ◆ संस्थान और सदस्यों के बीच उनके पुनर्निवेशन के लिए संचार व्यवस्था विकसित करने की दृष्टि से, संस्थान उसके प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में वृत्तिक से संबंधित सार्वजनिक वाद-विवाद में अनुध्यात मुद्दों पर जोर दिया गया।
- ◆ संपूर्ण विश्व में लेखांकन निकायों के साथ संपर्क स्थापित किया गया जिसमें वाद-विवाद के संदर्भ में भारत में लेखांकन वृत्ति को सुदृढ़ बनाना सम्मिलित है, जिसका यू.एस. में कुछ कंपनियों के बंद हो जाने के पश्चात् अनुसरण किया गया।
- ◆ राज्य, जिला और शहर स्तर पर संस्थान के समाचारों के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रादेशिक कार्यालयों में सार्वजनिक संबंध के प्रयोजनों के लिए नोडल अधिकारियों को पदाभिहित किया गया।
- ◆ राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों में प्रेस के साथ संरचनात्मक लेखों तथा प्रभावी बैठकों के माध्यम से सी.ए. पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया।
- ◆ संपूर्ण देश में संस्थान के समाचारों के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए प्रेस डाटाबेस का निर्माण किया गया।
- ◆ सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों के विकास के लिए सक्रिय पहल की गई, वृत्तिक की सकारात्मक पहचान बनाई गई, सी.ए. छात्रों के लिए कैरियर संभावनाओं और चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं को

विज्ञापन के माध्यम से विशिष्टता प्रदान की गई जैसा कि प्रमुख समाचारपत्रों और पत्रिकाओं जिसमें खालिज़ टाइम्स आफ़ दुबई भी सम्मिलित है।

- ◆ संस्थान की प्रतिकृति के संनिर्माण का प्रस्ताव किया गया और टी.वी. चैनलों पर एपिसोड्स के माध्यम से साधारण जागरूकता पैदा की गई।
- ◆ संस्थान के कार्यालय में तथा इंटरनेट के माध्यम से सदस्यों और छात्रों के प्रत्युत्तर की क्वालिटी को सुदृढ़ बनाया गया तथा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाया गया और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए पत्रिकाओं और छात्रों के समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्रदान गई।
- ◆ आई सी ए आई पत्रिका तिमाही प्रकाशित की जा रही है।
- ◆ संस्थान के वेबसाइट को फेस-लिफ्ट (मुख उपचार या बाह्यरूप संस्कार) दिया गया और इसे अधिक ज्ञानवर्धक और अनुकूल रूप से उपयोगी बनाया गया। फोटो गैलरी और महत्वपूर्ण भाषणों के लिए नया अनुभाग शुरू किया गया।
- ◆ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठकें की गई।
- ◆ भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के विभिन्न सरकारी विभागों के सचिवों के साथ बैठकें की गई।

5.13.1 मीडिया विषय

(i) जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में 15वां अखिल भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय श्री जसवंत सिंह, संघ के वित्त मंत्री द्वारा किया गया। मंत्रियों और भारत सरकार के पूर्व मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सुविख्यात विदेशी व्यक्तियों में, जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया, इंटरनेशनल फेडरेशन आफ़ अकाउंटेंट (आई एफ़ ए सी) के अध्यक्ष, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स

- बोर्ड (आई ए एस बी) के अध्यक्ष, चीन के वृत्तिक निकायों के प्रमुख और सार्क देश सम्मिलित हैं। माननीय श्री शरद यादव, उपभोक्ता मामलों के संघ मंत्री मुख्य अतिथि थे और माननीय श्री सुरेश प्रभु, भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री को सम्मेलन के विदाई भाषण पर अतिथि का सम्मान दिया गया था।
- (ii) माननीय श्री भैरों सिंह शेखावत, भारत के उपराष्ट्रपति ने 'डब्ल्यू टी ओ - रोड अहेड' - संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने वाले दस्तावेज और डब्ल्यू टी ओ की व्यवस्था पर संभावित रोड मैप जारी किया। श्री राजीव प्रताप रूडी, संघ के तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री और माननीय श्री विजय गोयल, संघ में तत्कालीन श्रम और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री को मुख्य अतिथि से सम्मानित किया गया।
- (iii) सभी प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं को सलाह दी गई कि वे 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के रूप में मनाएं।
- (iv) श्री विमल जालान, तत्कालीन गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई दिल्ली में सी ए दिवस के स्मरणोत्सव पर विशेष संबोधन का आयोजन किया गया।
- (v) श्री विनोद ढाल, भूतपूर्व सचिव, कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीयर रिव्यू मैनुअल जारी किया गया।
- (vi) संस्थान के 53वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन संघ के खान राज्य मंत्री, माननीय श्री रमेश बियास ने किया।
- (vii) संस्थान द्वारा पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के निदेशकों (वित्त) गोल मेज की बैठक आयोजित की गई जिसका उद्घाटन माननीय श्री वी.एन.कौल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के पदाधिकारियों के अतिरिक्त 50 पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के निदेशकों (वित्त) ने भी इसमें भाग लिया।
- (viii) भारतीय बीमा कंपनियों और बीमा मध्यवर्तियों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और मुख्य वित्त अधिकारियों की बैठक जून, 2003 को हैदराबाद में आयोजित की गई थी। श्री एन. रंगाचारी, तत्कालीन अध्यक्ष, आई आर डी ए ने बैठक को संबोधित किया।
- (ix) आई सी ए आई लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा प्रोद्भवन आधार पर तैयार की गई दिल्ली नगर निगम की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को औपचारिक रूप से दिल्ली नगर निगम को सौंपी गई। इस समारोह के मुख्य अतिथि, दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय श्री विजय कपूर थे। इसके अलावा, लेखाओं का पुनरीक्षित चार्ट और साधारण पाठकों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई व्यापक वित्तीय रिपोर्ट की गाइड भी जारी कर दी गई थी।
- (x) आई सी ए श्रीलंका के साथ संयुक्त सम्मेलन को बंगलौर में आयोजित किया गया था। श्रीलंका के वाणिज्य मंत्री मुख्य अतिथि थे और विप्रो के प्रमुख श्री आजिम प्रेमजी ने उद्घाटन भाषण दिया। श्रीलंका संस्थान के साथ पहला संयुक्त सम्मलेन अक्टूबर, 2002 में कोलम्बो में आयोजित किया गया था।
- (xi) अधिकांश लोगों के लिए विभिन्न शहरों में जनता जागरूकता और विनिवेश शिक्षा कार्यक्रम किया गया और विनिवेशकर्ताओं को स्टॉक मार्किट में उतार-चढ़ाव और उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में जानकारी दी गई।
- (xii) नोएडा स्थित संस्थान के नए भवन की भूमि पूजा की गई।
- (xiii) प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक संबंध नीति के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।
- (xiv) संस्थान की सार्वजनिक संबंध नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

5.13.2 अंतरराष्ट्रीय

- (i) जनवरी, 2003 में नई दिल्ली में साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (एस ए एफ ए) की सभा बैठक का आयोजन किया गया।
- (ii) जनवरी, 2003 में कोलम्बो, श्रीलंका में आई सी ए श्रीलंका आन सिस्टम आडिट के साथ संयुक्त कार्यक्रम आरंभ किया गया।
- (iii) श्रीलंका के साथ छात्र एक्सचेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेपाल के साथ भी ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित करने का विचार किया जा रहा है।
- (iv) ऐसे अन्य देशों में संस्थान की बैठकें की गई जिसके साथ पारस्परिक सहयोग और अर्हता की मान्यता के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- (v) सी ए पी ए कार्यपालक समिति की बैठक नवम्बर, 2003 में नई दिल्ली में आयोजित की जानी है। सी ए पी ए और एस ए एफ ए की बैठकों के साथ-साथ आई एफ ए सी बोर्ड की बैठक मार्च, 2004 में करने का विनिश्चय किया गया है।

5.14 व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन

व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति ने, 2001 में इसके प्रारंभ से, संकल्पनावाद, सूत्रीकरण, बातचीत, कार्यान्वयन, व्यापार से संबंधित प्रतितोष विधि जिसमें विशिष्ट रूप से माल और सेवाओं में व्यापार भी सम्मिलित है, तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली, जिसमें साधारणतया राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय रूप से दोनों विश्व व्यापार संगठन प्रणाली भी सम्मिलित है, से संबंधित सभी विषयों में सुविज्ञता और प्राधिकार स्थापित करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए उसके लक्ष्य को प्राप्त करने और संस्थान की सदस्यता के बीच इन विषयों में ऐसे साधनों और युक्तियों के माध्यम से, जो अधिक प्रभावकारी समझे जाते हों, विशेषज्ञता के आधार को सृजित और बढ़ाने का कठिन प्रयास किया जिससे कि

इस संबंध में निश्चित और अनिश्चित राष्ट्रीय आकांक्षाओं, चिन्ता और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

वर्ष के दौरान, समिति ने संस्थानों की पहचान करने और विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न करार पर व्यापक सिफारिशें करने के लिए तथा व्यापक सिफारिशें और सूचनापत्र को प्रकाशित करके ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे।

संस्थानों की पहचान करने वाले “मार्ग आगे है” नामक दस्तावेज और विश्व व्यापार संगठन प्रणाली पर संभावित मार्ग व्यवस्था संबंधी दस्तावेज को समिति द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऐसे वाद-विवादों और विचार-विमर्श, जो 2001 में समिति द्वारा आयोजित “विश्व व्यापार संगठन प्रणाली में विकासशील राष्ट्रों की चिन्ता” संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जो विषय था, से अद्भूत सिफारिशों वाले दस्तावेज को भी समिति द्वारा इसमें शामिल किया गया था। विकासशील देशों के संस्थानों की सम्मिलित करारवार और नियमवार पहचान का विस्तार किया गया तथा ऐसे जटिल मुद्दों का संभावित मार्ग आगे है, उपचारों और व्यावहारिक समाधान करने का सुझाव दिया गया जिन्हें विभिन्न देशों के विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकट किया गया।

वर्ष के दौरान, समिति ने भारत के उप-राष्ट्रपति माननीय श्री भैरों सिंह शेखावत के शुभ हाथों से “विश्व व्यापार संगठन - मार्ग आगे है” दस्तावेज को प्रकाशित करने के लिए 22 फरवरी, 2003 को नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। संघ के तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री माननीय श्री राजीव प्रताप रुड़ी ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई जिन्होंने “डब्ल्यू टी ओ - भारत का परिप्रेक्ष्य” पर समारोह को संबोधित किया।

संघ के तत्कालीन श्रम और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री माननीय श्री विजय गोयल ने भी “श्रम सुधार और डब्ल्यू टी ओ - भारतीय परिप्रेक्ष्य” पर सभा को संबोधित किया। समारोह में संसद सदस्यों, भूतपूर्व मंत्रियों, सरकारी

पदाधिकारियों, आई सी ए आई के केन्द्रीय परिषद् और प्रादेशिक परिषदों के सदस्यों, आई सी ए आई के सदस्यों तथा अन्य वृत्तिकों, मीडिया और अन्य उच्चाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

- ◆ समिति, सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों के फायदे के लिए क्षेत्र में सुसंगत आधुनिक तकनीकी प्रदान करने हेतु “डब्ल्यू टी ओ अन्वेषक - डब्ल्यू टी ओ विलय संबंधी आधुनिक तकनीकी” नामक प्रकाशन को नियमित रूप से उद्बोधन प्रचार देने के लिए प्रकाशित करती आ रही है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति ने प्रकाशन के आठ अंक प्रकाशित किए। समिति ने इन्हें संस्थान की वेबसाइट पर होस्ट करना आरंभ कर दिया है। अन्य बातों के साथ, समिति ने निम्नलिखित विषयों पर ज्ञान के सक्रिय कैरियर और आधुनिक लेखों को मुद्रित कर डब्ल्यू टी ओ के क्षेत्र में वृत्तिक और अन्य संबंधित व्यक्तियों के हित/चिन्ता के विषय आधुनिक तकनीकी/वृत्तिक के रूप में कार्य करना जारी रखा है :-

- ◆ डब्ल्यू टी ओ - दोहा से कुनकुन
- ◆ डब्ल्यू टी ओ प्रणाली - छोटे और मझोले उद्यमों पर प्रभाव
- ◆ क्या बहुपक्षीय प्रतियोगिता करार बांछनी है
- ◆ सार्वभौमिक प्रयास - चाइनीज अनुभव
- ◆ जी ए टी एस बातचीत पर निर्बाध रूप से पूछे गए प्रश्न
- ◆ प्रतिपाटन और प्रतिसहायिकी उपायों पर निर्बाध रूप से पूछे गए प्रश्न
- ◆ निम्नलिखित विषयों पर वर्तमान आधुनिक डब्ल्यू टी ओ बातचीत
 - कृषि क्षेत्र
 - प्रतिपाटन करार
 - ट्रिप्स और लोक स्वास्थ्य
 - सेवा क्षेत्र

- विशेष और वैमिन्य निरूपण उपबंध
- कार्यान्वयन मुद्दे
- विवाद समाधान
- औद्योगिक टैरिफ

- ◆ भारत द्वारा प्रतिपाटन संबंधी कार्यवाहियां
- ◆ प्रतिपाटन अनवेषण संबंधी डब्ल्यू टी ओ सचिवालय रिपोर्ट
- ◆ प्रमुख मामलों पर डब्ल्यू टी ओ विवाद समाधान निकाय के निष्कर्ष/निर्णय
- ◆ डब्ल्यू.टी.ओ. सचिवालय द्वारा व्यापार नीति पुनर्विचार
- ◆ अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिप्रेक्ष्य में विकास पर वार्षिक रिपोर्ट

इसके अतिरिक्त, “अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन” में प्रारंभ किए जाने वाला प्रस्तावित पोस्ट अर्हता पाठ्यक्रम अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यू टी ओ से संबंधित सेवाओं के क्षेत्रों में समर्पित प्रेक्टिस को विकसित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञ कौशल के साथ सदस्यों का ज्ञानवर्धन करने के लिए इच्छुक है।

समिति ने पाठ्यक्रम को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए अन्य पद्धतियों को अन्तिम रूप देने का कार्य आरम्भ कर दिया है। समिति, अपने क्रियाकलापों में सहायता के लिए विशेषज्ञ/उपाय कुशल व्यक्तियों के पैनल को अंतिम रूप दे रही है।

5.15 बीमा संबंधी

बीमा संबंधी समिति, को 2001 में गठित किया गया था जिससे कि संस्थान के सदस्यों के लिए बीमा क्षेत्र में वृत्तिक अवसरों की पहचान करने, उनको बीमा उद्योग विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम संचालित करने, सेमिनारों, कार्यशालायों आदि के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा सके और क्षेत्र के प्रचुरोद्भव के लिए बीमा कंपनियों, बीमा मध्यवर्तियों, बीमा विनियमक और बीमा प्राधिकरण, सरकार, आदि जैसे

उद्योग संघटकों को प्रभावित किया जा सके। वर्ष के दौरान, समिति ने अपने उल्लिखित उद्देश्यों, विशिष्टतया बीमा क्षेत्र में पोस्ट अर्हता पाठ्यक्रम प्रारंभ की नीति बनाने के लिए अधिक ध्यान दिया।

5.15.1 बीमा और जोखिम प्रबंध में पोस्ट अर्हता पाठ्यक्रम का आरंभ किया जाना

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने और भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, 19 अप्रैल, 2003 को चेन्नई में बीमा और जोखिम प्रबंध (डी आई आर एम) में पोस्ट अर्हता पाठ्यक्रम शुरू किया गया। पाठ्यक्रम में मौलिक सिद्धांत और प्रेक्टिस के प्रारंभिक ज्ञान को सम्मिलित किया गया है जो बीमा के प्रासंगिक है और जीवन और साधारण बीमा खंडों, उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं, जोखिम प्रबंध के संघटक और इसमें सार्वजनिक प्रकटीकरण, वैकल्पिक बाहरी स्रोतों की खोज में उत्पाद सूत्रीकरण, मार्केटिंग, वितरण, पुनर्बीमा आदि जैसे बीमा कारबार संस्थापित परिवर्तित क्षेत्रों में कारगर चलाने की योजना को भी सम्मिलित किया गया है। डी आई आर एम पाठ्यक्रम में प्रेक्टिस कर रहे सदस्यों और ऐसे व्यक्तियों, और जो अन्यथा बीमा कारबार गतिविधियों के मूल, तकनीकी और व्यावहारिक पहलू के सुबोध परिज्ञान के उपबंध पर संकेन्द्रण करके विश्लेषणात्मक के अध्ययन के माध्यम से नियोजित है, के बीमा उद्योग द्वारा अपेक्षित वृत्तिक ज्ञान की शिक्षा देने के लिए परिकल्पित है।

उद्योग विनिर्दिष्ट विशेषज्ञता प्राप्त पाठ्यक्रम होने के नाते, पाठ्यक्रम में अनुमान के अनुसार प्रवेश किया गया। जुलाई, 2003 में 1405 सदस्यों ने पाठ्यक्रम के लिए नामांकन किया। अभ्यर्थियों की क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नलिखित है: -

पश्चिमी	194
दक्षिणी	722
पूर्वी	92
मध्य	193

उत्तरी	204
कुल	1405

तकनीकी परीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, अभ्यर्थियों को अपेक्षित ज्ञान संघटक और कौशल तथा प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम के रूप में शिक्षा प्रदान की जाएगी जिससे कि वे बीमा क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए इसे वृत्ति से साथ जोड़ सकें।

समिति अभ्यर्थियों के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण के और अधिक समसामयिक पद्धतियों को खोजने और उन्हें मान्यता देने पर विचार कर रही है जो विषयों को प्रभावी रूप से ग्रहण करने को सुकर बनाएगा।

5.15.2 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए माड्यूलर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

बीमा संबंधी सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए माड्यूलर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का भी समिति विचार कर रही है जिसके लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने माड्यूलर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संकल्पना पर अपना ध्यान केन्द्रित किया हुआ है और आने वाले समय में वह संकल्पना पाठ्यक्रम के साथ होगी। पाठ्यक्रम में बीमा सर्वेक्षण विभागों के व्यावहारिक और तकनीकी पहलुओं से संबंधित वृत्तिक अध्ययन और प्रशिक्षण सम्मिलित हैं जिसके लिए इस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सेवाएं दे सकते हैं। पाठ्यक्रम, संस्थान के सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसर पैदा करेगा और सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम को पूरा करने पर सदस्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सर्वेक्षक और हानि निर्धारिक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

5.15.3 सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, आदि

समिति ने अपने प्रकट उद्देश्यों के रूप में सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से बीमा से संबंधित ज्ञान का प्रसार किया है। उपरोक्त उद्देश्य के अनुसरण में, संस्थान द्वारा

संचालित ऐसे कार्यक्रमों में समिति के सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और संस्थान के सदस्यों के बीच बीमा क्षेत्र विनिर्दिष्ट ज्ञान का प्रसार-प्रचार करते हैं। प्रसार-प्रचार का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि बीमा और जोखिम प्रबंध में पोस्ट अर्हता पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों को बीमा उद्योग के देशी और विदेशी क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए।

समिति ने जून, 2003 के महीने में बीमा क्षेत्र की एक बैठक भी आयोजित की जिसमें भारतीय बीमा कंपनियों और बीमा मध्यवर्तियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों, अर्थात्, बीमा ब्रोकरों और तीसरे पक्षकार प्रशासकों ने भाग लिया। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अध्यक्ष और सदस्यों ने साधारणतया परिवर्तित बीमा और जोखिम प्रबंध से संबंधित विषयों पर बीमा क्षेत्र, कारपोरेट शासन मुद्दे और संपरीक्षा समिति, बीमा क्षेत्र में प्रबंध और विशिष्टतया बीमा क्षेत्र में सुधार संबंधी साक्षेप महत्व की अनुकूलता पर भाग लिया।

6. अंतरराष्ट्रीय पहल

- संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय रूप से वृत्ति की अच्छी प्रतिभा को बनाए रखने में एक जोरदार पहल जारी रखी है। वर्ष के दौरान आई सी ए आई द्वारा की गई पहल विदेश में लेखांकन निकायों द्वारा अपनी अर्हता की मान्यता के लिए वृत्तिक समकक्षता स्थापित करने, साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (एस ए एफ ए), कन्फेडरेसन आफ एशियन एंड पेसिफिक अकाउंटेंट (सी ए पी ए) और इंटरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (आई एफ ए सी) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वृत्ति को बेहतर प्रतिनिधित्व प्रदान करने और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय को एक असमान कार्यकरण महौल में वृत्तिक सेवाएं देने के लिए सशक्त बनाने की दृष्टि से, उसके भारत से बाहर के चैप्टर के माध्यम से, इसके विदेशी सदस्यों के साथ संस्थान को अंतर्वर्धन सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया है।

- संस्थान ने अकाउंटेंसी वृत्ति को अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सक्रिय भागीदारी और

महत्वपूर्ण तकनीकी योगदान देना जारी रखा है। वर्ष के दौरान श्री अशोक चन्दक, भूतपूर्व अध्यक्ष को एस ए एफ ए के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। संस्थान को नवम्बर, 2002 में हांगकांग XVI वर्ल्ड कांग्रेस आफ अकाउंटेंट्स और जनवरी, 2003 में पेरिस में इंटरनेशनल आडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड-नेशनल स्टैंडर्ड सैटर्स आफ दि आई एफ ए सी की बैठक के लिए आमंत्रण प्राप्त हुए हैं। सितंबर, 2003 को वर्ल्ड स्टैंडर्ड सैटर्स के साथ होने वाली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड की बैठक के लिए भी आमंत्रण प्राप्त हुए हैं।

- पोस्ट-इनरान परिप्रेक्ष्य में, संस्थान एस ए एफ ए और सी ए पी ए मंचों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भारतीय लेखाकर्म वृत्ति की उच्च क्वालिटी को स्थापित करने में समर्थ था। वृत्ति के संपूर्ण विकास के लिए संस्थान द्वारा की गई पहल को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई थी।

- वर्ष के दौरान, संस्थान ने निम्नलिखित उपलब्धि के लिए अपनी अर्हता को मान्यता देने के लिए विदेश लेखांकन निकायों के साथ प्रभावशाली रीति से बातचीत की :-

- संस्था से सदस्यों को सर्टिफाइड जर्नल अकाउंटेंट एसोशिएसन आफ कनाडा (सी.जी.ए.) द्वारा एडवांस स्टैडिंग प्रास्थिति प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप, संस्थान के सदस्यों को कनाडा की सी.जी.ए. परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पहले के 16 प्रश्न पत्र के बजाय केवल पांच प्रश्नपत्र ही देने होंगे।

- इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आई सी ए ई डब्ल्यू) ने संस्थान के सदस्यों को उनकी परीक्षा के वृत्तिक प्रक्रम में छह में से पांच में छूट प्रदान की है। आई सी ए ई डब्ल्यू द्वारा छूट के लिए आई सी ए आई के छात्रों की प्रशिक्षण विरचना को मान्यता देने की प्रक्रिया चालू है।

- इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ न्यूजीलैंड (आई सी ए एन जेड) ने आई सी ए

आई अर्हता का पूरा पुनर्विलोकन आरंभ कर दिया है और संस्थान के सदस्यों को उनकी परीक्षाओं में छूट देने के लिए और आगे लाया जा रहा है।

- संस्थान के ऐसे सदस्य जो अच्छी स्थिति में हैं और यूगांडा में प्रवास करना चाहते हैं, इंस्टिट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स आफ यूगांडा (आई सी पी ए यू) के सदस्य बन सकेंगे।

- जाम्बिया इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी यह सूचित किया है कि आई सी ए आई अर्हता के धारकों को “लाइसंसिएट्स” के रूप में मान्यता दे दी जाएगी।

- दि इंटरनेशनल क्वालिटी एप्रैज़ल बोर्ड (एन ए एस बी ए) आफ दि यू.एस.ए. संस्थान की अर्हता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में था। उसका मूल्यांकन उसके अग्रिम प्रक्रम पर है और औपचारिक विनिश्चय शीघ्र ही लिए जाने की आशा है।

- दि कैनेडियन इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सी आ सी ए) और एन ए एस बी ए ने संयुक्त रूप से आई सी ए आई की अर्हता का मूल्यांकन करने का विनिश्चय किया है।

- संस्थान ने अन्य विदेशी लेखाकर्म निकायों के साथ संस्थान की अर्हता को मान्यता देने के मामलों को भी आगे बढ़ाना जारी रखा है।

- रूस, इजराइल, टर्की और इजिप्ट में लेखाकर्म निकायों के साथ समझौता ज्ञापन तैयार किया गया था।

◆ संस्थान निरन्तर साधारणतया सेवा क्षेत्र विशिष्टतया लेखाकर्म वृत्ति संबंधी जी ए टी एस की विविक्षाओं पर सरकार को सक्रिय सलाह दे रहा है। संस्थान ने अनुरोध पर बातचीत करने के लिए द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया और मई, 2003 को जिनेवा में सेवाओं में व्यापार के लिए हुए परिषद के विशेष सत्र के साथ-साथ प्रस्ताव रखा।

◆ लेखाकर्म वृत्ति में लघु और मझौले व्यावसायियों (एस.एम.पी) की आवश्यकताओं से संबंधित चिन्ता को आई एफ ए सी के एस एम पी टास्क फोर्स (कार्यबल) और इन्टर

गर्वमैन्टल वर्किंग ग्रुप आफ एक्सपर्ट्स आफ इंटरनेशनल स्टैन्डर्ड्स आफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग (आई एस ए आर) आन एस एम इज़ के समक्ष व्यक्ति की तथा संस्थान ने एस एम ई के लिए लेखांकन अच्छी प्रैक्टिस का सुझाव देने में सक्रिय भूमिका निभाई।

◆ संस्थान ने आई एफ ए सी के तत्वावधान में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी मंच बनाने का भी प्रस्ताव बनाया।

◆ दक्षिण एशिया क्षेत्र में लेखांकन निकायों के लिए स्थानीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और छात्र एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित किए थे। संस्था द्वारा इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ श्रीलंका और इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल के सहयोग से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

◆ संस्थान ने इंडोनिशिया में एक चैप्टर खोला है और विशिष्टतया कनाडा तथा यू.एस.ए. में और अधिक चैप्टर खोलने की संभाव्यता का पता लगाया। संस्थान ने सहभागिता को बढ़ावा देने के उनके क्रियाकलापों के हित के लिए प्रतिकूल उपाय करे।

◆ जनवरी, 2002 में सी आई सी पी ए (चीन) और आई सी ए आई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे जनवरी, 2003 में दो संस्थानों के बीच हुए समझौता-ज्ञापन द्वारा और सुदृढ़ बनाया गया था। इसके अनुसरण में, चाइनीज संस्थान के साथ उनके द्वारा विहित लेखांकन और संपरीक्षा मानकों के निर्वचन, प्रयोज्यता और प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी प्रलेखन का आदान-प्रदान किया गया। तथापि, मेजबान देश में सार्स की समस्या के कारण भारतीय शिष्टमंडल अपना दौरा नहीं कर सका।

◆ आई सी ए आई शिष्टमंडल यू ए ई के उच्चतर शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री एच ई शेख नहयान से तब मिला जब वे यू ए ई के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान को स्थापित करने के लिए संस्थान के साथ तकनीकी सहयोग करार पर प्रवेश करके यू ए ई सरकार

की संभावना पर विचार प्रवेश करने लिए अपनी सहमति व्यक्त कर रहे थे।

- ◆ पहली एस ए एफ ए टैली कांफ्रेंसिंग अप्रैल, 2003 में संस्थान द्वारा आयोजित की गई थी।
- ◆ सी ए पी ए कार्यपालक समिति की बैठक नवम्बर, 2003 में भारत में होनी है।
- ◆ संस्थान मार्च, 2004 में होने वाली प्रस्तावित आई एफ ए सी बोर्ड की बैठक की मेजबानी करेगा। इस अवसर पर, सी ए पी ए के कार्यपालक समिति की बैठक और एस ए एफ ए की संभा बैठक भी होनी है।

7. आई सी ए आई - 21 शताब्दी पर भावी दृष्टि

20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में तेजी से बदलते विश्व के आर्थिक परिदृश्य से लेखांकन वृत्ति का पुनःपुनरीक्षण करने की आवश्यकता हो गई है और उसे प्रतिस्थापित करने के लिए संस्थान एक उच्च क्षमता वाले न्यासी हो गए हैं तथा इसके लिए अनेक संस्थाओं को सम्बोधन किया जा रहा है और स्टाक होल्डर के आधिक्य में विनियामकों, उद्योग, जनता की काफी आशाएं बढ़ गई हैं।

संस्थान के परिषद ने भावी दृष्टि विचरित करने और वृत्ति की पुनर्संरचना के लिए पहले एक समिति गठित की थी। प्रारूप दायित्व/विजन विवरण में अनेक सदस्यों और स्टाक होल्डरों को सम्मिलित किया गया था तथा सभी स्टाक होल्डरों से प्राप्त विचार तथा राय के माध्यम से उपयुक्त विचार वाली युक्तियों की जांच की। जब ऐसी युक्तियां बनाई जा रही थी तब यह उपयुक्त समझा गया था कि कार्यान्वयन चरण सहायता करने के लिए इन युक्तियों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

“आई सी ए आई - 21वीं शताब्दी पर भावी दृष्टि” नामक विजन और पुनर्संरचना संबंधी समिति की रिपोर्ट का विमोचन नई दिल्ली में 15वें अखिल

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सम्मेलन की समाप्ति के दौरान 5 जनवरी, 2003 को संघ के उपमोक्षता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री माननीय श्री शरद यादव के शुभ हाथों से हुआ था। रिपोर्ट भावपूर्ण रूप से 21वीं सदी में संस्थान की भावी दृष्टि और स्टाक होल्डरों की आशाओं से संबंधित है और अन्य बातों के साथ, सदस्य स्तर, फर्म स्तर और संस्थान और वृत्ति स्तर पर पर्याप्त युक्तियों का सामना करने की आवश्यकता और उभरते हुए व्यापार आर्डर के संदर्भ में समसामयिक और प्रकट होने वाली विचारधारा से संबंधित है।

8. अन्य क्रियाकलाप

8.1 मानव संसाधन विकास

8.1.1 मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में संस्थान के सदस्यों और छात्रों की बदलती हुई अपेक्षा पद्धति को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

(i) विशिष्टता का विकास करना, प्रबंध दबाव, अंतर वैयक्तिक संबंध, समूह कार्य, विनिश्चय करने में सहक्रिया, प्रतिरक्षा और सहायक संचार आदि जैसे मानव अभिनाम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम/नियोजन विकास कार्यक्रम

(ii) सभी अधिकारियों और कर्मचारिवृंदों के लिए शारीरिक समस्याओं और प्रबंध दबाव के समाधान के लिए योग थेरापी से संबंधित कार्यक्रम।

(iii) संस्थान के संगठन और कृत्य की दृष्टि से, नियुक्त नए अधिकारियों के लिए कार्यक्रम।

(iv) वरिष्ठ अधिकारियों के लिए संगठनात्मक उत्कृष्टता संबंधी कार्यशाला।

(v) नियमित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम जिसमें वास्तविक संस्थान परियोजना भी सम्मिलित है।

इस प्रकार, नियमित संसाधन प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें कम्प्यूटर पाठ्यक्रम भी है, मुख्यालय और प्रादेशिक स्तरों पर आयोजित किए जा रहे हैं।

8.1.2 मानव संसाधन - कल्याणकारी उपाय

संस्थान का यह विचार है कि मानव संसाधन, संगठन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण आस्तियाँ हैं। इसने अपने कर्मचारियों के लिए अनेक कल्याणकारी स्कीमें चलाई हैं जैसे - शिक्षा भत्तों का पुनरीक्षण और अनुग्रह संदाय, सामाजिक समामेलन आयोजित करने के लिए सहायिकी का नगदीकरण आदि।

8.2. सदस्यों और छात्रों की सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

संस्थान एक दशक से अधिक समय से अपने दिन-प्रति-दिन की प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रभावी रूप से कर रहा है। संस्थान की प्रमुख प्रकृति को और इसकी विनियामक तथा उन्नतिशील प्रक्रियाओं की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह अपनी पैतृक संपत्ति को वितरित उपयोजनों से केन्द्रीकृत यथार्थ संस्थान प्रणाली में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करता है। तदनुसार, इसने अपने आई.टी. मसौदे में इस कल्पनादृष्टि को शामिल करके एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसलिए, कारबार और प्रौद्योगिकीय वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से कदम मिलाते हुए और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की प्रक्रिया जारी रखने की दृष्टि से यथार्थ संस्थान परियोजना (वी.आई.पी.) को क्रियान्वित करने के लिए समुचित विकास पहल शुरू हो गई है।

8.2.1 यथार्थ संस्थान परियोजना

वी.आई.पी. जिसे गत वर्ष में प्रारंभ किया गया, अब क्रियान्वयन के विकसित चरण में आ गई है। उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं पर आधारित सिस्टम डिज़ाइन पूर्ण हो गया है और परियोजना विकास/जांच चरण में है। वी.आई.पी. सीवनहीन मोड में, भारत में सभी कार्यालयों की प्रक्रियाओं को संघटित करेगी और संस्थान के सभी कार्यों में आन लाइन पहुंच को सुनिश्चित बनाएगी। वी.आई.पी. के साथ-साथ कारबार प्रक्रियाएं पुनरीक्षित और परिष्कृत की जाती हैं। इसके द्वारा मुद्दों को सुदृढ़ बनाने की भी आशा है।

इस प्रणाली से संस्थान एक गृह संस्थान की ओर आगे बढ़ेगा और सदस्यों तथा छात्रों को उनकी दहलीज़ पर सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

ऐसी आशा की जाती है कि वी.आई.पी. उचित व्यक्ति (सदस्य, छात्र, संस्थान का पदधारी) को उसकी दहलीज़ पर उचित सूचना प्रदान करके संस्थान के कार्यकरण में एक उदाहरणीय परिवर्तन लाएगी। परियोजना की संकल्पना गृह बैंककारी, कहीं/किसी भी समय बैंककारी के समान है। परियोजना से 7 x 24 x 365 सेवाएं गृह संस्थान/कहीं भी/किसी भी समय संस्थान के रूप में प्राप्त होंगी। यह संस्थान को कागजहीन कार्यालय की ओर अग्रसर करेगी जिससे सदस्यों और छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, पेमेंट गेट वे आन लाइन सुविधाओं सहित प्राप्त होंगी।

8.3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अखिल भारतीय सम्मेलन

संस्थान ने नई दिल्ली में 3 से 5 जनवरी, 2003 तक “अकाउंटेंसी - डाइवर्स डिमांड्स ‘डिसीपिलिड एपरोच’” विषय पर चार्टर्ड अकाउंटेंटों का 15वां अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया। हालांकि सम्मेलन को अखिल भारतीय सम्मेलन के रूप में नामित किया गया था परन्तु यह वस्तुतः एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें चाइनीज़ इंस्टीट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स से एक प्रतिनिधि मंडल के अतिरिक्त पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश से साफा सदस्य निकायों के प्रधानों ने भाग लिया था। सम्मेलन स्वयं में एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि सर डेविड टवीडी, अध्यक्ष इन्टरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड और श्री रेने रिकोल, अध्यक्ष इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स ने भी श्रोताओं की सम्मानीय जनसमूह को संबोधित किया था जिससे सदस्यों के वृत्तिक ज्ञान में वृद्धि हुई।

सम्मेलन का उद्घाटन 3 जनवरी, 2003 को विज्ञान भवन में माननीय केन्द्रीय वित्त और कंपनी

कार्य मंत्री श्री जसवंत सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया था और सभी तीनों दिवसों की सम्माननीय जनसमूह इसकी साक्षी थी। इस सम्मेलन में श्री सुरेश प्रभु, संसद सदस्य (भूतपूर्व विद्युत मंत्री), माननीय केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री आनन्दराव वी. अदसुल, भूतपूर्व विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली, श्री मणिशंकर अय्यर, संसद सदस्य जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों से अपनी बुद्धिमानी के विचार बांटे। सम्मेलन में अध्यक्ष, सेबी, अध्यक्ष आई.आर.डी.ए. सचिव कंपनी कार्य विभाग सहित प्रतिष्ठित/विशेषज्ञ व्यक्तियों ने भाग लिया। कुछ अन्य विशेषज्ञों ने भी वृत्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने भाषणों में उजागर किया। सम्मेलन का समापन माननीय केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और लोक वितरण मंत्री श्री शरद यादव द्वारा हुआ जिसमें “आई.सी.ए.आई. - विज्ञान फार 21 फर्स्ट सेंचुरी” का अनावरण भी माननीय मंत्री द्वारा किया गया।

चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति और संस्थान के लिए यह एक यादगार अवसर था क्योंकि सम्मेलन का आयोजन लगभग छः वर्षों के अन्तराल के बाद हुआ था और इसमें मौजूद जन समूह को देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझने तथा उनके संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के संभाव्य योगदान को जानने का अवसर प्राप्त हुआ था। सम्मेलन में समकालिक महत्व के मुद्दों पर सक्रिय - चर्चा की गई जैसे - निगमित शासन का ऐक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए आर्थिक सुधारों की वास्तविकताएं लेखपालों और समाज के मध्य पुनः संबंध स्थापित करना, वित्तीय सेक्टर, कराधान और निगमित विधियों से संबंधित मुद्दे और अवसर। तकनीकी विषय-वस्तु के कारण केवल यही जीवंत नहीं रहा बल्कि सम्मेलन ने कुछ मनोरंजक क्षण भी देखे जब सम्मेलन पैकेज के रूप में सम्मेलन की दूसरी शाम को “ऊषा मंगेशकर नाइट” का भरपूर आनन्द प्रतिनिधियों ने उठाया।

सम्मेलन में 1300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें 9 देशों से प्रतिनिधिमंडल भी थे। प्रिंट मीडिया ने सम्मेलन को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। कारपोरेट/पब्लिक सेक्टर का सक्रिय

योगदान और स्पांसरशिप रहा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन्धुत्व पर सम्मेलन का सम्मोहक और अभिष्ट प्रभाव रहा।

8.4 संपरीक्षा समिति

संपरीक्षा समिति का गठन वर्ष 2001-02 में परिषद द्वारा किया गया था जिसमें अन्य के अतिरिक्त स्वीकृत उद्देश्य थे - वित्तीय सूचना की सच्ची और सही प्रकृति सुनिश्चित करने के लिए इसकी बाबत संस्थान की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और प्रकटन पद्धति का अवलोकन, प्राथमिक रूप से लेखांकन नीतियों को अपनाए जाने पर जोर देते हुए वार्षिक वित्तीय विवरणों की परिषद को प्रस्तुत किए जाने के पूर्व समीक्षा, लेखांकन मानक और लागू विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन तथा समाधान आदि, आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता को आंकना और आंकड़ा सुरक्षा, सत्यनिष्ठा की क्षमता तथा वित्तीय और जोखिम प्रबंध नीतियां।

समिति ने अपने निर्देश निबंधनों के ढांचे के भीतर कार्य करना जारी रखा। समिति ने, वर्ष के दौरान कतिपय नियत आस्तियों पर अवक्षयण प्रभार की बाबत लेखांकन नीतियों और संस्थान की सहबद्ध और फैलो सदस्यता के लिए आवेदकों से प्राप्त प्रवेश फीस और दाखिला फीस का आय और आरक्षित में आबंटन की समीक्षा की। समिति ने संस्थान के आय और व्यय विवरण को पुनरीक्षित प्रूफ में प्रस्तुत किए जाने की भी सिफारिश की है जिससे कि क्रियाकलाप आधार प्रक्रियात्मक परिणाम के अधिक उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित किया जाए।

समिति ने संस्थान और इसके अंगों के कार्यकरण को वर्णित करने वाली विवेक और उपयुक्तता मुखी शासन प्रक्रियाओं के अनुपालन पर अधिक जोर दिया और इस प्रयोजन के लिए इसने प्रबंध मंडल के साथ संस्थान के संपरीक्षकों की संपरीक्षा के पूर्व और बाद में कारण सहित चर्चा को सुकर बनाया। यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों को लागू किया गया कि संस्थान में प्रादेशिक सार पर कार्य कर रही संपरीक्षा समिति का भरपूर योगदान हो।

चालू वर्ष के दौरान, समिति ने वर्ष 2003-2004 से लिए कार्ययोजना के अनुसरण में कार्य करने का दृढ़ संकल्प लिया और संस्थान के विभिन्न कार्यालयों में बैठकें करके उनके क्रियाकलापों की समीक्षा की तथा पद्धति में सुधार लाने के लिए उपायों की सिफारिश की जिससे उनकी प्रक्रियात्मक क्षमता बढ़ाई जा सके और वे स्वतंत्र मुद्दों, जिनमें सूचना, सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के मुद्दे भी हैं, को पहचाना जा सके।

8.5 वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड

8.5.1 संस्थान की परिषद ने वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड का गठन जुलाई, 2002 से इसकी एक अस्थाई समिति के रूप में किया है।

8.5.2 बोर्ड में संस्थान की परिषद के सात सदस्य हैं जिनमें से दो केन्द्रीय सरकार के नामनिर्देशित हैं।

8.5.3 बोर्ड कतिपय विनियामकों सहयोजित करने पर भी विचार करेगा। विनियामकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति, बोर्ड के परिकल्पित संरचना बोर्ड को कंपनियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने और दोषी कंपनी के विरुद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने में सुकर बनाएगी।

8.5.4 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड ने अपने निर्देश-निबंधनों को निम्नानुसार अंतिम रूप दिया: -

(i) यह संभव सीमा तक अवधारण करने की दृष्टि से कतिपय उद्यमों के साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेगा :

(क) वित्तीय विवरणों के तैयार किए जाने और प्रस्तुतिकरण में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ अनुपालन ;

(ख) उद्यम से सुसंगत विनियामक निकायों, कानून और नियमों तथा विनियमों द्वारा निहित प्रकटन अपेक्षाओं के साथ अनुपालन ; और

(ग) उद्यम और संपरीक्षक की रिपोर्टिंग बाध्यता के साथ अनुपालन।

(ii) यह साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों की समीक्षा या तो स्वप्रेरणा से या आर.बी.आई., सेबी, आई.आर.डी.ए. आदि

विनियामक निकायों द्वारा इसे निर्दिष्ट किए जाने पर कर सकेगा यह ऐसे उद्यमों के साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों की भी समीक्षा कर सकेगा जिनके संबंध में मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से उनके साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों में अनियमितताओं को उजागर किया गया है।

(iii) उपरोक्त पैरा (1) में कथित तथ्यों के अनुपालन के संबंध में बोर्ड के निष्कर्ष, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन संबंधित संपरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने का आधार बनेंगे। जहां तक उद्यम के प्रबंधमंडल का संबंध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को सुसंगत शक्तियां प्रदान करने के लंबित रहते हुए, बोर्ड उद्यम के सुसंगत विनियामक निकाय को अनियमितता बाबत सूचित करेगा और इसकी संसूचना प्रबंध मंडल को भी देगा।

(iv) वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड के क्षेत्राधिकार के भीतर उद्यमों में निम्नलिखित है :

(क) ऐसे उद्यम जिनके ऋण या साम्य प्रतिभूति भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध किए जाते हैं ;

(ख) लोक वित्तीय संस्थाएं और बैंक ;

(ग) 50 करोड़ रुपए या अधिक का आवर्त वाले असूचिबद्ध और अन्य वाणिज्यिक उद्यम;

(घ) उद्यमों का ऐसा अन्य प्रवर्ग जो बोर्ड की राय में वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुति करने में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन, उद्यम के सुसंगत विनियामक निकायों, कानून, नियमों और विनियमों द्वारा विहित प्रकटन अपेक्षाओं के अनुपालन की संभावना के कारण लोक हित भेद्य बनाता है।

(v) ऐसे लेखांकन और संपरीक्षा मुद्दे हो सकते हैं जिनका स्पष्टीकरण अपेक्षित है। ऐसे स्पष्टीकरण जारी करने की बोर्ड को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तथापि, यदि बोर्ड की यह राय है कि किसी मुद्दे पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है तो वह उस मुद्दे को

परिषद् की समुचित समिति को विचारण के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

8.5.5 बोर्ड, साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करने के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रचालित प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बोर्ड 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा प्रारम्भ कर देगा।

8.5.6 मीडिया द्वारा उजागर की गई कुछ उद्यमों के वित्तीय विवरणों की अनियमितताओं पर आधारित कतिपय समीक्षाएं भी पुनर्विचारित की जा रही हैं। इसके अलावा, बोर्ड ने 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत में 500 अग्रणी कंपनियों, जिनमें बैंककारी, बीमा, पारस्परिक निधि और विद्युत कारोबार वाली कंपनियां शामिल हैं, के साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों की भी इच्छा व्यक्त की है।

8.6 शिक्षा और प्रशिक्षण समीक्षा समिति

मई, 2003 में शिक्षा और प्रशिक्षण समीक्षा समिति, शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रति 'देख-रेख और अनुरक्षण' की सतत नीति के भाग रूप में (सी.आर.ई.टी.) गठित की गई।

समिति की प्रथम बैठक 15 जुलाई, 2003 को आयोजित हुई। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, परिषद् द्वारा विचारण और अनुमोदन के लिए निम्नलिखित निर्देश निबंधनों को अंतिम रूप दिया :

- ◆ परिवर्तनशील वातावरण और वृत्ति की मांग के संदर्भ में संस्थान की सदस्यता के लिए विद्यमान शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली की सुसंगतता और पर्याप्ता को अवधारित और सुनिश्चित करने के लिए इसकी समीक्षा।
- ◆ आई.एफ.ए.सी. की शिक्षा समिति जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा विकसित अहर्तापूर्व और अर्हता पश्चात् के निर्देश से अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा मानकों में उल्लिखित मानक और वर्णन प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए समुचित, उपायों पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

- ◆ छात्रों के लिए वृत्तिक शिक्षा कार्यक्रम की विषय-वस्तु में समुचित परिवर्तनों पर विचार करने और उन्हें अपनाने के लिए विद्यमान पाठ्यविवरण की समीक्षा।

- ◆ बढ़ती हुई अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त करने के उपायों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, विद्यमान शिक्षा की स्वीकृति और उपयोजन तथा प्रशिक्षण प्रक्रिया और पारस्परिक पहचान करार।

- ◆ सदस्यों के लिए सतत वृत्तिक शिक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार (इसमें सदस्यता पश्चात् परीक्षाएं शामिल हैं)

- ◆ पूर्वगामी पेशाओं में उल्लिखित विषयों से उत्पन्न ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो समिति अवधारित करे।

समिति ने अपने व्यापक लक्ष्यों और उद्देश्यों पर विचार-विमर्श किया और विद्यमान शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली की समीक्षा के लिए बहुभुजी रणनीति अपनाने का विनिश्चय किया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सदस्यों, छात्रों, सेवा के उपयोगकर्ताओं, विद्याविदों, वेबसाइट और अन्य माध्यमों से विशेष रूप से अभिकल्पित प्रश्नावलियों के मुद्दे पर एक व्यापक परामर्शी प्रक्रिया, प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण, शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रवेश अपेक्षाएं, व्यावहारिक प्रशिक्षण, सैद्धान्तिक शिक्षा और अन्य संबंधित पहलू तथा अर्हता पश्चात् परीक्षाओं पर विचार करने के लिए पृथक अध्ययन समूहों की स्थापना, चयनित व्यक्ति के साथ सांसद और आई एफ ए सी की शिक्षा समिति जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों की उद्धोषणाओं के विशिष्ट निर्देश से वृत्तिक लेखांकन शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय रुझानों का अध्ययन विश्व के अग्रणी वृत्तिक लेखांकन निकायों के पाठ्यक्रम विवरण तथा उच्चतर शिक्षा के अन्य सुसंगत केन्द्र शामिल हैं।

9. अन्य विषय

9.1 आई.सी.ए. आई. का वार्षिक समारोह।

आई.सी.ए.आई. का वार्षिक समारोह 4 फरवरी, 2003 को अशोक होटल, नई दिल्ली में

आयोजित किया गया। केन्द्रीय खान राज्य मंत्री माननीय श्री रमेश बियास मुख्य अतिथि थे। समारोह में सर्वोत्तम प्रस्तुत लेखा के लिए संस्थान के प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं को शील्ड और प्लेक, संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को पुरस्कार और मेडल और संस्थान की उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को शील्ड और प्रशंसा पत्र वितरित किए गए। समारोह में उच्च सरकारी अधिकारियों आई.सी.ए.आई. के सदस्यों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आमंत्रितों की बड़ी संख्या ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वृत्ति पर प्रशंसा के फूलों की बारिश की।

9.2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस की याद में 5 जुलाई, 2003 को अशोक होटल, नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया। माननीय डा. विमल जालान, तत्कालीन गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने “रिफार्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर - वे फारवर्ड” विषय पर एक विशेष भाषण दिया। समारोह में बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा अनेक स्थानों पर शाखाओं ने भी स्थानीय रूप से भव्य रूप में समारोह आयोजित किए।

9.3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में संशोधन

क. चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में संशोधन

आई.सी.ए.आई. की परिषद् ने जुलाई, 2002 में आयोजित इसकी बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों की समीक्षा के लिए कार्य-समूह की सिफारिशों पर विचार किया। परिषद् ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के संशोधनों पर अपनी सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने हेतु अंतिम रूप दे दिया है। आई.सी.ए.आई. की परिषद् द्वारा अंतिम रूप दिए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के प्रारूप संशोधन 3 अगस्त, 2002 को केन्द्रीय

सरकार को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उक्त संशोधन केन्द्रीय सरकार के सक्रिय विचारण के अधीन है।

ख. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988, में संशोधन

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित अर्हतात्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करके विनियम 204 में कतिपय संशोधनों को अंतिम अनुमोदन प्रदान कर दिया है :

♦ बीमा और जोखिम प्रबंध में अर्हतात्तर पाठ्यक्रम

(ii) प्रस्तावित संशोधन

संस्थान की परिषद् ने वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) उत्तीर्ण करने और कम्प्यूटर प्रशिक्षण के 250 घंटे पूरा करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण कराने वाले आबद्ध शिक्षार्थियों के संदेय वृत्तिका की बढ़ी हुई दरों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से विनियम 43 में प्रस्तावित संशोधन करने के लिए अनुरोध किया गया है। अनुसूची ‘ग’, ‘घ’ और ‘ङ’ में पहले प्रस्तावित अन्य संशोधन, जिनके द्वारा परिषद् को विभिन्न फीसें नियत करने और इन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विनिश्चित करने के लिए शक्ति प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की गई थी, सरकार के विचाराधीन हैं और सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन मिलने के पश्चात् उन्हें जनसाधारण की टिप्पणियों के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

9.4 पूर्व अध्यक्षों की बैठक

गत वर्ष पूर्व अध्यक्षों की बैठक के जोरदार प्रोत्साहन से उत्साहित होकर यह महसूस किया गया कि ऐसी बैठकों को इस वर्ष भी, जहां तक संभव हो, जारी रखा जाए। तदनुसार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संस्थान के पूर्व अध्यक्ष/प्रादेशिक परिषदों के सभापति के मध्य कोलकाता, मुम्बई और चैन्नई में क्रमशः 27 मार्च, 2003 को, 17 अप्रैल, 2003 और 18 अप्रैल, 2003 को बैठकों का आयोजन किया गया। उक्त

बैठकों में सामान्यतया वृत्तिक महत्व के विषयों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए और विशेष रूप से (i) वृत्तिक विकास के लिए नए मार्ग; (ii) छोटे और मध्यम व्यावसायियों को सुदृढ़ बनाने के लिए रणनीतियाँ; (iii) संस्थान को एनरोन घटनाक्रम के बाद के काल में स्थापित करने; (iv) वृत्ति को विश्व में प्रतियोगिताओं और संभावनाओं के लिए तैयार करना; और (v) वृत्ति के नियमन और विकास से संबंधित अन्य मुद्दों पर बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए।

9.5 केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय संस्थान के सदस्यों, छात्रों और विभिन्न संकलित लेखों की एक सूची के साथ पुस्तकें, पत्रिकाएँ, समाचारपत्र और संदर्भ सुविधाएँ प्रदान करता है। इनकी एक सूची प्रत्येक मास संस्थान की पत्रिका में “अकाउंटेंट्स ब्राउज़र” संदर्भ के अधीन प्रकाशित की जाती है। संदर्भ सेवा विशेष मामले के रूप में अनुसंधानकर्ताओं और फाउंडेशन पाठ्यक्रम के छात्रों को भी प्रदान की जाती है। संस्थान के नौएडा कार्यालय में भी केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यालयों पर विभिन्न निदेशालयों को नामित पुस्तकालय भी प्रदान किए गए हैं। डेलनेट के माध्यम से पुस्तकालय की नेटवर्किंग, भारत में और विदेश में क्रियात्मक है और पुस्तकालय सामग्री, जिसके अंतर्गत पुस्तकें, पत्रिकाएँ, आर्टिकल, सदस्यों का अभिलेख है, का कम्प्यूटरीकरण किया गया है जो पूछताछ पर तथा वेब मोड्यूल पर उपलब्ध है। 10,000 से अधिक आर्टिकल का भंडारण आधार जिसके अंतर्गत आई.सी.ए.आई. की पत्रिका “चार्टर्ड अकाउंटेंट्स” के आर्टिकल हैं, भी पुस्तकालय साफ्टवेयर में उपलब्ध हैं। उपरोक्त के अलावा समुचित लेन वर्जन भी स्थान पर है जो 8000 कंपनियों का सबसे अधिक विश्वसनीय और सशक्त कारपोरेट डाटाबेस है। डाटाबेस वित्तीय विवरण, अनुपात विश्लेषण, निधिकार, उत्पाद प्रोफाइल, विवरणियाँ और स्टॉक मार्केट में जोखिम आदि प्रदान करता है।

उपरोक्त के अलावा, पुस्तकालय सेवाएँ देश भर के प्रादेशिक केन्द्रों और शाखाओं में भी प्रदान

की जाती हैं। विभिन्न प्रादेशिक पुस्तकालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के पश्चात् केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय डाटाबेस से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुस्तकालयों के विकास के लिए संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संगमों और अध्ययन केन्द्रों को उदार अनुदान प्रदान किए जाते हैं। परिषद् ने सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं में उपलब्ध पुस्तकालय सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष अनुदान देने का विनिश्चय किया है।

9.6 संपादक मंडल

संपादक मंडल अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है अर्थात् - अपने सदस्यों को वृत्तिक ज्ञान, वृत्तिकों को आई.सी.ए.आई. रूचिगत मामलों से संबंधित मामलों और क्रियाकलापों और ऐसे अन्य मामले जिन्हें बांछागत रूप में शैक्षिक वृत्तिक मूल्य का समझा जाता है “द चार्टर्ड एकाउंटेंट” पत्रिका या अन्य माध्यम से स्त्रियमित रूप से पहचानना। पत्रिका सदस्यों के क्षेत्रों में मुख्य क्षमताओं को विभिन्न प्रकार से विकसित करने पर ध्यान दे रही है। संबंधित क्षेत्रों में प्रसिद्ध विशेषज्ञ समकालिक विषयों पर स्तंभ लिख रहे हैं।

पत्रिका ने उच्च वृत्तिक मानक बनाए रखा है और रिपोर्ट की पूरी अवधि के दौरान छाया रहा जिससे इसका मासिक परिचलन 1,50,000 प्रतियों तक पहुंच गया। अब पत्रिका का अधिकाधिक संस्थाओं में और लेखांकन तथा अन्य संबंधित वृत्तियों के व्यक्तियों द्वारा पढ़ा जाता है, उदाहरणार्थ - विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, पुस्तकालय और पत्रिका खरीदने वाले अनेक संगठन/कारपोरेट।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संपादक मंडल के निम्नलिखित कार्यकलाप महत्त्वपूर्ण रहे हैं :

◆ निम्नलिखित विषयों पर पत्रिका का प्रकाशन।

- सूचना सुरक्षा संपरीक्षा
- बीमा उद्योग
- मूल्य वर्धित कर

- ◆ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के अवसर पर अर्थात् 1 जुलाई, 2003 को एक विशेष अंक निकाला गया। कुछ अन्तरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित विशेषज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट लोगों ने इस अंक में अपने लेखों का योगदान किया।
- ◆ चार्टर्ड अकाउंटेंटों को उपलब्ध “वृत्तिक अवसर” पर नियमित स्तंभ का अप्रैल, 2003 से प्रकाशन।
- ◆ “नीतिशास्त्र की संहिता” पर अप्रैल, 2003 से लेखों की श्रृंखला का प्रकाशन।
- ◆ अनेक सरकारी परिपत्रों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन।

संपादक मंडल, पत्रिका की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए समुचित उपाय कर रहा है जिससे कि इसे न केवल संस्थान के सदस्यों और छात्रों में, बल्कि लेखांकन वृत्ति से संबंधित अन्य लोगों को भी अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके।

10. सदस्य

10.1 सदस्यता

31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, संस्थान द्वारा 9177 नए सदस्यों को दर्ज किया गया जिससे 1 अप्रैल, 2003 को उसके कुल सदस्यों की संख्या 1,10,256 हो गई।

पूर्व वर्ष में 2486 की संख्या की तुलना में, 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 2866 सहयोजित सदस्य फ़ैलों के रूप में प्रविष्ट किए गए।

1.4.2003 को सदस्यों की संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	सहयोजित (1)	फ़ैलों (2)	स्तम्भ (1) और (2) का योग
सीओपी धारक	44512	30887	75339
अन्य	5125	29732	34857
योग	49637	60619	110256

10.2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हितकारी निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हितकारी निधि ऐसे जरूरतमंद लोगों, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को उनके पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। निधि के आजीवन सदस्यों की संख्या 31 मार्च, 2002 को 31,370 से बढ़कर 31 मार्च 2003 को 47,752 हो गई है।

	31.3.2002 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.3.2003 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
दी गई वित्तीय सहायता	26,97,200	34,50,500
प्रशासनिक खर्च	1,05,251	1,45,898
निधि अधिशेष (कमी)	(3,91,944)	1,23,42,341
निधि का अतिशेष	22,33,335	1,45,75,676
कोरपस का अतिशेष	1,82,38,500	3,42,50,000

11. छात्र

11.1 शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम

1 अक्टूबर, 2001 से प्रारम्भ की गई शिक्षा और प्रशिक्षण की एक नई स्कीम ने सफलतापूर्वक एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रम I और पाठ्यक्रम II के छात्रों के प्रथम बैच तथा फाइनल पाठ्यक्रम (नया पाठ्यविवरण) के छात्रों ने नवंबर, 2002 में अपनी-अपनी परीक्षाएं दीं।

नई स्कीम के भाग रूप में निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :-

11.1.1 फाइनल (नया पाठ्य विवरण) छात्रों के लिए सैद्धांतिक शिक्षा स्कीम के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया गया और उन्हें प्रादेशिक परिषदों एवं शाखाओं में परिचालित किया गया। स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

11.1.2 साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पर 15 दिवसीय पाठ्यक्रम के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे छात्रों को जिन्होंने अपना व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, संस्थान की सदस्यता के लिए आवेदन करने के पूर्व इस पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। नई स्कीम के अंतर्गत नवंबर, 2002 में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के फायदे के लिए इस पाठ्यक्रम का संचालन सभी पांच प्रादेशिक मुख्यालयों में किया गया। मई, 2003 में हुई फाइनल परीक्षा के परिणामों की घोषणा के पश्चात् इस पाठ्यक्रम का संचालन प्रादेशिक मुख्यालयों और प्रादेशिक परिषदों की अनेक शाखाओं में भी किया गया। पाठ्यक्रम का संचालन प्रादेशिक मुख्यालयों और शाखाओं में आवधिक अंतरालों से किया जाएगा।

11.1.3 250 घंटे का अनिवार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण : व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकरण के पूर्व 250 घंटे के अनिवार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण को क्रियान्वित कर दिया गया है विशेष रूप से प्रत्यायित एवं राष्ट्र व्यापी रूप से कार्यरत कतिपय प्रमुख कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे निट, एपटेक, एस.एस.आई., फर्स्ट कम्प्यूटर्स के अतिरिक्त कतिपय प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं के कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों और कुछ ऐसी संस्थाओं द्वारा भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम I और II) के लिए मौखिक कोचिंग कक्षाओं हेतु पहले से ही प्रत्यायित हैं और जिनके पास आवश्यक संरचनात्मक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में, 2 प्रादेशिक परिषदों, प्रादेशिक परिषदों की तीन शाखाओं के कम्प्यूटर केन्द्रों और इस प्रयोजन के लिए 5 प्रत्यायित

संस्थाओं को प्रत्यायन प्रदान किया गया है। अनिवार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण के 250 घंटे के कार्यक्रम के लिए एक समान पाठ्यक्रम सामग्री तीन मोड्यूलों में जारी कर दी गई है। हाल ही, बोर्ड ने छात्रों से प्राप्त पुनर्निवेश के आधार पर स्कीम के प्रचालन पर पुनर्विचार किया है तथा प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तर पर प्रचालित कुछ और संस्थाओं के प्रत्यायन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया है।

11.2 छात्रों की सेवाएं

11.2.1 पाठ्य विवरण में शामिल अनेक विषयों से संबंधित व्यापक अध्ययन सामग्री का भेजा जाना जारी है। इसके अलावा फाइनल के छात्रों के फायदे के लिए अलग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री जारी की गई है जिसमें प्रबंध लेखांकन और वित्तीय विश्लेषण के प्रारूपिक प्रश्न और उनके उत्तर अंतर्विष्ट हैं। वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा किए गए संशोधनों की बाबत निःशुल्क अनुपूरक अध्ययन सामग्री भी जारी की गई है।

11.2.2 छात्रों के फायदे के लिए आवासीय प्रास्थिति और कर विविक्षाओं पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया है, जो अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में कारगर सिद्ध होगी।

11.2.3 वृत्तिक शिक्षा - II के छात्रों के लिए कारबार और निगमित विधि के विषय पर प्रश्नोत्तर का एक संकलन जारी कर दिया गया है।

11.2.4 पूर्व स्कीम के अंतर्गत फाउन्डेशन/इन्टरमीडिएट तथा नए वृत्तिक शिक्षा - I के, वृत्तिक शिक्षा - II और फाइनल (नया पाठ्य विवरणों) के लिए पुनरीक्षण जांच पत्र और उनके उत्तर जारी कर दिए गए हैं।

11.2.5 फाइनल की अध्ययन सामग्री के हिन्दी में अनुवाद, मुद्रण और वितरण के लिए एक प्राइवेट प्रकाशक के साथ व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। फाइनल पाठ्यक्रम (समूह I) की अध्ययन सामग्री हिन्दी में शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी और उसके बाद समूह II की अध्ययन सामग्री जारी की जाएगी।

11.2.6 मई, 2002 में आयोजित फाउन्डेशन/इन्टरमीडिएट/फाइनल परीक्षाओं और नवंबर, 2002 में आयोजित पुराने पाठ्यक्रम की फाउन्डेशन/इन्टरमीडिएट/फाइनल परीक्षाओं और नए पाठ्यक्रम की वृत्तिक शिक्षा-I/वृत्तिक शिक्षा - II और फाइनल परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के प्रस्तावित उत्तर वाल्यूम्स जारी किए गए हैं।

11.2.7 ऐसे सभी स्थानों पर रविवार की परीक्षाएं अनिवार्य करने का विनिश्चय किया गया है जहां पर शाखाएं और परीक्षा केन्द्र हैं। इसे शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

11.2.8 परीक्षाओं के लिए तैयारी करते समय पाठ्यविवरण के विभिन्न विषयों के संबंध में उत्पन्न शंकाओं और कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से छात्रों की सहायता करने के लिए प्रादेशिक कार्यालयों में निःशुल्क काउंसेलिंग सेवा प्रारम्भ की गई है।

11.2.9 बोर्ड के संकाय सदस्यों का एक परामर्शी समूह गठित किया गया है जिससे कि वृत्तिक शिक्षा और फाइनल पाठ्यक्रम वाले छात्रों द्वारा पूछी गई शैक्षिक शंकाओं का उत्तर आन लाइन पर देकर उनकी सहायता कर सके।

11.3 प्रशिक्षण गाइड और आचार संहिता

शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, 1994 में निकाली गई प्रशिक्षण गाइड को पूर्ण रूप से पुनरीक्षित कर दिया गया है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आबद्ध संपरीक्षा प्रशिक्षणार्थी अच्छी संरचनात्मक और क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। पुनरीक्षित प्रशिक्षण गाइड में अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण अभिलेख के पुनरीक्षित प्रारूप व्यावहारिक/औद्योगिक प्रशिक्षण की रिपोर्ट शामिल है। पुनरीक्षित प्रशिक्षण गाइड 1 जनवरी, 2003 से प्रभावी है।

चार्टर्ड लेखाकर्म छात्रों के लिए एक आचार संहिता जारी कर दी गई है। संहिता में आबद्ध/संपरीक्षा प्रशिक्षणार्थियों के आचरण को उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों के

आचरण को भी शामिल करने की इच्छा व्यक्त की गई है।

11.4 आत्म विकास पुस्तिका श्रृंखला

इस वर्ष के दौरान, “टाइम एण्ड स्ट्रैस मैनेजमेंट” और “स्किल्स फार जनरल कोरेस्पोंडेंस” जैसे चयनित विषयों पर पुस्तिकाएं निकाली गईं।

11.5 छात्रों की संख्या

11.5.1 31 मार्च, 2002 और 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्षों के दौरान पी.ई.- I पी.ई. - II और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी:

पाठ्यक्रम	2002-2003	2001-2002
पी ई - I	35524	5006 (1.10.2001 से 31.3.2002 तक)
पी ई - II	24786	11848 (1.10.2001 से 31.3.2002 तक)
आर्टिकल सहित पी ई - II	8497	17555
फाइनल	11102	11524

11.5.2 अध्ययन बोर्ड के रजिस्टर में प्रविष्ट 31 मार्च, 2003 को छात्रों की कुल संख्या (उन छात्रों को छोड़कर जो वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रम I के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं), 31 मार्च, 2002 को छात्रों की कुल संख्या 2,58,995 (2,47,147+ वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रम II के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्र 11,848) की तुलना में, 2,80,399 थी।

11.6 प्रत्यायन स्कीम

31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 1) के छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित करने के लिए 70 संस्थाओं को (जिसमें 8 शाखाएं और 1 क्षेत्रीय परिषद् हैं) तथा

(पाठ्यक्रम 2) के लिए 44 संस्थाओं को (जिसमें 1 क्षेत्रीय परिषद् और 6 शाखाएं हैं) प्रत्यायन प्रदान किया गया। इस समय वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 1) के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की संख्या 70 और वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 2) के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की संख्या 44 है। नवम्बर, 2002 में होने वाली परीक्षा के छात्रों के फायदे के लिए 14 संस्थानों ने वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 1) की कक्षाएं और मई, 2003 की परीक्षाओं के लिए 66 संस्थानों ने कक्षाएं आयोजित की। 10 संस्थानों ने वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 2) की कक्षाएं नवंबर, 2002 की परीक्षाओं के लिए और 24 संस्थानों ने मई, 2003 की परीक्षाओं के लिए आयोजित की।

कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने के प्रयोजन के लिए दुबई में समुद्रपार एक संस्थान को प्रत्ययन प्रदान किया गया।

11.7 सेमिनार और सम्मेलन

11.7.1 कोलकाता में 29 और 30 नवम्बर, 2002 को 15वीं अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन “एक्सीलेंस थ्रू वेल्थ बेस्ड नोलेज” विषय पर किया गया। सम्मेलन में पूरे देश से 742 छात्रों ने भाग लिया। सम्मेलन को गणमान्य व्यक्तियों और व्यावसायियों ने संबोधित किया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत 11 चयनित विषयों से संबंधित 17 तकनीकी पेपरों पर चार तकनीकी सत्रों में चर्चा की गई।

11.7.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड ने एक दिवसीय संगोष्ठी, वक्तृता/क्विज़ प्रतियोगिता और प्रादेशिक/राज्य स्तर पर सम्मेलनों के आयोजन को बढ़ावा देना जारी रखा।

(i) 10 शाखाओं ने बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् ने 6 अक्टूबर, 2002 को एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें 738 छात्रों ने भाग लिया।

(ii) सी.आई.सी.ए.एस.ए की इन्दौर शाखा ने 5 दिसंबर, 2002 को एक आधे दिन की संगोष्ठी का आयोजन किया।

(iii) एस.आई.सी.ए.एस.ए. की कालीकट शाखा ने 21 दिसंबर, 2002 को समस्त केरल छात्र सम्मेलन आयोजित किया।

(iv) कोलकाता में 6 जुलाई, 2002 को पूर्वी भारत सी.ए.छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया।

(v) डब्ल्यू.आई.सी.ए.एस.ए की औरंगाबाद शाखा ने 20 और 21 दिसंबर, 2002 को दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

(vi) दक्षिणी भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संघ ने बंगलौर में 4 और 5 जनवरी, 2003 को दो दिन का क्षेत्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया।

(vii) 13 और 14 जुलाई, 2002 को रायपुर में छठा मध्य सी.ए. छात्र सम्मेलन आयोजित हुआ।

(viii) एस.आई.आर.सी.की कोट्टायम शाखा ने 6 और 7 जुलाई, 2002 को दो दिवसीय छात्र सम्मेलन आयोजित किया।

(ix) एर्नाकुलम में 8 जनवरी, 2003 को 8वीं अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता और दूसरी अखिल भारतीय क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस वर्ष के दौरान 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 19 शाखाओं ने शाखा और प्रादेशिक स्तर पर वक्तृता प्रतियोगिता आयोजित की तथा 5 क्षेत्रीय सहित 20 शाखाओं ने शाखा और प्रादेशिक स्तर पर क्विज़ प्रतियोगिता के विजेताओं ने अंतिम प्रतियोगिता में भाग लिया।

(x) 26 से 28 जून, 2003 तक गोवा में पश्चिमी भारतीय छात्रों ने एक उप क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

(xi) एस.आई.सी.ए.एस.ए. की एर्नाकुलम शाखा और एस.आई.आर.सी. की एर्नाकुलम शाखा ने दो दिवसीय समस्त केरल सी.ए.छात्र सम्मेलन का आयोजन एर्नाकुलम में 4 और 5 जुलाई, 2003 को किया।

(xii) एस.आई.सी.ए.एस.ए. की कालीकट शाखा ने भी “स्ट्राइविंग अहेड, टुवार्ड्स एपिटोम” विषय पर कालीकट में 12 जुलाई, 2003 को एक दिवसीय समस्त केरल छात्र सम्मेलन आयोजित किया।

(xiii) पूर्वी भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ और ई.आई.आर.सी. ने 13 जुलाई, 2003 को कोलकाता में “एजुकेशन एंड वेल्थ एडिशन” विषय पर एक दिवसीय पूर्वी भारत सी.ए. छात्र सम्मेलन आयोजित किया।

11.7.3 20 और 21 जून, 2003 को चैन्नई में “एक्सपेंडिंग द होरीजन्स आफ नालिज, स्किल्स एण्ड वेल्थूज” विषय पर 16वां अखिल भारतीय सी.ए. छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के 9 छात्रों सहित देश के विभिन्न भागों से 1550 प्रतिनिधियों की रिकार्ड संख्या ने भाग लिया। सम्मेलन को गणमान्य व्यक्तियों और व्यवसायियों ने संबोधित किया। लेखांकन और संपरीक्षा, निगमित विधि, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधि, वृत्तिक नीतिशास्त्र के क्षेत्रों से चयनित 12 विषयों पर छात्रों द्वारा प्रस्तुत 23 तकनीकी पेपरों पर 4 तकनीकी सत्रों में विचार किया गया। “बाडी, माइंड और इन्टेलक्ट”, एपरोच टू एक्जामिनेशन्स और “हेल्थ एण्ड ह्यूमर” पर विशेष सत्र भी आयोजित किया गया।

11.8 छात्रवृत्तियां

31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के दौरान संस्थान के कोष में से 145 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई (8 गुणता एवं आवश्यकता आधृत छात्रवृत्तियां, 37 गुणता छात्रवृत्तियां, 100 आवश्यक आधृत छात्रवृत्तियां)। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन के लिए स्थापित विभिन्न विन्यासों से प्राप्त आय में से 43 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

11.9 छात्रों का संवादपत्र (स्टूडेंट्स न्यूजलेटर)

मासिक सी.ए. छात्र संवादपत्र - द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टूडेंट्स जिसमें उपयोगी लेख, शैक्षणिक अद्यतन, आलेख और अन्य सुसंगत अद्योषणाएं हैं, छात्रों के लिए उपयोगी साबित हुई। यह प्रकाशन छात्रों और सदस्यों में भी लोकप्रिय रहा।

सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार (2,000 रु.) श्री विजय पी. मंडलोई ‘अवेन्यूज आफ इन्वेस्टमेंट’ को जिल्द V में नवंबर, 2001

के अंक में प्रकाशित उनके लेख के लिए प्रदान किया गया।

दूसरा पुरस्कार (1,000 रुपए) मिस नेहा मेहता को उनके लेख ‘टिप्स टू इम्प्रूव स्टडिंग प्रोसेस’ के लिए दिया गया, जो कि बड़ौदा शाखा की डब्ल्यू.आई.सी.ए.एस.ए. न्यूजलेटर के जिल्द 11, 2002 में प्रकाशित हुआ था।

11.10 छात्र आदान - प्रदान कार्यक्रम

शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और सी.पी.ई. पर एस.ए.एफ.ए. समिति द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसरण जून, 2002 में श्रीलंका के साथ एक छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीलंका से नौ सदस्यीय छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने 20 और 21 जून, 2002 को चैन्नई में आयोजित 16वें अखिल भारतीय सी.ए. छात्र सम्मेलन में भाग लिया। वे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की कुछ फर्मों, इन्फोसिस और एच.ए.एल जैसे औद्योगिक संगठनों और रूचि के कतिपय अन्य स्थानों पर भी गए।

10 भारतीय छात्रों का वैसा ही एक प्रतिनिधिमंडल 27 अगस्त से 7 सितंबर, 2003 तक श्रीलंका जाएगा और वहां उनके छात्रों के सम्मेलन और छात्रों के अन्य कार्यक्रमों में भाग लेगा तथा चार्टर्ड अकाउंटेंटों की फर्मों में भी जाएगा।

11.11 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं

सहकर्मी की भावना विकसित करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और बौद्धिक विकास आदि के संबर्धन में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के छात्रों को सक्रिय रूप से लंगाने की दृष्टि से संस्थान की परिषद् हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं खोलने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करती रही है। इस प्रक्रिया में, अब तक छात्र संघों की 34 शाखाएं पहले ही स्थापित हो चुकी है।

11.12 एस वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के दौरान, 200 रुपए प्रति छात्र प्रतिमास के मूल्य की 60 छात्रवृत्तियां, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने

वाले छात्रों को दी गई। निधि की सदस्यता 31 मार्च, 2002 को 324 के मुकाबले 31 मार्च, 2003 को 340 थी। निधि के पास जमा ~~रुपए~~ 31 मार्च, 2002 को 4,89,829 रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2003 को 4,69,857 रुपए थी।

11.13 सी.ए.पाठ्यक्रम को पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिए मान्यता

विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर सम्पर्क करने के बाद वाणिज्य शिक्षा और कैरियर काउंसिल समिति पी.एच.डी./फैलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 3 भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अलावा 73 विश्वविद्यालयों से सी.ए. पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रही है।

12. प्रादेशिक परिषद् और उनकी शाखाएं

12.1 संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं, अर्थात् पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद्। जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं।

12.1.1 प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 97 है।

12.1.2 फिलहाल, भारत के बाहर संस्थान के 11 चैप्टर हैं।

12.1.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बुंदेलखंड में एक नया संदर्भ पुस्तकालय स्थापित किया गया है। इसे मिलाकर पूरे भारत में 38 संदर्भ पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं।

12.2. शाखाओं के लिए भवन

रिपोर्टाधीन अवधि के प्रादेशिक परिषदों की अनेक शाखाएं अपने निजी परिसर बनाने में रुचि दिखाते रहे हैं कुल मिलाकर 50 शाखाओं के अपने भवन हैं।

12.3. शील्ड

1986-87 से संस्थान, सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् को हर वर्ष चल शील्ड देता है। पुरस्कार सम्पूर्ण कार्यों को देखकर दिया जाता है। इसी प्रकार हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड प्रदान की जाती है। पुरस्कार स्थापित सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है। अखिल भारतीय आधार पर सर्वश्रेष्ठ सी.ए. छात्र संघ को और प्रादेशिक आधार पर छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड वर्ष 1999 से चलाई गई है। वर्ष 2002 के लिए यह शील्ड 4 फरवरी, 2003 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी:-

1. सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् : पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्
2. प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा - पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की नागपुर शाखा और दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की बंगलौर शाखा को संयुक्त रूप से
3. सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ - पश्चिम भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ
4. छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा :

पश्चिमी क्षेत्र - डब्ल्यू.आई.सी.ए. एस.ए. की बड़ौदा शाखा

दक्षिण क्षेत्र - एस.आई.सी.ए.एस.ए. की एर्नाकुलम शाखा

मध्य क्षेत्र - सी.आई.सी.ए.एस.ए. की रायपुर शाखा

उत्तम कार्य प्रदर्शन को देखते हुए निम्नलिखित शाखाओं को अलग से क्रमशः अत्यंत प्रशंसनीय कार्य के लिए प्रमाण पत्र दिया गया था:

- (i) पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद् की बड़ौदा शाखा
- (ii) दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की बेलगाम शाखा
- (iii) मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की रायपुर शाखा

12.4 नव विकेद्रीकृत कार्यालय

प्रादेशिक स्तर पर कार्य/क्रियाकलाप की बढ़ती मात्रा को ध्यान में रखकर और तुरंत तथा व्यक्तिपरक सेवा के महत्व को मानते हुए जो विकेद्रीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जा सके हैं, संस्थान की परिषद् ने मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में पहले से कार्यरत विकेद्रीकृत कार्यालयों के अलावा दक्षिणी क्षेत्र में बंगलौर और हैदराबाद में, पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद और पुणे में, मध्य क्षेत्र में जयपुर में, 5 और विकेद्रीकृत कार्यालय खोल चुकी है और परिषद् ने उन्हें और अधिक प्रभावकारी और उपयोगी बनाने के लिए हाल ही में कुछ नई पहल की है।

13. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2003 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा जो परिषद् द्वारा अनुमोदित है, संलग्न है।

14. प्रशंसा

14.1 परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी हैं जिन्होंने संस्थान की समितियों पर सहयोजित सदस्य के रूप में कार्य किया है और उनका भी आभार है जिन्होंने परिषद् के शैक्षिक तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परिक्षाओं के संचालन में वर्ष 2002-2003 के दौरान परिषद् की सहायता की।

14.2 परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2002-2003 में केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

परिषद् भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहती है। परिषद् माननीय सर्व श्री जसवंत सिंह, शरद यादव, सुरेश प्रभु, अरूण जेटली, विजय गोयल, राजीव प्रताप रूडी, आनन्दराव वी.अदसुल, रमेश बियास के प्रति भी गहरा आभार प्रकट करती है जिन्होंने सुसंगत समय पर संघ की मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के अनेक कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई। इसी प्रकार से, परिषद् राज्य स्तर पर अनेक कृत्यकारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती है जिन्होंने संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई।

14.4 परिषद् आई.सी.ए.आई. द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रुचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

14.5 संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने निष्ठापूर्ण और अनथक प्रयासों के लिए परिषद् द्वारा प्रशंसनीय हैं।

सदस्यों के आंकड़े (1.4.1997 से)

सारण - 1

वर्ष (को यथाअवमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1.4.1997	सहयुक्त	14649	11013	4906	3972	6971	41511
	अध्येता	11042	8975	4369	4560	8049	36995
	योग	25691	19988	9275	8532	15020	78506
1.4.1998	सहयुक्त	16160	11564	5187	4351	7406	44668
	अध्येता	11501	9420	4558	4909	8733	39121
	योग	27661	20984	9745	9260	16139	83789
1.4.1999	सहयुक्त	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	अध्येता	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	योग	29968	22457	10341	10220	17375	90366
1.4.2000	सहयुक्त	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	अध्येता	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	योग	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1.4.2001	सहयुक्त	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	अध्येता	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	योग	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1.4.2002	सहयुक्त	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	अध्येता	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	योग	34311	24704	11168	11893	19654	101730

सदस्यों के आंकड़े (1.4.1950 से)

सारणी - 2

	1.4.1950	1.4.1951	1.4.1961	1.4.1971	1.4.1981	1.4.1991	1.4.2001
	को	को	को	को	को	को	को
अध्येता	569	672	1,590	3,326	8,642	22,136	44,789
सहयुक्त	1,120	1,285	4,059	7,901	16,796	36,862	51,603
योग	1,689	1,957	5,649	11,227	25,438	58,998	96,392

छात्र रजिस्ट्रीकरण प्रगति चार्ट (31.3.1996 से)

	31.3.1996 को	31.3.1997 को	31.3.1998 को	31.3.1999 को	31.3.2000 को	31.3.2001 को	31.3.2002 को
फाउंडेशन/ पी.ई. (पाठ्यक्रम - I)	29,015	28,209	37,052	43,809	44,180	35,999	* 34,215
इंटरमीडिएट/ पी.ई. (पाठ्यक्रम - II)	19,288	21,354	24,652	28,253	27,508	23,405	** 29,403
फाइनल	8,675	9,275	9,394	12,227	10,787	9,026	11,524
योग	56,978	58,838	71,098	84,289	82,475	68,430	75,142

* 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-I) के 5006 छात्र भी शामिल है।

** 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-II) के 11848 छात्र भी शामिल है।

	31.3.2001 को
पी ई (पाठ्यक्रम - I)	35524
पी ई (पाठ्यक्रम - II)	24786
आर्टिकल सहित पी ई (पाठ्यक्रम - II)	8497
फाइनल	11102
योग	79909

अट्टारहवीं परिषद् की रचना (2003-04)

अध्यक्ष
श्री आर.भूपति
एफसीए

उपाध्यक्ष
श्री सुनील गोयल
एफसीए

अवधि
5 फरवरी 2003 से

सचिव
डॉ. अशोक हल्दिया

18वीं परिषद् के सदस्य (2003-04)

निर्वाचित सदस्य

श्री अभिजीत बंदोपाध्याय	कोलकाता
श्री अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
श्री अशोक चंडक	नागपुर
श्रीमती भावना जी दोषी	मुम्बई
श्री गोपाल प्रसाद डोकनिया	कोलकाता
श्री जे.पी. गोखले	मुम्बई
श्री के.एस. विक्रमसे	मुम्बई
श्री मनोज फेड़नीस	इंदौर
श्री एन. नित्यानंदा	बैंगलूर
श्री एन.डी. गुप्ता	नई दिल्ली
श्री एन.वी. अय्यर	मुम्बई
श्री निरंजन साहा	कोलकाता
श्री पी.पी. पारीक	जयपुर
श्री पंकज इन्दर चंद जैन	मुम्बई
श्री आर. भूपति	चैन्नई
श्री आर.एस. अड्डुकिया	मुम्बई
श्री एस. गोपालाकृष्णन	हैदराबाद
श्री एस. संधानाकृष्णन	चैन्नई
श्री एस.एच. तलाटी	अहमदाबाद
श्री शांतिलाल डागा	हैदराबाद
श्री सुनील गोयल	जयपुर
डॉ. सुनील गुलाटी	नई दिल्ली
श्री टी.एन. मनोहरन	चैन्नई
श्री विनोद जैन	नई दिल्ली

मनोनीत सदस्य

श्री जी.सी. श्रीवास्तव	नई दिल्ली
श्री राजीव महर्षि	नई दिल्ली
श्री के.बी. शर्मा	जम्मू
श्री आर.सी. चांदीवाला	नई दिल्ली
श्री सुनील भार्गव	जयपुर

संपरीक्षक

श्री ए.सी. बब्बर, एफ.सी.ए.	नई दिल्ली
श्री राजीव रस्तोगी, एफ.सी.ए.	नई दिल्ली

संपरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 31 मार्च, 2003 को यथा-विद्यमान संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपाबद्ध आय-व्यय लेखा की भी संपरीक्षा की है, जिसमें अन्य संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित संस्थान के कार्यालयों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के लेखा सम्मिलित हैं। तीन शाखाओं के असंपरीक्षित लेखा जिन्होंने संपरीक्षित लेखा नहीं भेजे हैं, को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधमंडल का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी संपरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत संपरीक्षा मानकों के अनुसार संपरीक्षा की। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम इस संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए संपरीक्षा की योजना बनाएं और करें कि क्या वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्ध कथन से मुक्त हैं। संपरीक्षा के अंतर्गत जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की परीक्षा करना शामिल होता है। संपरीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और प्रबंधमंडल द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।
3. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :-
 - क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे ;
 - ख) तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा, जिन पर रिपोर्ट में विचार किया गया है, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं ;
 - ग) हमारी राय में लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुरूप रखे गए हैं;
 - घ) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों और लेखाओं के भागरूप टिप्पणों से संलग्न और उसके साथ पठित अनुसूचियों सहित विवरण एक सही और उचित अवलोकन प्रस्तुत करते हैं :
 - i) 31 मार्च, 2003 को यथा-विद्यमान कामकाज के तुलनपत्र के मामले में, और
 - ii) उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यय के मुकाबले आय के आधिक्य में आय-व्यय लेखा के मामले में :

ह/-
ए. सी. बब्बर
चार्टर्ड अकाउंटेंट

ह/-
राजीव कुमार रस्तोगी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 18 सितम्बर, 2003

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
31 मार्च, 2003 को यथा-विद्यमान तुलनपत्र

(रकम लाख रुपए में)

निधियों के स्रोत	अनुसूची	31.03.2003	31.03.2002
पूँजीगत आरक्षितियां	I	3031.50	2698.91
साधारण आरक्षितियां	II	1609.96	1294.09
अन्य आरक्षितियां	III	77.14	82.83
उद्दिष्ट निधियां	IV	4543.05	3698.79
	योग	9261.65	7774.62
निधियों का उपयोगनः			
<u>स्थिर आस्तियां</u>	V		
सकल ब्लाक		3913.30	3424.35
न्यूनः अवक्षयण		(1585.51)	(1302.19)
शुद्ध ब्लाक		2347.79	2122.16
<u>निवेशः</u>	VI		
उद्दिष्ट निधि निवेश		4543.05	3698.79
अन्य निवेश		2448.69	1433.12
वर्तमान आस्तियां, उधार और अग्रिमः		6991.74	5131.91
<u>सूचियां</u>	VII	218.76	188.68
प्राप्य लेखे	VIII	1153.71	813.49
नकद और बैंक अतिशेष		1093.29	1910.34
उधार और अग्रिम	IX	579.98	484.05
उप-योग		3045.74	3396.56
<u>न्यूनः वर्तमान दायित्व और प्रावधान</u>			
अग्रिम प्राप्त शुल्क/आय	X	2029.52	2110.92
व्यय के लेनदार		574.06	449.41
उपदान निधि के लिए प्रावधान		179.68	97.95
अन्य दायित्व		342.01	227.70
उप-योग		3125.27	2885.98
शुद्ध वर्तमान आस्तियां		(79.53)	510.58
<u>विविध व्यय-स्वाफ्टवेयर विकास(उस सीमा तक जो अवलिखित या समायोजित न हो)</u>	XI	1.65	9.97
योग		9261.65	7774.62
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का वक्तव्य	XV		
टिप्पणियां जो लेखाओं के अंग हैं	XVI		

ह/-
दीपक दीक्षित
संयुक्त सचिव

ह/-
जी.डी. खुशना
निदेशक

ह/-
अशोक हल्दिया
सचिव

ह/-
सुनील गोयल
उपाध्यक्ष

ह/-
आर. भूपति
अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
ए. सी. बब्बर
चार्टर्ड अकाउंटेंट

ह/-
राजीव कुमार रस्तोगी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 18 सितम्बर, 2003

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
आय और व्यय लेखा
31.03.2003 को समाप्त वर्ष के लिए

(रकम लाख रुपये में)

	अनुसूची	2002-2003	2001-2002
आय			
शुल्क	XII	5285.87	4005.55
प्रकाशन		533.56	345.74
संगोष्ठियां		513.05	486.71
निवेशों पर ब्याज		414.97	401.84
अनपेक्षित प्रावधान अपलिखित		12.71	7.76
अन्य आय	XIII	473.16	320.74
पूर्व अवधि आय		5.32	17.80
	योग	7238.64	5586.14
व्यय			
वेतन और भत्ते		1646.00	1297.11
परीक्षा व्यय		786.76	661.75
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम		357.34	89.21
सी.ए.ए.टी. पाठ्यक्रम व्यय		3.54	1.75
सुदूर शिक्षा व्यय		494.02	398.75
प्रकाशन		126.11	85.78
पत्रिका व्यय		279.14	285.08
संगोष्ठी व्यय		559.70	453.24
साधारण और प्रशासनिक व्यय	XIV	1210.58	933.23
यात्रा और वाहन -अंतर्देशीय		382.33	309.28
अंतर्राष्ट्रीय संबंध :			
-यात्रा		75.38	51.77
-शुल्क और अन्य व्यय		57.83	49.62
प्रास्थगित राजस्व व्यय(नीति सं. VII)		9.58	6.67
संपरीक्षा शुल्क			
-प्रधान कार्यालय		1.73	1.57
-अन्य कार्यालय		4.65	2.66
निवेशों के मूल्य में गिरावट के लिए प्रावधान			27.20
स्टॉक के मूल्य में गिरावट के लिए प्रावधान		20.92	4.18
अवक्षयण		263.93	170.50
पूर्व अवधि व्यय		23.10	39.29
	योग	6302.64	4868.64
शुद्ध अतिशेष		936.00	717.50
निधियों/आरक्षितियों में विनियोजन			
शिक्षा निधि [नीति सं. III (ख)]		583.22	452.30
कर्मचारी हितकारी निधि [नीति सं. III (ग)]		9.21	8.56
कम्प्यूटरीकरण निधि			200.00
साधारण आरक्षिति		343.57	56.64
	योग	936.00	717.50

महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियों का वक्तव्य
टिप्पणियां, जो लेखाओं के अंग हैं

XV

XVI

ह/-
दीपक दीक्षित
संयुक्त सचिव

ह/-
जी.डी. खुराना
निदेशक

ह/-
अशोक हल्दिया
सचिव

ह/-
सुनील गोयल
उपाध्यक्ष

ह/-
आर. भूपति
अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
ए. सी. बब्बर
चार्टर्ड अकाउंटेंट

ह/-
राजीव कुमार रस्तोगी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 18 सितम्बर, 2003

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची I पूँजीगत आरक्षितियां

(रकम लाख रुपये में)

	31.03.2003	31.03.2002
(क) साधारण:		
आरंभिक अतिशेष		
जमा:	1009.69	948.53
-सदस्यता शुल्क [नीति सं. III (क)]	23.73	14.05
-भवनों के लिए संदान	119.93	38.41
अंतरण		
साधारण आरक्षितियों से अंतरित	6.82	5.60
अन्य आरक्षितियों से अंतरित	-	-
उद्दिष्ट निधियों से अंतरित-अन्य	2.70	3.10
न्यून:		61.16
-चंडीगढ़ की भूमि के मध्ये समायोजन	(65.37)	
योग(क)	1097.50	1009.69
(ख) शिक्षा:		
आरंभिक अतिशेष	1689.22	1500.81
जमा: शिक्षा निधि से अंतरित[नीति सं. III (घ)(iii)]	244.78	188.41
योग(ख)	1934.00	1689.22
सकल योग (क)+(ख)	3031.50	2698.91

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची II

साधारण आरक्षितियां

(रकम लाख रुपये में)

	31.03.2003	31.03.2002
आरंभिक अतिशेष	1294.09	1256.31
जमा:		
आय-व्यय लेखा से विनियोजन	343.57	56.64
अंतरण		
उद्दिष्ट निधियों से अंतरण-स्वर्ण जयंती निधि	-	16.62
उद्दिष्ट निधियों से अंतरण-पदक और पुरस्कार निधि	-	0.45
अन्य आरक्षितियों से अंतरण	5.61	349.18
न्यून अंतरण:		
उद्दिष्ट निधियों में अंतरण-अनुसंधान	0.83	0.75
उद्दिष्ट निधि में अंतरण-अन्य	25.66	20.50
अन्य आरक्षितियों में अंतरण	-	9.08
पूँजीगत आरक्षितियों में अंतरण-साधारण	6.82	(33.31)
योग	1609.96	1294.09

अनुसूची III

अन्य आरक्षितियां*

(रकम लाख रुपये में)

	31.03.2003	31.3.2002
आरंभिक अतिशेष	82.83	73.93
जमा अंतरण:		
-साधारण आरक्षितियों से अंतरण	-	9.08
-उद्दिष्ट निधियों से अंतरण-अन्य	-	0.10
न्यून अंतरण:		
-साधारण आरक्षितियों में अंतरण	5.61	--
वर्ष के दौरान शुद्ध ह्रास	0.08	(5.69)
योग	77.14	82.83

* अन्य आरक्षितियां वे आरक्षितियां हैं जैसे पुस्तकालय आरक्षितियां और कोचिंग कक्षा आरक्षितियां जैसा कि प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं की पुस्तकों में अंकित हैं।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची IV
उद्दिष्ट निधियां

(रकम लाख रुपये में)

	31.03.2003	31.03.2002
अनुसंधान निधियां		
आरंभिक अतिशेष	361.07	321.69
साधारण आरक्षिति से अंतरण	0.83	0.75
वर्ष के दौरान वृद्धियां	6.86	8.48
वर्ष के दौरान आय	29.95	30.15
उप-योग (क)	37.64	39.38
	398.71	361.07
लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन और भवन निधि		
आरंभिक अतिशेष	220.33	201.03
वर्ष के दौरान आय	18.24	19.30
उप-योग (ख)	238.57	220.33
कम्प्यूटरीकरण निधि		
आरंभिक अतिशेष	343.45	130.89
आय-व्यय लेखा से विनियोजन		200.00
वर्ष के दौरान आय	28.44	12.56
उप-योग (ग)	28.44	212.56
	371.89	343.45
स्वर्ण जयंती समारोह निधि		
आरंभिक अतिशेष	-	15.18
वर्ष के दौरान आय	-	1.44
न्यून वर्ष के दौरान भुगतान	-	-
साधारण आरक्षिति में अंतरण	-	(16.62)
उप-योग (घ)	0.00	0.00
शिक्षा निधि		
आरंभिक अतिशेष	1819.42	1419.28
आय-व्यय लेख से विनियोजन[नीति सं. III (ख)]	583.22	452.30
वर्ष के दौरान आय	150.64	136.25
न्यून: पूंजीगत आरक्षितियों में अंतरण-शिक्षा[नीति सं. III (घ) (iii)]	(244.78)	(188.41)
उप-योग (ड.)	2308.50	1819.42
पदक और पुरस्कार निधियां		
आरंभिक अतिशेष	54.86	41.59
वर्ष के दौरान वृद्धियां	0.95	13.08
वर्ष के दौरान आय	4.62	3.93
न्यून: वर्ष के दौरान भुगतान	2.56	3.23
साधारण आरक्षिति में अंतरण	-	0.45
समायोजन	0.39	0.06
उप-योग (च)	(2.95)	(3.74)
	57.48	54.86

अनुसूची IV

उद्दिष्ट निधियां(जारी)

		31.03.2003	(रकम लाख रुपये में)	31.03.2002
विद्यार्थी छात्रवृत्ति निधियां				
आरंभिक अतिशेष		24.54		23.62
वर्ष के दौरान वृद्धियां				
वर्ष के दौरान आय	2.03	2.03	2.26	2.26
न्यून: वर्ष के दौरान भुगतान		(1.23)		(1.34)
उप-योग (छ)		<u>25.34</u>		<u>24.54</u>
पेंशन निधि				
आरंभिक अतिशेष		455.45		419.23
वर्ष के दौरान वृद्धियां	161.59		28.03	
वर्ष के दौरान आय	37.71	199.30	40.25	68.28
न्यून: वर्ष के दौरान भुगतान		(40.90)		(32.06)
उप-योग (ज)		<u>613.65</u>		<u>455.45</u>
छुट्टी नकदीकरण निधि				
आरंभिक अतिशेष		221.52		195.16
वर्ष के दौरान वृद्धियां	72.49		36.93	
वर्ष के दौरान आय	18.34	90.63	18.73	55.66
न्यून: वर्ष के दौरान भुगतान		(34.23)		(29.30)
उप-योग (झ)		<u>276.12</u>		<u>221.52</u>
कर्मचारी हितकारी निधि				
आरंभिक अतिशेष		36.02		26.07
आय-व्यय लेखे से विनियोजन[नीति सं. III (ग)]	9.21		8.56	
वर्ष के दौरान आय	2.96	12.19	2.51	11.07
न्यून: वर्ष के दौरान भुगतान		(1.35)		(1.12)
उप-योग (अ)		<u>46.66</u>		<u>36.02</u>
अन्य निधियां(प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)				
आरंभिक अतिशेष		162.13		127.10
जमा/न्यून: समायोजन	(0.31)		0.10	
वर्ष के दौरान वृद्धियां	9.61		15.63	
वर्ष के दौरान आय	11.96		11.64	
साधारण आरक्षिति से अंतरण	25.66		20.50	
		46.92		47.87
न्यून: पूंजीगत आरक्षितियों में अंतरण-साधारण	2.70		3.10	
अन्य आरक्षितियों में अंतरण			0.10	
वर्ष के दौरान भुगतान	2.62	(5.32)	9.64	(12.84)
उप-योग(ट)		<u>203.73</u>		<u>162.13</u>
सकल योग		<u>4543.05</u>		<u>3698.79</u>

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची V
स्थिर आस्तियां

आस्तियां	सकल ब्याक				अवस्यण ब्याक		मुद्द ब्याक		(रकम लाख रुपये में)
	1.4.2002 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान समायोजन/ अंतरण/विक्रय	31.3.2003 को लागत	1.4.2002 तक	वर्ष के दौरान समायोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.3.2003 तक	31.3.2002 को लागत के बाद लागत	
1. भूमि पूर्ण स्वामित्व (टिप्पण सं. 9)	169.67	31.48	(59.62)	141.53	0.00		0.00	141.53	169.67
2. भूमि-पट्टाधृत	9.69			9.69	2.12	0.22	2.34	7.35	7.57
3. भूमि (ए.आर. एफ.) पट्टाधृत	289.45			289.45	15.49	3.22	18.71	270.74	273.96
4. भवन	884.10	33.64		917.74	291.17	31.31	322.48	595.26	592.93
5. विद्युत संस्थापन और फिटिंग	142.43	18.80	(0.48)	160.75	66.76	7.17	74.93	85.82	75.67
6. वातानुकूलन	100.40	35.29	0.45	136.14	58.45	8.87	67.50	68.64	41.95
7. फर्नीचर और फिक्सचर	340.02	43.64	(0.53)	383.13	153.88	20.89	174.47	208.66	186.14
8. लिफ्ट	41.63	18.05		59.68	13.29	3.72	16.99	42.69	28.34
9. कार्यालय उपकरण	251.16	39.99	(0.69)	290.46	124.50	22.59	147.17	143.29	126.68
10. यान	22.92	5.89	(3.28)	25.53	7.88	3.79	9.27	16.26	15.04
11. पुस्तकालय की पुस्तकें	218.38	29.28	(0.06)	247.60	165.02	82.43	247.60	0.00	53.36
12. कम्प्यूटर	503.19	45.27	(3.07)	545.39	403.63	79.72	484.05	61.34	99.56
उप-योग	2973.04	301.33	(67.28)	3207.09	1302.19	263.93	1565.51	1841.58	1670.85
13. भवन-निर्माण कार्य जारी	451.31	270.12	(15.22)	706.21	0.00		0.00	706.21	451.31
योग	3424.35	571.45	(82.50)	3913.30	1302.19	263.93	1565.51	2347.79	2122.16
पूर्व वर्ष	3054.86	386.65	(17.16)	3424.35	1139.03	170.50	1302.19	2122.16	1915.83

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची VI
निवेश

(रकम लाख रुपये में)

	31.03.2003	31.03.2002
दीर्घकालीन निवेश		
(I) भारतीय यूनिट ट्रस्ट में यूनिटें		
(i) खैराती और धार्मिक न्यास रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां यूनिट योजना (सी.आर. टी एस.-81)	114.36	448.31
न्यून: निवेशों के मूल्य में ह्रास	28.96	85.40
		105.62
		342.69
(ii) यूनिट 1964 योजना	15.29	15.29
न्यून: निवेशों के मूल्य में ह्रास	2.80	12.49
		6.95
		8.34
(iii) संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना(आई. आई.एस.एफ.यू.एस.-98)	442.09	387.80
	539.98	738.83
(II) अनुसूचित बैंकों में निश्चितकालीन निक्षेप	6451.76	4393.08
कुल निवेश	6991.74	5131.91
आबंटन		
उद्दिष्ट निधि निवेशों को आबंटित	4543.05	3698.79
अन्य निवेशों को आबंटित	2448.69	1433.12
योग	6991.74	5131.91

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची VII
सूचियां

(रकम लाख रुपये में)

	31.03.2003	31.03.2002
प्रकाशन और अध्ययन सामग्री	210.35	150.08
अध्ययन सामग्री और प्रकाशनों के लिए कागज़	59.22	68.03
(जिसमें मुद्रकों के पास कागज़ का भंडार - 54.71 लाख रु.		

पूर्व वर्ष 59.19 लाख रु. शामिल हैं)

लेखन सामग्री और अन्य मदें	19.29	19.75
उप-योग	288.86	237.86
न्यून: बेकार भंडार के लिए प्रावधान	(70.10)	(49.18)
योग	218.76	188.68

अनुसूची VIII:

प्राप्य लेखे

(रकम लाख रुपये में)

	31.03.2003	31.03.2002
निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज	998.77	644.98
अन्य प्राप्य	162.54	175.98
न्यून: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	(7.60)	(7.47)
योग	1153.71	813.49

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची IX

उधार और अग्रिम(प्राप्य-योग्य)

(रकम लाख रुपये में)

	31.03.2003	31.03.2002
कर्मचारियों को अग्रिम(आवास, यान और अन्य ऋण)	190.59	182.70
कर्मचारियों के उधार से वसूलनीय ब्याज	68.36	64.27
प्रतिभूति निक्षेप	14.67	15.24
अन्य - अग्रिम और पूर्व भुगतान	306.36	221.84
योग	579.98	484.05

अनुसूची X:

अग्रिम प्राप्त शुल्क/आय

(रकम लाख रुपये में)

	31.03.2003	31.03.2002
परीक्षा शुल्क	742.80	773.03
पत्रिका अभिदान	11.25	37.92
सदस्यता शुल्क	252.01	247.26
छात्र शुल्क	41.96	79.78
ट्यूशन शुल्क	811.23	885.03
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम शुल्क	132.02	55.08
संगोष्ठी शुल्क और अन्य संग्रहण	38.25	32.82
योग	2029.52	2110.92

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची XI

विविध व्यय - साफ्टवेयर विकास

(उस सीमा तक जितना अवलिखित या समायोजित न हो)

(रकम लाख रुपये में)

	31.03.2003	31.03.2002
आरंभिक अतिशेष	9.97	14.59
वर्ष के दौरान वृद्धियां	1.26	2.05
न्यून: वर्ष के दौरान आय-व्यय में प्रभारित	(9.58)	(6.67)
योग	1.65	9.97

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची XII

शुल्क:

(रकम लाख रुपये में)

	2002-2003	2001-2002
प्रवेश शुल्क	9.01	4.61
सदस्यता शुल्क	1262.56	1156.22
छात्र पंजीकरण शुल्क	19.44	55.90
छात्र संगठन शुल्क	3.24	9.32
सुदूर शिक्षा ट्यूशन शुल्क	1815.66	1282.67
परीक्षा शुल्क	1685.54	1385.70
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम शुल्क	479.31	109.16
सी.ए.ए.टी. पाठ्यक्रम शुल्क	11.11	1.97
योग	5285.87	4005.55

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची XIII

अन्य आय

(रकम लाख रुपये में)

	2002-2003	2001-2002
छात्र सूचना-पत्र	7.21	3.43
पत्रिका से आय-विज्ञापन	0.61	0.50
पत्रिका से आय-अभिदान	86.86	66.13
सूचना पत्र	28.76	19.22
(प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)		
कम्प्यूटर केन्द्र	32.56	13.75
अनुशासन संबंधी मामले दाखिल करने का शुल्क	0.26	0.09
कैम्पस साक्षात्कार	36.04	28.16
विशेषज्ञ सलाहकार समिति शुल्क	7.55	3.45
कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज	15.54	12.72
कोचिंग कक्षाओं से आय	178.51	115.36
(प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)		
अन्य	79.26	57.93
योग	473.16	320.74

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची XIV

साधारण और प्रशासनिक व्यय

(रकम लाख रुपये में)

	2002-2003	2001-2002
मुद्रण और लेखन-सामग्री	136.28	106.84
डाक, तार और दूरभाष	218.01	193.19
किराया, दरें और कर	166.40	137.08
मरम्मत और रखरखाव	232.77	115.01
वृत्तिक शुल्क	43.01	24.62
कम्प्यूटर केन्द्र	14.14	7.36
छात्र सूचना-पत्र	50.83	47.41
सूचना-पत्र(प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)	72.44	61.14
कैम्पस साक्षात्कार	17.66	12.27
बैंक शाखा संपरीक्षा पंजीकरण	7.20	6.30
योग्यता छात्रवृत्ति	2.93	3.70
छात्र संगठनों और संदर्भ पुस्तकालयों को अनुदान	1.52	1.74
कोचिंग कक्षा व्यय(प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)	96.63	68.03
अन्य व्यय	150.76	148.54
योग	1210.58	933.23

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची XV

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विवरण

I. लेखांकन कन्वेंशन

लेखा ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

II. राजस्व मान्यता

क) सहयोजित सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क का 1/3 अंश को आय माना जाता है।

ख) प्राप्त ट्यूशन/पाठ्यक्रम शुल्क को निम्नलिखित आधार पर आय माना जाता है :-

1) प्रशिक्षण-पूर्व(फाउंडेशन/पी.ई. I/ पी.ई. II) पी.ई. II आर्टिकल सहित पाठ्यक्रम

- वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान पंजीकृत छात्रों से प्राप्त 100% शुल्क; और
- तत्पश्चात् पंजीकृत छात्रों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क तथा शुल्क का 50%, अतिशेष को आगामी वर्ष की आय माना जाता है।

2) अन्य (इंटर और फाइनल पाठ्यक्रम)

क) एकमुश्त प्राप्त शुल्क

प्राप्ति वर्ष में पंजीकृत छात्रों से प्राप्त शुल्क का 1/3 अंश और शेष 2/3 अंश आगामी दो वर्षों में सम आधार पर।

ख) किस्तों में प्राप्त शुल्क

i) प्रथम किस्त - प्राप्ति वर्ष में पंजीकृत छात्रों से प्राप्त शुल्क का 50% और शेष 50% प्रतिशत आगामी दो वर्षों में सम आधार पर।

ii) दूसरी किस्त - प्राप्ति वर्ष में 100%

3) साधारण प्रबंध कौशल और अनिवार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्ति वर्ष में।

4) सूचना प्रणाली संपरीक्षा/सी.ए.ए.टी. पाठ्यक्रम

i) सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम शुल्क और उससे संबंधित प्रत्यक्ष व्ययों को उस वर्ष में माना जाता है जिसमें व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाता है।

ii) सी.ए.ए.टी. पाठ्यक्रम शुल्क - प्राप्ति वर्ष में

ग) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क और उससे संबंधित प्रत्यक्ष व्ययों को उस वर्ष में माना जाता है जिसमें परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

घ) निवेशों से आय

- i) यूनिटों में किए गए निवेशों पर लाभांश को प्राप्त करने के हकदारी के आधार पर आय माना जाता है।
- ii) प्रतिभूतियों और बैंकों में निश्चितकालीन निक्षेपों पर ब्याज से आय को प्रोद्भूत होने के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- iii) निवेशों से होने वाली आय को संबंधित उद्दिष्ट निधियों के आरंभिक अतिशेषों पर भारित औसत पद्धति के आधार पर उद्दिष्ट निधियों में आबंटित किया जाता है।

ड. पत्रिका अभिदान

- i) छात्रों से, पुरानी योजना के अंतर्गत, तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त पत्रिका अभिदान का 1/3 अंश प्राप्ति वर्ष की आय माना जाता है और शेष 2/3 अंश आगामी दो वर्षों में सम आधार पर आय माना जाता है।
- ii) पत्रिका के मध्ये अन्यो से प्राप्त वार्षिक अभिदान प्राप्ति वर्ष में दर्ज किया जाता है।

III. पूँजीगत आरक्षिति और उद्दिष्ट निधि में आबंटन/अंतरण

- (क) अध्येता सदस्यों से प्रवेश शुल्क और सहयोजित सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क का 2/3 भाग सीधे पूँजीगत आरक्षिति - साधारण में लिया जाता है।
- (ख) छात्रों से संबंधित गतिविधियों से उद्भूत होने वाले अधिशेष का 50% शिक्षा निधि में अंतरित किया जाता है।
- (ग) वर्ष के दौरान सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क (सहयोजित और अध्येता तथा प्रैक्टिस प्रमाणपत्र शुल्क) का 0.75% कर्मचारी हितकारी निधि में आबंटित किया जाता है।
- (घ) निम्नलिखित उद्दिष्ट निधियों में से पूँजीगत आरक्षिति-शिक्षा में अंतरण:-

- | | |
|---|--|
| i) कम्प्यूटरीकरण निधि में से | विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और प्रधान कार्यालय कम्प्यूटरीकरण परियोजना के संबंध में कम्प्यूटरों और संबंधित साधित्रों की क्रय लागत का 100%। |
| ii) लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन और अन्य भवन निधि में से | लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन से संबंधित स्थिर आस्तियों की लागत का 100%। |
| iii) शिक्षा निधि में से | अन्य स्थिर आस्तियों की अतिरिक्त लागत (कटौती के पश्चात् शुद्ध) का 50%। |

IV स्थिर आस्तियां/अवक्षयण

- क) स्थिर आस्तियां मूल लागत में से अवक्षयण घटाने पर वर्णित की जाती हैं।
- ख) पट्टाधृत भूमियों का पट्टा अवधि में क्रमिक अपाकरण किया जा रहा है।

- ग) वर्ष के दौरान कम्प्यूटर और पुस्तकालय पुस्तकों पर प्रभारित अवक्षयण की दरों में परिवर्तन किया गया है ।
 इस कारण प्रभारित अवक्षयण आय-व्यय लेखे में 59.49 लाख रुपए अधिक है ।
 घ) अतिरिक्त आस्तियों पर अवक्षयण का मासिक आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है ।
 ड.) अवक्षयण अवलिखित मूल्य पद्धति पर निम्नलिखित दरों पर लगाया जाता है :-

भवन	5%
वातानुकूलन और कार्यालय उपकरण	15%
लिफ्ट, विद्युत संस्थापन और फर्नीचर और फिक्सचर	10%
यान	20%
कम्प्यूटर	60%
पुस्तकालय पुस्तकें	100%

V निवेश

- क) एक वर्ष से अधिक की अवधि तक के लिए धारित या धारित किए जाने के आशयित निवेशों को दीर्घकालीन निवेश माना जाता है ।
 ख) अन्य निवेशों को अल्पकालीन निवेश माना जाता है ।
 ग) सभी निवेशों का मूल्य लागत पर निकाला जाता है । स्थायी मूल्य ह्रास का प्रावधान किया जाता है ।

VI सूचियां

- क) कागज, लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुओं का मूल्यांकन लागत पर और प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री का प्रथम प्राप्ति प्रथम निकास पद्धति के आधार पर लागत पर किया जाता है ।
 ख) पुरानी अध्ययन सामग्री और संस्थान के एक वर्ष से अधिक पुराने प्रकाशनों की स्टॉक लागत पर शत-प्रतिशत प्रावधान किया जाता है । इसके अतिरिक्त, नए पाठ्य-विवरण के सिवाय बी.ओ.एस. प्रकाशनों के शेष स्टॉक की लागत पर 25 प्रतिशत प्रावधान किया जाता है ।

VII प्रास्थगित राजस्व व्यय

साफ्टवेयर विकास प्रभार मध्ये कम्प्यूटरीकरण व्ययों को, जिसके अंतर्गत क्रय किए गए साफ्टवेयर की लागत भी शामिल है, प्रास्थगित राजस्व व्यय माना जाता है जिसे तीन वर्ष की अवधि में बराबर-बराबर अपलिखित किया जाता है ।

VIII सेवांत/सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं

- क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित उपदान मध्ये अवधारित दायित्व को आय-व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है ।
 ख) बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित पेंशन और छुट्टी नकदीकरण मध्ये अवधारित दायित्व आय-व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है और इसके लिए पृथक् उद्दिष्ट निधियां रखी जाती हैं ।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान**अनुसूची XVI****लेखाओं के भागरूप टिप्पणियां**

1. आकस्मिक दायित्व: चार शाखाओं की बाबत सम्पत्ति/भवन कर संबंधी विवादग्रस्त रकम मद्धे 22.98 लाख रुपये की राशि के लिए प्रावधान नहीं किया गया है(पूर्व वर्ष में 18.25 लाख रुपये) ।
2. विभिन्न पक्षकारों के 9.02 लाख रुपये के दावे(पूर्व वर्ष में 9.02 लाख रुपये) संस्थान द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं ।
3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन निर्धारण वर्ष 2002-03 तक आय-कर से छूट प्रदान की गई है । छूट के नवीकरण के लिए आवेदन कर-प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है ।
4. पूंजीगत प्रतिबद्धता की प्राक्कलित रकम(अग्रिमों के पश्चात् शुद्ध) 274.13 लाख रुपये है(पूर्व वर्ष में 449.47 लाख रुपये) ।
5. निवेशों पर प्रोद्भूत 998.77 लाख रुपये के ब्याज को(पूर्व वर्ष में 644.98 लाख रुपये) लेखा प्राप्यों के अधीन शामिल किया गया है ।
6. पूर्ण स्वामित्व भूमि के अंतर्गत हुबली स्थित भूमि से संबंधित 2.62 लाख रुपये भी शामिल हैं जिसके संबंध में मुकदमा चल रहा है ।
7. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहित और पुनः वर्गीकृत किया गया है ।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रकम लाख रुपये में)

	2002-2003	2001-2002
क. क्रियाशील कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
शुद्ध अतिरिक्त	936.00	717.50
समायोजन:		
अवक्षयण	263.93	170.50
अन्य निवेशों से प्राप्त व्याज	(414.97)	(401.84)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व क्रियाशील लाभ	784.96	486.16
सूचियों में वृद्धि	(30.08)	(58.02)
प्राप्य रकमों में कमी/वृद्धि	(340.22)	(12.99)
उधारों और अग्रिमों में वृद्धि/कमी	(95.93)	4.61
अग्रिम प्राप्त शुल्क/आय में कमी/वृद्धि	(81.40)	344.19
व्ययों के लिए लेनदारों में वृद्धि/कमी	124.65	(6.64)
उपदान निधि के प्रावधान में वृद्धि/कमी	81.73	(12.91)
अन्य सयित्वों में वृद्धि	114.31	67.71
प्रकीर्ण व्यय में कमी(उस सीमा तक जो अपलिखित या समायोजित नहीं है)	8.32	4.62
क्रियाशील कार्यकलापों से शुद्ध नकदी	(218.62)	330.57
	566.34	816.73
ख. निवेशकारी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
स्थिर आस्तियों का अर्जन	(488.96)	(376.83)
निवेशों का अर्जन	(1859.83)	(157.05)
अन्य निवेशों से प्राप्त व्याज	414.97	401.84
उद्दिष्ट निधि निवेशों से आय	304.30	278.41
पूंजीगत प्राप्तियां	246.12	78.29
निवेशकारी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी	(1383.39)	224.66
नकदी/नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी	(817.05)	1041.39
अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	1910.34	868.95
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	1093.29	1910.34

डा० अशोक हल्दिया, सचिव

[सं० विज्ञापन/III/IV/104/03-असाधारण]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2003

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(5)/54/2003.—In pursuance of Sub-section (5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Report and the Audited Accounts of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2003 is hereby published for general information.

54th ANNUAL REPORT

The Council of the Institute of the Chartered Accountants of India has immense pleasure in presenting its 54th Annual Report for the year ended 31st March, 2003. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), which was set up by an Act of Parliament on 1st July, 1949, entered into its 54th year of existence during the year. The Council, at the outset, commends the members and students for the respect which the Chartered Accountancy profession commands today in the Society. This has been achieved by excellence, independence and integrity displayed by the members and students all along.

It would not be an exaggeration, if it is stated that the year under report was a turbulent one not only for the profession of chartered accountancy in the country, for the reasons not attributable to it, but also for the accountancy profession globally. The tirades made against our profession were smashed with facts and figures and also by proactive measures to further strengthen the profession. The members have been kept abreast of the same from time to time. In essence, the focus had been on dissemination of facts and perspective for proper appreciation at all levels, bridging up the expectation gap, raising the level of technical and education standards, and extending the role of the

profession in newer and normal areas. Crisis brings in challenges and opportunities as well. As in the past, the profession has been able to overcome the challenges and emerge stronger.

The Report highlights the important activities of the Council and its various Committees. The Report also covers the seminars and conferences organised, training programmes conducted, relevant statistics relating to members and students and also the accounts of the Institute for the year 2002-2003. The important activities and major initiatives of the ICAI upto the end of July, 2003 have also been briefly mentioned.

1. THE COUNCIL

The Eighteenth Council was constituted on 5th February, 2001 for a period of three years upto 4th February, 2004. In terms of the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council should be composed of 30 members — 24 elected members and 6 members to be nominated by the Central Government. The composition of the Council for the year 2003-2004 commencing from 5th February, 2003 is shown separately.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949,

constituted on 5th February, 2003 three Standing, and various Non-Standing Committees to deal with matters concerning the profession. Besides the above, the Committee for Review of Education & Training was also constituted, inter alia, to review the existing system of education and training thereby determining and ensuring the relevance and adequacy of the CA qualification in the context of the changing environment and demands on the profession. During the year ended 31st March, 2003, 159 meetings were held of various Committees of the Council as compared to 154 meetings held during the year ended 31st March, 2002.

3. AUDITORS

Shri A.C. Bubber, FCA and Shri Rajiv Rastogi, FCA were the Joint Auditors of the ICAI for the year 2002-2003. The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

4.1 Executive Committee

This Committee looks after the maintenance of various registers pertaining to students/members/firms, admission, removal and restoration of members, consideration of matters relating to members including issue of certificate of practice, matters relating to students including according permission to them, condonation of delay on the part of students/members/firms, matters connected with Branches including opening of new Branches, opening of new Chapters abroad and those connected with employees, maintenance of accounts etc.

Some of the important recommendations made by the Committee to the Council are on matters relating to:

- ♦ Becoming the founder member of International Innovative Network (IIN)

- ♦ Revised draft of the Training Guide for students of Chartered Accountancy Course
- ♦ Setting up of a Branch of Regional Council at Ahmednagar in Western Region
- ♦ Guidelines for permitting members to engage additional articled clerks in terms of Regulations 43(8) of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2001
- ♦ Format for Record of Tax Audit for the purpose of monitoring the limit of 30 tax audits
- ♦ Norms for the formation and functioning of Chapters within India at places not falling under the jurisdiction of the Regional Councils/Branches for the limited purpose of organising CPE Programmes
- ♦ Increasing the rates of stipend payable to articled clerks joining training after passing PE – II Examination
- ♦ Guidelines for conducting student-related enquiries
- ♦ Guidelines on matters to be made known to the press after the conclusion of Council meeting
- ♦ Autonomy of various Committees of the Council and the specific guidelines for forwarding the matter to the Executive Committee for approval/noting
- ♦ Placing the Accounts of the Institute before this Committee every quarter for transparency and good corporate governance.
- ♦ Guidelines for Constitution of Committees by the Regional Councils.
- ♦ Amendments in Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 - Introduction of new Post Qualification Course on "International Trade Laws and World Trade Organisation".

- ♦ Norms for the formation and functioning of Study Circles within India
- ♦ Approval for becoming a founder member of National Foundation for Corporate Governance to be set up by the Central Government to promote good corporate governance in the country
- ♦ Dispensing with the requirement to furnish client-wise details of training at times of transfer of articled clerks from one employer to another
- ♦ Registration Fee and Technical Examination Fee for the Post Qualification Course in Insurance and Risk Management

4.2 Examination Committee

The Chartered Accountants Final and Intermediate/ Professional Education-II Examinations were held in May, 2002 in 137 and 144 centres respectively spread over 85 cities, in addition to those at Dubai and Kathmandu and in November, 2002 in 134 and 140 centres respectively in 87 cities all over the country, in addition to those at Dubai and Kathmandu. The Foundation/Professional Education-I Examination(s) was/were held in May, 2002 in 129 centres and in November, 2002 in 119 centres respectively. Effective from May, 2002, new examination centres were set up at Bikaner and Udipi also. Additionally, new examination centres were set up at Bathinda and Akola from November, 2002 examinations.

The total number of candidates who appeared in the Final, Intermediate/Professional Education-II and Foundation/ Professional Education-I Examinations held in May, 2002 were 33817, 48822 and 19934 respectively and in November, 2002 were 32575, 56305 and 13794 respectively.

In May, 2003, the Chartered Accountants Final and Professional Education-II Examinations were held in 126 and 142 centres respectively spread over 90 cities, in addition to those at Dubai and Kathmandu. The Chartered

Accountants Foundation/Professional Education-I Examination(s) was/were held in May, 2003 in 123 centres at 90 cities and also at Dubai and Kathmandu. Effective from May, 2003, new examination centres were set up at Gurgaon and Hubli also.

During the year under report, for the convenience of the candidates, the following facilities were continued-

- ♦ Examination application forms in the OMR format were continued and the admit cards bearing their scanned photograph and specimen signature were issued to the candidates. This obviated the necessity of issuance of the identity card to the candidates separately.
- ♦ Examination application forms were made available, besides at all the regional offices of the Institute and branches of the Regional Councils, at different locations in the metropolis of Delhi, Kolkata and Mumbai. The facility of downloading the admit card from the website by using the Personal Identification Number (PIN) indicated by them in the OMR application form was extended.
- ♦ Results as well as marks were made available simultaneously at different locations in the metropolis of Delhi and Mumbai.
- ♦ Results were made available on the Institute's IVR system. The results as well as the marks were also made available on the National Informatics Centre's website. Merit list was also displayed on the website simultaneously with declaration of results.
- ♦ Facility of down loading of the results as well as marks by the regional offices of the Institute and branches of Regional Councils was extended simultaneously with the declaration of results.
- ♦ Facility of on-line printing of the statement of marks by the candidates from the website by using the Personal Identification

Number (PIN) indicated by the candidates in the OMR/ICR application form was extended from May 2003 examinations.

- ♦ Facility of registering requests in advance for ascertaining results on declaration was extended and candidates registering for the same were provided with their results by e-mail immediately after declaration of results.

Consultancy continued to be provided to few of the foreign institutions in the examination systems and procedures. The Institute of Chartered Accountants of Nepal successfully conducted its Foundation and Intermediate examinations with the continued technical expertise and support of the ICAI.

4.3 Disciplinary Committee

This Committee assists the Council in the maintenance of the status and standards of professional qualification awarded by the Institute. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary inquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon prima facie opinion, during the year 1st April, 2002 – 31st March, 2003, the Committee held its sittings on 28 occasions for a period spanning 49 days and at venues covering the various regions of the country. During the year under report, the Committee concluded its enquiry in 63 cases, which included cases, referred to it in previous years.

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Keeping in view the objectives of achieving and sustaining excellence, the Council continued to lay greater emphasis on technical research, professional development, continuing professional education of members and education and training of students, through its various non-standing Committees.

The Technical Committees set up by the Council continued its endeavour in the fields of accounting, auditing and allied areas.

While various research activities have been undertaken/identified, a large number of publications on accounting standards, auditing standards, expert opinions, background material for use in seminars, conferences and training programmes have also been brought out through the various Committees. These, inter alia, include the following :

5.1 Accounting Standards

Having come almost at par with the International Accounting Standards (IASs), the focus of the Accounting Standards Board during the period under report, was on ensuring that the newly issued accounting standards are implemented in an effective manner so that the purpose for which these standards are issued, i.e., meaningful and transparent financial reporting, is served. In this direction, the Accounting Standards Board issued several Accounting Standards Interpretations and General Clarifications on many accounting standards during the period.

With a view to keep pace with developments in accounting taking place the world-over, the revision to many accounting standards has been accorded priority. During the period under report, revised Accounting Standard (AS) 11, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, has been issued which will become mandatory in respect of accounting periods commencing on or after 1-4-2004. Besides this, revision to various other accounting standards is in progress.

While focussing on the issuance of Accounting Standards Interpretations, General Clarifications and revision to Accounting Standards, the formulation of new accounting standards corresponding to IASs has not been placed on the back burner. During the period under report, the exposure draft of a proposed accounting standard on 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets' has been issued; while the work on proposed accounting standard on 'Financial Instruments' has progressed substantially.

During the period under report, thirteen exposure drafts of IASs issued by the International Accounting Standards Board (IASB) were examined by the Board as a part of its 'improvement project'. On the basis of examination, the Board submitted its detailed comments on the exposure drafts to the IASB.

Besides the above, work on some other proposed accounting standards and other projects is in progress.

The Sub-committee of the Board on Accounting Standards for Governmental Bodies continued its endeavour in developing conceptual framework and accounting standards for governmental bodies.

5.2 Auditing Standards

The Auditing Practices Committee, which was originally constituted as a sub-committee of the Research Committee of the Institute, was made into a separate and independent non-Standing Committee in September 1982. In its constant efforts for achieving integrity, objectivity and excellence, the Council of the Institute set up this Committee with the basic objective of formulating Statements on Standard Auditing Practices (SAPs), representing codification of the existing best auditing practices. The SAPs were issued under the authority of the Council of the Institute and are mandatory in nature. The Committee, however, also formulates guidance notes on matters relating to auditing. Over the period of its existence, the Committee has issued more than twenty nine SAPs and more than twenty guidance notes, both generic and industry specific, on various matters relating to auditing.

The year that has gone by was a landmark year in the history of the Auditing Practices Committee. The Council, with a view to bring out clearly the nature of functions being performed by the Committee, renamed the Committee as the Auditing and Assurance Standards Board (AASB) with effect from July 2, 2002. As a result, the nomenclature of the Statements on Standard Auditing Practices (SAPs) was also changed to Auditing and Assurance Standards (AASs). However, the

most important step of the Council, aimed at bringing more transparency in the working of the Committee, was having representatives from a cross-section of regulators, like the Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India; industry representatives, for example, the Confederation of Indian Industries, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry; academics like, the various Indian Institutes of Management. The Council also decided that copies of the Exposure Drafts issued by the Committee be sent to bodies like (various) stock exchanges, office of the Comptroller and Auditor General of India and that in the due course, public hearings of the Exposure Drafts be also held.

The last year was probably one of the busiest years in the life of the AASB marked by a seminar and issuance of a number of new as well as revised AASs and two Guidance Notes. A brief overview of the work done by the Board during the period under report is as follows.

5.2.1 Seminar

The Board, in January, 2003, held an all India seminar at Hyderabad on the theme, "Auditors, Auditees and Regulators: Old Relationships, New Realities". A number of topics dealing with various issues of concern, like auditors' independence, accounting and auditing standards, regulation of the profession, banking, insurance, corporate governance etc., were also discussed. The Seminar was attended by about 1200 delegates.

5.2.2 Documents released

During the reporting period, ten Auditing and Assurance Standards (including three revised ones) were issued. A Supplement to the Guidance Note on Audit of Banks was also issued. The Supplement provided an updated guidance on audit of banks. The Board also published the Format of the Auditor's Report issued in April, 2002 and subsequently revised the same in

December, 2002. (*The format has, however, been withdrawn pursuant to issuance of AAS 28*).

Apart from the above mentioned documents, several other documents have also been approved by the Council of the Institute and the same would be published shortly.

5.2.3 General Clarifications

During the year, the Board was also empowered to issue General Clarifications on matters arising out of Statements on Standard Auditing Practices (now known as Auditing and Assurance Standards). Accordingly, in exercise of the said empowerment, the Board also issued a General Clarification on Statement on Standard Auditing Practices (SAP-9), 'Using the Work of another Auditor'.

5.2.4 Handbook of Auditing Pronouncements

The Board also brought out, the first of its kind, a Handbook of Auditing Pronouncements, in two volumes. The Handbook contained exclusively the auditing pronouncements of the Institute, viz., the Statements on Standard Auditing Practices and Guidance Notes on issues relating to auditing. Another new concept was also introduced in the form of a Compact Disc containing all the SAPs issued till July 1, 2002. This CD formed part of the Handbook.

5.2.5 Joint Committee with IRDA

During the year, a joint committee of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) and the Institute was constituted as a common platform to consider important issues and share views and ideas on audit and other concerned subjects in the insurance industry at a macro level. The first meeting of the joint committee

was held in July, 2003 at Chennai. The focus of discussion was on issues relating to investments, accounting regulations, and matters relating to actuarial regulations.

5.2.6 Interaction with the Reserve Bank of India

During the year, representatives of the Committee led by its Chairman attended a high level meeting with the State Governments and other authorities on the issue of regulation of Non Banking Finance Companies (NBFCs) and unincorporated bodies, organised by the Reserve Bank of India. A number of important issues were discussed at the said meeting, for example status of registration on NBFCs with Reserve Bank of India, unauthorised activities of companies whose application for registration had been rejected or those who had not applied for registration, companies not responding to Reserve Bank of India's communications, governmental delays in passing necessary legislation, lack of infrastructure with Reserve Bank of India, contributions by ICAI, Department of Company Affairs and Company Law Board in regulating NBFCs and unincorporated bodies, need for coordination among various bodies etc.

5.2.7 Responding to Important Legislative Developments in the Country

(i) Companies (Amendment) Bill, 2003

One of the important works done by the Board during the period under report was responding to the Companies (Amendment) Bill, 2003. The Board, alongwith the Corporate Laws Committee of the Institute, held a joint meeting in June, 2003

with the basic purpose of deliberating upon the Companies (Amendment) Bill, 2003 and identifying the anomalies therein. The Companies (Auditor's Report) Order, 2003 was also discussed at the said joint meeting. The said meeting was followed by a Roundtable on the Bill, attended among others by the Joint Secretary, Department of Company Affairs. The comments, as finalised from the deliberations at the said meeting and the Roundtable would be included in the memorandum to be submitted to the Government on the Companies (Amendment) Bill, 2003.

(ii) Companies (Auditor's Report) Order, 2003

In response to the issuance of the Companies (Auditor's) Report Order, 2003 (CARO) which would replace the existing Manufacturing and Other Companies (Auditor's) Report Order, 1988 (MAOCARO), the Board has also constituted a study group to revise the Institute's existing Statement on Manufacturing and Other Companies (Auditor's) Report Order, 1988 so as to enable the members to properly understand and also to comply with the reporting requirements of the Companies (Auditor's) Report Order, 2003.

(iii) Responding to International Developments

The Board remained responsive to the developments taking place at the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) of the International Federation of Accountants (IFAC). Recently, the Board submitted its comments on the three important Exposure Drafts issued by IFAC, viz., International Framework for Assurance Engagements, ISAE 2000 -

Assurance Engagements on Subject Matters Other Than Historical Financial Information and the (Revised) International Auditing Practices Statements on Special Considerations in an Audit of Small Entities. In addition, the Board has also undertaken the task of revising the Preface to the Statements on Standard Auditing Practices to bring it in line with the proposed Preface to the International Standards on Auditing issued by IAASB.

(iv) Projects in Progress

The Auditing and Assurance Standards Board has embarked on a number of ambitious projects to keep the members abreast with the latest developments taking place around them on the professional and legal fronts and also to keep pace with the ever increasing expectations of the society.

5.3 Research

The Research Committee brings out various publications in the form of guidance notes, research studies, technical guides on accounting and auditing in specific industries, guidelines on internal audit in respect of specific industries, monographs, etc., with a view to providing guidance to the members of the Institute in the discharge of their professional duties and to enhancing the value of the services rendered. During the year, the Committee formulated two Guidance Notes, viz., the Guidance Note on Accounting for Oil and Gas Producing Activities and the Guidance Note on Accounting for Securitisation. These have been issued under the authority of the Council of the Institute in March 2003.

With the view to suggest an accounting and financial reporting framework for Not-for-Profit sector which is based on sound accounting principles and result in presentation of true and fair view of the state of affairs and the operating results of the activities in the financial statements, the Committee issued Technical

Guide for Accounting and Audit of Not for Profit Organisations. The Technical Guide is expected to go a long way in promoting adoption of sound accounting practices in the sector. The Guidelines on Internal Audit – Tours and Travel Services has also been released by the Committee.

Apart from the above, the Guidance Note on Accounting for Equity Index and Equity Stock Futures and Options and the Technical Guide on Accounting and Audit of Chit Fund Business are under finalisation and are likely to be released shortly.

The drafts of certain research projects including the drafts of the Guidance Note on Accounting for Demergers, the Guidance Note on Accounting for Employees Stock Options (ESOPs) and Employee Stock Purchase Plans (ESPPs), the revised Guidance Note on Treatment of Expenditure during Construction Period and the Guide to Estimation of Future Cash Flows and Discount Rates are under consideration of the Committee. During the year, the Committee has decided to bring out certain new guidance notes, such as, Guidance Note on Accounting for Interest Rate Futures and Options, and Guidance Note on Accounting for Loyalty Programmes.

With a view to providing guidance to members on industry - specific issues, the Committee decided to bring out a number of new industry - specific technical guides on accounting and auditing and/or guidelines on internal audit. Apart from this, the Committee also decided to undertake the revision of all the Research Studies published prior to January 1, 1995. Besides, significant progress has been made in respect of other projects also which are at various stages of completion.

During the last year, the Research Committee published a 'Compendium of Guidance Notes – Accounting' that contains all Guidance Notes on accounting aspects which were issued upto July 1, 2002 and are valid as on the date. The said Compendium has been released with a CD containing electronic copy of the Compendium. The Compendium as on July 1, 2003, is under

preparation and is likely to be released shortly. A CD containing electronic copy of the research studies published upto July 1, 2003, which are presently not under revision, is also under preparation and is likely to be released soon.

During the year, under the aegis of the Committee, comments on the Draft Cost Accounting Records Rules in respect of Chemical Industry were presented to the Department of Company Affairs. Most of the comments presented were accepted by the Department as well.

With a view to promoting better standards in the presentation of information in the published accounts, the ICAI has been holding an annual competition for the Best Presented Accounts through the Shield Panel, a sub-committee of the Research Committee. Under the Best Presented Accounts Competition—2001-02, the Panel of Judges considered the Annual Reports and Accounts of various entities, for the year 2001-02, received under the various categories and decided to give away the awards. The Shields were presented by the Hon'ble Union Minister of State for Mines, Shri Ramesh Bais at the Annual Function of the ICAI held on 4th February, 2003.

Very recently, in order to give a fillip to the said competition at the national level, it has been decided to change the title of the Competition from "Annual Best Presented Accounts Competition" to "ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting". The awards proposed to be given now fall under the following categories:

Category I : Non-financial public and private sector enterprises (other than those covered by Category III below)

Category II : Financial Institutions in public, private and co-operative sectors, such as, banks, insurance companies, NBFCs, etc.

Category III : Not-for-Profit Organisations including companies registered under section 25 of the Companies Act, 1956.

Having regard to the significance of the proposed awards, it has also been decided to organise a befitting Function for distribution of the prizes to the award winners.

It has further been decided that a silver shield and two copper plaques be awarded under Category I and a silver shield and a copper plaque each in Categories II and III.

5.4 Corporate Laws

The Year 2002-03 was an era of significant achievements and one step further in meeting the objectives of Corporate Laws Committee. Several projects undertaken by the Committee were completed successfully. It is worth highlighting that a Study Group constituted under the aegis of this Committee undertook revision of MAOCARO after a comprehensive study. The revised final version of MAOCARO was submitted to Department of Company Affairs for suitable notification. The Committee has also initiated revision of Schedule VI to the Companies Act, 1956. During the year, several seminars and conferences were held covering a wide range of contemporary topics connected with corporate laws. The Committee also organised a number of training programmes for the Officers of Department of Company Affairs.

5.5 Fiscal Laws

Following the past practice, the Fiscal Laws Committee conducted a Workshop on Union Budget - 2003. The Workshop was attended, among others by senior Government Officers. The Post-Budget Memorandum - 2003 was submitted to the Central Government. Earlier the Committee had submitted its Pre-Budget Memorandum - 2003 to the Central Government. Some of the suggestions in the Pre-Budget Memorandum - 2003 were incorporated by the Central Government in the Finance Bill, 2003. Subsequently, some more suggestions in the Post-Budget Memorandum - 2003 were also accepted when the Finance Bill, 2003 was passed into an Act.

The Committee brought out the Second Revised Edition of the "Issues on Tax Audit". The Committee revised the Guidance Note on Audit under Section 115JB of the Income-tax Act, 1961. The Committee brought out a landmark publication "Depreciation - accounting, taxation and company law issues - A Study". This publication is a critical examination of the various facets of depreciation in accounting, taxation and company law areas.

The Committee submitted its considered response to the Report of the National Task Force headed by Dr. Vijay Kelkar. The Committee also submitted its response to the Working Group on Taxation of Non-residents. The representatives of the Committee met the Task Force on Infrastructure constituted by the Central Board of Direct Taxes (CBDT) and submitted the suggestions of the Committee. Similarly, the representatives of the Institute had a meeting with the Chairman, CBDT and exchanged views on matters of importance to the profession. The Committee provided valuable inputs to the Expert Group constituted by the CBDT to evolve the rule and format for Annual Information Return to be furnished by an assessee under Section 285BA of the Income-tax Act.

The Committee organised an All India Seminar on Taxation in Chennai. Further, it organised a National Seminar at Mangalore on Fiscal and Allied Laws in collaboration with the Mangalore Branch of the Southern India Regional Council (SIRC).

5.6 Financial Markets And Investors' Protection

Keeping in view the ground realities, growing concern and need for good corporate governance and investor protection, the Committee chartered its ambitious mission and vision for the year. Broadly, a focussed action plan was kept in mind to achieve further significant milestones in the initiatives and achievable plan of action. Efforts were made to keep a pro-active track record of interaction with the market regulators namely the Securities and Exchange Board of India (SEBI),

Department of Company Affairs, (DCA) and the Reserve Bank of India (RBI). Also, in order to bring the profession into the main stream of finance specialisation, the Committee endeavoured that a task had to be taken and initiated. For this purpose, the Committee is contemplating the structuring of an appropriate curriculum at the post-qualification level. This approach would, in a significant way, facilitate the members of the profession at par with the finance professionals. The initiatives which were embarked upon this year are:

5.6.1 Interaction with Market Regulators

The Committee and its Chairman interacted with various Advisory Committees of SEBI, namely, Advisory Committee on Mutual Funds, Committee to examine issues related to simultaneous offerings by Indian Companies and Secondary Market and Mutual Funds.

With the Department of Company Affairs, in particular reference to Investors' Protection, the Committee participated at the various meetings on Debenture Trustee Investor's Protection.

5.6.2 Awareness Programme for Small Investors

In an effort to educate and bring awareness among small investors, the Committee contemplated a specific action plan programme to conduct Small Investors' Awareness Programme, in 10 select Investors' Centres spread across India. These programmes are to be conducted in association with the following Regional Councils and their branches.

Region	Branches/Places
Western	Mumbai Vadodara
Southern	Bangalore Chennai

Central	Jaipur Agra
Eastern	Kolkata Guwahati
Northern	New-Delhi

Apart from the above programmes, a two-day National Convention of Small Investors' with the consortium support and assistance of SEBI, DCA and RBI has been proposed.

5.6.3 Re-structurisation of post-qualification Course in Management Accountancy

The Committee thought it fit that the existing post-qualification Course in Management Accountancy presently administered by the CPE Committee should be thoroughly restructured and if necessary the name of the course be changed suitably in relation to Finance Area so that it provides greater opportunity to the members of the profession for specialization. Considering the vast potentials and propounding areas of practice and services that are presently catered by the Chartered Accountants in the area of financial management and services and which are likely to emerge in future, the Committee thought it fit that if an appropriate re-structured course is introduced, it would improve the brand image of the CA Profession at par with the finance professionals.

In this connection, the Committee is presently contemplating the task of structuring and conduct of examinations of the course on its own.

5.6.4 Publications

In order to assist the members of the profession, the Committee brought out a Compendium of RBI Master Circulars in two volumes.

5.6.5 Study Material on various matters relating to CAs in the financial market services

- (i) Propounding areas of practice for CAs in Corporate, Finance and related Laws.
- (ii) Evolving a model for Self-Regulatory Mechanism for Indian Financial Markets.

5.6.6 Round Table Discussion with Chief Executive Officers (CEOs) of Mutual Fund Companies

A Study Group was constituted to study issues relating to mutual funds. The report of the Study Group was considered and in the light of various critical issues involved, it was proposed to call a round table discussion with the Chief Executive Officers (CEOs) of all mutual funds in India to discuss the issues of mutual concern to the industry, investors and regulators as well.

5.7 Expert Opinions

The Expert Advisory Committee has been constituted with the objective of answering queries of the members of the Institute on matters involving accounting and auditing principles and related areas.

The Expert Advisory Committee receives queries on wide ranging subjects. During the period under report, the Committee finalised opinions on 42 queries. The opinions finalised by the Committee included opinions on issues involving accounting principles established in the form of Accounting Standards, Guidance Notes, etc., such as segment reporting, borrowing costs, investments, revenue recognition, deferred taxation, etc. The opinions of the Committee not only provide an interpretative framework of the established accounting and auditing principles, but also lay down principles in those areas in respect of which no authoritative pronouncements have

been established so far. With the issuance of a number of accounting standards by the ICAI during the last few years, the interpretative role of the Committee has assumed even greater importance.

The opinions finalised during a year are published in a Volume of Compendium of Opinions. So far, 21 Volumes of the Compendium, containing opinions finalised by the Committee upto January 2002 have been released for sale. Volume XXII of the Compendium, containing opinions finalised by the Committee between February 2002 and February 2003, is under compilation.

The opinions of the Expert Advisory Committee represent the opinions of the members comprising the Committee and not necessarily the opinion of the Council of the ICAI. The opinions are based on the facts and circumstances of the query as supplied by the querist, accounting/auditing principles and practices and the relevant laws applicable on the date the Committee finalises the particular opinion. While finalising the opinion, the Committee also considers not only the national developments in the areas concerned but also the relevant international literature including the emerging thoughts on the subject.

Some of the opinions finalised by the Committee are being published in every issue of the Institute's Journal 'The Chartered Accountant', for information of members at large.

5.8 Continuing Professional Education

In the era of *Global Village* the necessity for continued professional updation is of utmost importance. Developments in information technology and the dynamism in the trade and industrial environment are also important drivers for newer challenges and opportunities for members of the profession. To facilitate members to uphold the high standards of professional services, the Continuing Professional Education Committee (CPE Committee) has been providing inputs to them by way of Seminars, Conferences, Background

Materials and use of the electronic media apart from conducting the post qualification courses in Management Accountancy, Corporate Management and Tax Management. The Committee has been taking all possible efforts for sharpening of professional skills so that the word "Chartered Accountant" is identical with excellence in services.

Keeping in view the growing importance of Continuing Professional Education (CPE), and the increasing level of intensity of CPE activities made imperative by the changes in the environment within which professional chartered accountants operate and engage themselves in various capacities, the Council of the Institute has issued the Statement on Continuing Professional Education which prescribes the norms of implementation of CPE activities by the Institute and its various organs for its members.

As per the Statement on Continuing Professional Education, which is effective from 1.1.2003:

- ♦ All members in practice (with certain exceptions) are required to obtain to their credit a minimum of 25 CPE hours in a block of three years with a minimum of 6 hours in every calendar year.
- ♦ All members in service in industry, or engaged otherwise than in practice, are recommended to obtain to their credit a minimum of 25 CPE hours in a block of three years with a minimum of 6 hours in every calendar year.

In order to provide the opportunities to members of the Institute to comply with the above said requirements, all the CPE Programme Organising Units (POUs) of the Institute have been advised to conduct as many CPE Programmes throughout the country as possible.

The Council has issued Norms for the formation and functioning of Chapters within India at places not falling under the jurisdiction of the

Regional Councils / Branches for the limited purpose of organizing CPE Programmes as well as the Norms for the formation and functioning of Study Circles within India. The members are encouraged to form CPE Chapters and CPE Study Circles so that CPE Programmes can be conducted at each and every possible corner of the country.

As required under the Statement on Continuing Professional Education, the CPE Committee has issued CPE Advisories on the following aspects to enable program designers, developers and organisers as well as all other persons connected with CPE activities at CPE Programme Organising Units' level, to discharge their responsibilities:

- ♦ Program development
- ♦ Use of learning technologies
- ♦ Monitors and Supervisors
- ♦ CPE Documentation
- ♦ Management of Program Costs
- ♦ Development of Background Material
- ♦ CPE support to Members in mofussil areas and remote places.

Monitors and supervisors as required under the CPE Advisory on Monitors and Supervisors are being nominated for CPE Programme Organizing Units in accordance with the relevant CPE Advisory.

The Committee has developed and distributed computer software for recording and reporting of CPE credit hours to all the Regional Councils and their Branches. The same software would be used by the Head office for the maintenance of Central CPE Database. Efforts are being taken to hoist the Central CPE Database in the website of the Institute so that the members can access the same to know about their CPE Credit.

The Committee has constituted Regional CPE Monitoring Committees to monitor the CPE related activities at the Regional level of the Institute.

Since the Committee is broad-based and meant for the members of the Institute to take care of

their post qualification education and training, the Committee has taken the initiative to revamp the Post Qualification Courses that are being conducted by the Committee.

- Accordingly, a Post Qualification Course on Financial Management is being formulated in place of Management Accountancy Course. The proposed post qualification course on Financial Management is being structured to lead to super specialization of members in the area of financial management.

The Committee is also working to revamp the course curriculums of Corporate Management Course and Tax Management Course. The Committee has been taking appropriate measures to popularize these courses. The revised curriculums of the Post Qualification Courses are being synchronized with the IFAC's requirement on Continuing Professional Development.

The teleconferencing programmes are being reintroduced to cater to the CPE requirements of the members of the Institute, in general and those residing in mofussil and remote places, in particular.

The Committee has organized 'Training for Trainers' programmes to develop CPE resource persons' base throughout the country with appropriate financial support by the Institute.

In order to encourage excellence in the area of accounting, auditing, management, economics and allied areas, the Committee continued to publish the quarterly research magazine 'Management and Accounting Research' (MAR) and try to make MAR the most sought after magazine in this part of the world. The Journal attracts technical contributions from experts, both in India and from abroad.

The Committee has been working on the following strategic initiatives:

- Strengthening of the system of production of Background Material so that member gets them at the right point of time. The CPE Directorate has

invited Expression of Interest to prepare CPE Background Materials from authors so as to publish enough number of CPE background materials to cater to the needs of members.

- Conducting modular training programmes of 100 hours/200 hours on areas of super specialization for the members of the Institute instead of launching post qualification courses in those areas.
- Approaching Ministry of HRD of Government of India for recognizing our Institute either as deemed university or as an Institution of national importance.
- Hoisting a Knowledge Portal to meet the requirements of the Continuing Professional Education of the Members.
- Revised Terms of Reference and the implementation plan in coherence with the Vision Document of the Institute so that a synergistic outcome accrues in achievement of the mandate of the Committee functions.
- Conducting Capsule modular programmes in association with Institutes of national importance on topics of contemporary and future relevance for members of the Institute.
- Organising organisational level CPE Programmes to enable the members in Industry to meet the CPE requirement and other professional to get the opportunity to share the Knowledge and Wisdom of the Institute.
- Introducing smart cards with installation of card readers in the Regional Council Headquarters and Branches to record attendance of members in CPE programmes.

5.9 Professional Development

The Professional Development Committee continued its efforts towards increasing the professional opportunities available to the members by exploring/pursuing new/existing areas where the expertise of the members could be utilised in a productive and fruitful manner. As a part of this process, it continued to interact with regulatory authorities and users of services of the profession, both in India and abroad.

The major achievements/endeavours of the Committee during the year are given below :-

- ♦ A study was made on the requirement for mandatory audit of accounts by Chartered Accountants under the VAT Acts/draft VAT Acts of various States and based on this study, an article titled "Professional Opportunities arising out of introduction of Value Added Tax" was published in the April, 2003 issue of the Institute's Journal, 'The Chartered Accountant', for information of members. Meetings for promoting the idea of professional audits by Chartered Accountants of Dealers were held with the senior officers concerned with VAT in different States including Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, and others. As a result, many States which had earlier not included the provision of audit by Chartered Accountants under their VAT Acts, later included such provisions.
 - ♦ The matter of utilising the services of ISA qualified auditors was pursued vigorously with the Indian Banks' Association and as a result many Banks have now started requesting for ISA qualified members, from the Institute.
 - ♦ Pursuant to discussions with NABARD on the allotment of audits of Regional Rural Banks to Chartered Accountants in a systematic manner as also on the scale of remuneration, NABARD has now set up a working group to go into all these matters, in which the Institute is also a member.
 - ♦ A detailed representation had been sent to RBI requesting for increase in audit remuneration for Statutory Audits of Banks in March, 2003, on account of the increase in volume and extent of work, and discussions have also been held at various levels in this regard. It appears likely that the representation will receive a favourable response.
 - ♦ The matters of systematisation of the process of concurrent audit and establishing an uniform system of engagement of concurrent auditors, promulgation of uniform guidelines for all banks as regards concurrent audits, remuneration to concurrent auditors, etc. were taken up with the Indian Banks' Association and a joint working group has now been formed to examine all these issues. The Group has representation from various banks as well as the IBA itself.
- At the Central Government level, discussions took place with the Department of Banking and Insurance, where a number of issues were identified for continuing examination as follows :
- Continuance of the provision for mandatory nomination of a Chartered Accountant on the Board of Directors of Nationalised Banks.
 - Allotment of Concurrent Audits of Public Sector Banks to Chartered Accountants/firms on the panel of auditors for Branches of Public Sector Banks.
 - Mooting the concept of a single systemic framework for all requirements of a Bank including the concurrent, inspection, revenue and credit monitoring audits etc.
 - Establishment of a Monitoring Mechanism for audit of non-corporate borrowers.
 - Need for giving weightage to Information Systems Audit Skills for internal/concurrent audits of banks.

- Need for laying down a requirement for Concurrent Audit of Branches of Insurance Companies.
 - Consideration for introducing audit of Insurance Claims settled, by Chartered Accountants.
 - Role being played by the ICAI in strengthening the financial system of banks.
- ◆ Detailed discussions were held on a continual basis with the RBI on the problems of organizing credit insurance and the general problems concerned with the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. The RBI agreed that these problems must be brought to the notice of the Audit Committees and Independent Directors of Banks and also as such agreed to participate in any program to be organized by the Institute for Chairmen of Audit Committees of Banks and Independent Bank Directors. Besides this, two other major issues were also discussed with the RBI – one concerning 'Risk Based Supervision', on which the RBI had recently issued circulars, and the other major issue which was discussed with RBI was 'Fraud' and the actions being taken by the RBI to combat the same. Among other issues discussed with the RBI were (a) Lending the expertise of the Institute to the RBI to compute Risk Based Premiums, and (b) Methods of obtaining better corporate governance in the RRBs and also Co-operative Banks through the concerned agencies.
 - ◆ A representation has been made to the RBI requesting to issue the necessary directions to all the Banks so that the managers of the unaudited branches engaged the services of Chartered Accountants to conduct the Tax Audit for the purposes of necessary certifications in these regards. This matter was pursued at a subsequent meeting with RBI and the removal of the anomaly is under its consideration.
 - ◆ As a result of vigorous persuasion, the Government of Chattisgarh has now allotted Municipal audits to Chartered Accountants, besides giving out the work of conversion of municipal accounts to accrual basis also to the Chartered Accountants.
 - ◆ In Andhra Pradesh, municipal audits are already being done by Chartered Accountants. In addition the A.P. Government has now taken a decision to get the work of internal audit for its Treasuries done by Chartered Accountants.
 - ◆ The Kerala State Task Force of the Professional Development Committee had a meeting with the Vice-Chairman and members of the State Planning Board, Kerala on 6th November, 2002 regarding "Improvement of Accounting System in Panchayati Raj Institutions". This represented a step forward towards full involvement of Chartered Accountants in improving the financial management systems in the local bodies in Kerala.
 - ◆ A number issues of direct interest to the members were pursued with various officials of the Office of Comptroller and Auditor General of India on a regular basis.
 - ◆ Representations have been sent, and presentations have been made to various State Governments for utilising the services of Chartered Accountants in the following areas:
 - (i) - Conversion of Accounts from Cash to Accrual basis of Accounting.
 - Audit under Sales Tax Act.
 - Note on Engagement of Chartered Accountants in the Co-operative Sector.
 - Involvement in Value Added Tax System.
 - Audit of Gram Panchayats and Panchayat Samities.
 - Role of Chartered Accountants in Forestry Related Activities.
 - Role of Chartered Accountants in Mining Related Activities.

- Other areas in which services of Chartered Accountants can be utilised :
- (ii) Environmental Accounting and Auditing
- (iii) End-use Certification for Utilisation of Government Grants
- (iv) Financial and Corporate Restructuring
- (v) Audit of Educational Institutions
- (vi) Audit of Health programmes
- (vii) Audit of various Entities Liable to collect Entertainment Tax
- (viii) Energy Audit
- (ix) Disaster Management

5.10 Peer Review Board

The Peer Review Board constituted by the Council of the Institute in 2002 held a series of meetings during the year under report on a regular basis.

The Peer Review Manual detailing peer review process with explanations, procedures, questionnaires to be filled by the practice unit, documents required to be maintained by the practice unit etc. has been finalised and released. Other significant activities carried out during the year are as under:-

- ♦ Applications received for empanelment as a reviewer from more than 1800 applicants have been scrutinised and letters of empanelment sent to 1600 applicants. The Panel of Reviewers is being finalised.
- ♦ Mandatory declaration called for from the practice units to be covered under Stage I of implementation of the peer review received from more than 1000 practice units, are under scrutiny. This information is being further supplemented through secondary sources viz., regulatory agencies appointing the auditors.
- ♦ The Board is regularly providing inputs to the members regarding the process

of peer review, its benefit and obligations of the Board by contributing articles in the Institute's Journal.

- ♦ In order to ensure that the peer reviewer is of a world class quality, a booklet on 'Training Modules for Peer Reviewers' has been developed for providing comprehensive training to the reviewers before the allotment of review work. The training programmes will be conducted all over the country depending on the number of empanelled reviewers, city-wise.
- ♦ An Interactive Workshop for Resource Persons identified by the Board was held at Mumbai on 18th July, 2003. The Resource Persons would later train the Reviewers at the above mentioned programmes.
- ♦ Awakening Programmes/Seminars have been organised at Delhi, Indore, Baroda, Ghaziabad, Jaipur, Ahmedabad and many more are being planned to create awareness about the Peer Review among the members and practice units.
- ♦ The Board has put in place the required framework for commencement of peer review work, as per schedule, as mandated by the 'Statement on Peer Review'.
- ♦ The Board is endeavouring to build up a unique world class Peer Review System, through establishment of the highest quality standards as a part of the peer review process as Community Quality Enhancement Programme by involving a large number of practising members who shall act as Reviewers.

5.11 Committee for Members in Industry

While various Committees of the Council of the Institute have been striving to develop industry-specific publications for providing necessary

guidance to members seeking career opportunities in such industries, or for members desirous of undertaking attest functions with reference to those industries, the Committee for Members in Industry, besides focussing its attention on conduct of campus interview, has been regularly organising programmes, spread across the country, with the sole objective of updating and sharpening the capabilities and skills of members in industry.

5.11.1 Campus Interviews

Campus Interviews introduced in September 1995 continued to receive an overwhelming response from both the employing organisations (public and private sectors including multi-nationals) and the newly qualified members interested to make their post qualification career in industry. During the year, 99 teams of employers had looked into the bio-data of about 6,311 young Chartered Accountants. Encouraged by the response to the scheme, the ICAI through its Committee for Members in Industry, organised Orientation Programmes at various interview centres to train young members to attend the Interview Boards with greater confidence. Also, two booklets, 'How to Face an Interview Board' and 'Interview Candidate's Question Bank' were sent to the candidates appearing in the Campus Interviews for their use.

5.12 Information Technology

5.12.1 Number of ISA registrations between 1st April 2002 and 31st March 2003:

The realization that the best way to capitalize on the emerging opportunities is to transform the traditional competencies in auditing and accounting into techno- based assurance skills, has impelled the members of the profession to seek knowledge updation by joining

ISA Course in a big way. This is amplified by the following :-

No. of ISA Registrations as on 31/3/2002	2892
--	------

No. of ISA Registrations between 1.4.2002 and 31.3.2003	6558
---	------

Total No. of ISA Registrations as on 31.3. 2003	9450
---	------

No. of ISA Registrations between 1.4.2003 and 1.8.2003	2520
--	------

Total No. of ISA Registrations as on date (1.8.2003)	11970
--	-------

5.12.2 ISA AT pass status between 1st April 2002 And 31st March 2003:

ISA Assessment Tests are being conducted every quarter. During the year under report,

No. of Candidates passed ISA AT as on 31.3.2002	260
---	-----

No. of Candidates passed ISA AT between 1.4.2002 and 31.3.2003	1717
--	------

Total Number of ISA AT passed as on 31.3. 2003	1977
--	------

5.12.3 ISA Resource Persons/Faculty Meet :

A Meet of the ISA Resource persons / Faculty was organised in Chennai on 8th and 9th July 2003 which deliberated and strategised action plans on the following areas:

- ◆ Revision of ISA Course Material
- ◆ Question Bank
- ◆ Mentoring of New Faculty
- ◆ Task Force for New Course on Information System Specialist (ISS)

5.12.4 IT Harmony Newsletter, the Voice of the Institute on Technology :

Commencing from the month of January 2003, the Committee on Information Technology has brought out IT Harmony Newsletter 2003, which has been highly acclaimed for the contents, design and thematic treatment. Printed versions are being brought out once in a quarter and in the remaining months the Newsletter is brought in email version. The first printed version of January 2003 issue contained a special insertion on E-Commerce and the second version of April 2003 issue focussed on Core-Banking. Apart from the thematic and contemporaneous coverage, other salient features are Interview with leaders in Government, business, technology institutions.

5.12.5 Online Test and Researched Online Study Material (ROSM) through e-learning

Through designated Managementor Portal services, twin services, namely Online Practice Tests and Researched Study Materials(ROSM) are available for the benefit of ISA participants 24 hours, 7 days a week.

5.12.6 Hands on Technology exposure of Finacle Application Programme in Infosys Campus, Bangalore on Saturday, the 17th May 2003.

On 17th May 2003, 30 ISA passed Members participated in Hands on Technology exposure of Finacle Application programme in Infosys Campus, Bangalore. Applications from ISA passed Members who intend to serve as Resource Persons for the initiatives of IT Committee were invited through the website. The first 30 applicants were chosen to attend the programme. Members had the benefit of

hands- on- exposure to the audit tools in Finacle.

5.12.7 Joint venture with The Indian Institute of Bankers:

The success of ISA course conducted by ICAI had attracted premier Institute such as The Indian Institute of Bankers(IIB), Mumbai seeking the support of ICAI in developing study material and Question Bank for a new course CeISB (Certificate in Information System, Security Banking). An understanding had already been reached with IIB for developing study material as well as providing Resource persons in the following areas:-

- ♦ Technology in Banks
- ♦ Technology – System, Development, Process, Implementation
- ♦ Security and Controls, Standards in Banking
- ♦ Continuity of Business
- ♦ Overview of legal framework
- ♦ Security policies, procedures and controls – II
- ♦ IS Review – Methodology and Approach

5.12.8 ISA Joint venture Programme with Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka :

On the request of Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL), ISA Professional Training Course developed by ICAI was launched in Sri Lanka on 27 January 2003. As per the Agreement between ICAI and ICASL, ICAI will be providing Study Materials, Faculty and Examination support.

The faculty deputed by ICAI conducted 12 Professional training programmes for ICASL which was well received by the participants. In the light of the successful completion of the first batch, there is a repeat request for conducting

another batch for participants in Sri Lanka.

5.13 Public Relations Activities Undertaken

The year witnessed a public debate world wide on the role of accounting profession, challenges and issues which also received lot of media attention. The proactive strategy was pursued to put forward in particular the Institute's viewpoint, strength of accounting profession in India and Institute's perspective on contemporary issues, also allaying the misapprehension and the concerns about the profession.

- ♦ Press conferences including with electronic media at the Head office, Regional offices and various other cities in the country on the initiatives taken/proposed to be taken, policies and programmes and also for responding to the issues concerning the profession. This included one to one meeting of the President with the leading journalists and TV Channels, on issues which confronted the profession.
- ♦ Focussed interaction with key journalists, press and electronic media, parliamentarians, Government officials, Regulators explaining the view point and initiatives being taken by the Institute on the issues related to the profession nationally and internationally.
- ♦ Emphasis on contemporary issues in public debate concerning the profession, in the programmes organised by the Institute, its Regional offices and Branches with a view to develop communication link between the Institute and members for their feedback.
- ♦ Establishing contacts and undertaking image building exercise with the accounting bodies across the globe, including the strengths of accounting profession in India in the context of the debate that followed after the collapse of some of the companies in US.
- ♦ Nodal officers for PR purposes designated at all Regional Offices to ensure dissemination of the Institute's news at the state, district and city level.
- ♦ Promoting CA Curriculum through structured articles as well as interactive meetings with the press in national as well as regional news papers.
- ♦ Building a press database for ensuring wide disbursal of Institute's news throughout the country.
- ♦ Proactive initiative for development of professional opportunities for members, creation of a positive image of the profession, highlighting the career prospects for CA students as also Services rendered by the Chartered Accountants through Advertisements in leading newspapers and magazines including Khaleej Times of Dubai.
- ♦ Proposal for Image building of the Institute and Creation of general awareness through series of episodes on TV Channels.
- ♦ Strengthening the quality of response to the members and students, in the Institute's offices and through the internet, strengthening the grievance handling mechanism, and communication through the journals and student's news letter for improving the quality of services.
- ♦ ICAI Patrika being published quarterly.
- ♦ The Website of the Institute given a face-lift and made more informative and user friendly. Introduction of new section on photo gallery and important speeches.
- ♦ Meetings with Chief Ministers and Finance Ministers of various states.
- ♦ Meeting with Secretaries of various Government Departments of Govt. of India and other State Governments.

5.13.1 Media Events

- (i) Organisation of the 15th All India Conference of Chartered Accountants in January 2003 at New Delhi which was inaugurated by Hon'ble Shri Jaswant Singh, Union Finance Minister. Ministers and former Ministers of Government of India also attended the Conference. The eminent overseas personalities, who participated in the Conference, include the President of the International Federation of Accountants (IFAC), Chairman of the International Accounting Standards Board (IASB), Heads of professional bodies in China and in the SAARC Countries. Hon'ble Shri Sharad Yadav, Union Minister of Consumer Affairs was the Chief Guest and Hon'ble Shri Suresh Prabhu, Former Union Minister of Power was the Guest of Honour at the Valedictory Session of the Conference.
- (ii) Hon'ble Shri Bhairon Singh Shekhawat, Vice President of India had released the publication 'The WTO – Road Ahead' – a document identifying concerns and possible Road Map on WTO Regime. Hon'ble Shri Rajiv Pratap Rudy, the then Union Minister of State for Commerce & Industry and Hon'ble Shri Vijay Goel, the then Union Minister of State for Labour & Parliamentary Affairs were the Guests of Honour.
- (iii) All Regional Offices and Branches were advised to celebrate 1st July as the Chartered Accountants' Day.
- (iv) Organisation of Special Address by Shri Bimal Jalan, then Governor, Reserve Bank of India, in commemoration of the CA Day, at New Delhi.
- (v) Peer Review Manual was released by Shri Vinod Dhall, former Secretary, Department of Company Affairs, Govt. of India.
- (vi) Organisation of the 53rd Annual Function of the Institute which was inaugurated by the Union Minister of State for Mines, Hon'ble Shri Ramesh Bais.
- (vii) A Roundtable Meeting of Directors (Finance) of Public Sector Undertakings was organised by the Institute which was inaugurated by Hon'ble Shri V.N. Kaul, Comptroller & Auditor General of India. Director (Fin) of about 50 PSUs besides officials of the office of C&AG participated in the Roundtable.
- (viii) A Roundtable of Chief Executive Officers (CEOs) & Chief Finance Officers (CFOs) of the Indian insurance companies and Insurance intermediaries was organised in June 2003 at Hyderabad. Shri N. Rangachary, the then Chairman IRDA presented the keynote address at the Roundtable.
- (ix) Annual Financial Reports of Municipal Corporation of Delhi prepared on Accrual Basis by the ICAI Accounting Research Foundation were formally submitted to the MCD. The Chief Guest at the function organised for the purpose was Hon'ble Shri Vijai Kapoor, Lt. Governor of Delhi. In addition, the Revised Chart of Accounts as well as the Quick Guide to the Comprehensive Financial Reports, prepared specially for the understanding of the lay reader were also released.
- (x) Joint Conference with ICA Sri Lanka was organised at Bangalore.

The Commerce Minister of Sri Lanka was the Chief Guest and WIPRO Chief, Shri Azim Premji delivered the inaugural address. 1st Joint Conference with the Sri Lankan Institute was organised at Colombo in October 2002.

New Delhi in November 2003. Meeting of the IFAC Board alongwith CAPA and SAFA meetings decided to take place in India in March 2004.

- (xi) Holding of Public Awareness and Investor's Education Programmes in different cities to make the public at large and Investors aware of the nuances of the Stock Market and their rights and responsibilities.
- (xii) Bhoomi Puja of the new building of the Institute at NOIDA.
- (xiii) Providing PR support for the programmes organised by the regional councils and the branches.
- (xiv) Finalisation of PR policy of the Institute is underway.

5.13.2 International

- (i) Organisation of Assembly meeting of the South Asian Federation of Accountants (SAFA) at New Delhi in January 2003.
- (ii) Launch of joint programme with ICA Sri Lanka on System Audit in January 2003 at Colombo, Sri Lanka.
- (iii) The Student Exchange programme with Sri Lanka was organised. Similar programme with Nepal is in the pipeline.
- (iv) Meetings with the Institutes in other countries with whom ICAI has signed MOU for mutual co-operation and recognition of qualifications.
- (v) CAPA Executive Committee meeting scheduled to be held at

5.14 Trade Laws & WTO

The Committee on Trade Laws & WTO, since its inception in 2001, has been vigorously striving to achieve its mission to establish and assure the expertise and authority of the ICAI in all matters of conceptualization, formulation, negotiation, implementation and redressal concerning Laws of trade including trade in goods and services in particular, and the implementation of international trade regimes including the WTO regime in general, both nationally and internationally, and to create and expand a base of expertise in these matters among the membership of the Institute through such ways and means as are considered to be most effective so as to fulfill stated and unstated national aspirations, concerns and needs in this regard.

During the year, the Committee continued its efforts towards identification of concerns & making comprehensive recommendations on various Agreements of WTO and dissemination of knowledge by publishing comprehensive recommendations and newsletter.

A document entitled 'Road Ahead' identifying the concerns and possible road map on WTO regime was published by the Committee. The document contains the recommendations arising out of the deliberations and discussions that took place in the International Conference on 'Concerns of the Developing Nations in the WTO Regime' organised by the Committee in 2001. The coverage encompasses Agreement wise and Article wise identification of concerns of developing countries and suggests possible road ahead, remedies and practical solutions to complex issues, which have emerged through the process of deliberations by experts from the various countries.

During the year, the Committee organised a function on 22nd February, 2003 at New Delhi

for release of the document 'The WTO - Road Ahead' at the august hands of Hon'ble Shri Bhairon Singh Shekhawat, Vice-President of India. The function was also graced by the presence of Hon'ble Shri Rajiv Pratap Rudy, the then Union Minister of State for Commerce & Industry who gave address on 'WTO - India's Perspective'.

Hon'ble Shri Vijay Goel, the then Union Minister of State for Labour and Parliamentary Affairs also addressed the gathering on 'Labour Reforms and WTO - Indian Perspective'. The function was well attended by Members of Parliament, Former Ministers, Government Officials, Members of Central Council & Regional Councils of ICAI, Members of ICAI and other professions, media and other dignitaries.

The Committee continued to publish regularly an awakening campaign publication entitled 'The WTO Pathfinder - A Technical Update on WTO Matters' providing relevant technical updates in the field for the benefit of members and other stakeholders concerned. During the period under report, the Committee published eight issues of the publication. The Committee has also started hoisting the same on the website of the Institute. The publication continued to act as a dynamic carrier of knowledge and technical/professional update on matters of interest/concern to the profession and others concerned in the field of WTO by carrying articles/updates, inter alia, on:

- ♦ WTO - Doha to Cancun
- ♦ WTO Regime - Impact on Small and Medium Enterprises (SMEs)
- ♦ Is a Multilateral Competition Agreement Desirable
- ♦ Globalisation Efforts: Chinese Experience
- ♦ Frequently Asked Questions on GATS Negotiations
- ♦ Frequently Asked Questions on Anti-dumping and Anti-subsidy Measures
- ♦ An Update on Current WTO Negotiations under:
 - Agriculture Sector
 - Anti-dumping Agreement
 - TRIPS and Public Health

- Services Sector
- Special & Differential Treatment Provisions
- Implementation Issues
- Dispute Settlement
- Industrial Tariffs
- ♦ Anti-dumping Proceedings by India
- ♦ WTO Secretariat Report on Anti-dumping Investigations
- ♦ WTO's Dispute Settlement Body's findings/rulings on leading cases
- ♦ Trade Policy Review of Member Countries by WTO Secretariat
- ♦ Annual Report on Overview of Developments in the International Trading Environment

Further, the post qualification course proposed to be introduced in 'International Trade Laws and World Trade Organisation' is intended to equip the members with the specialised skills necessary for developing the dedicated practice in the area of services related to International Trade Laws & WTO.

The Committee has begun work in development of the course modules and finalisation of other modalities for the early launch of the Course. The Committee is in the process of finalising the panel of experts/ resource persons for assisting in the activities of the Committee.

5.15 Committee on Insurance

The Committee on Insurance was constituted in 2001 to identify the professional opportunities for members of the Institute in the insurance sector, providing them with the focussed knowledge base through conducting insurance industry-specific courses, seminars, workshops, etc, to interact with the industry constituents viz. Insurance companies, insurance intermediaries, Insurance Regulatory and Development Authority, Government, etc., for the proliferation of the sector. The Committee concentrated, during the year, on the furtherance of its stated objectives, particularly on the formulation of strategies for the launch of the post qualification course in insurance.

5.15.1 Launch of the Post Qualification Course in Insurance and Risk Management:

The Post Qualification Course in Insurance and Risk Management (DIRM), after obtaining the acquiescence from the Insurance Regulatory and Development Authority and approval of the Government of India was launched on 19th April 2003 at Chennai. The Course embodies the elements of fundamental principles and practices having application in the insurance industry covering the life as well as general insurance segments, technical aspects adjunct therewith, constituents of risk management, and business strategic planning in varied fields constituting the insurance business viz., product formulation, marketing, distribution, reinsurance, etc., in the emerging era of globalisation, exploration of outsourcing alternative, and use of information technology in planning and configuration of information systems. The DIRM Course is envisaged to instill professional wisdom required by the insurance industry among the members in practice and those engaged otherwise, through analytical case studies focussing on the provision of lucid comprehension of the basic, technical and practical facets of the insurance business activities.

The Course, being an Industry-specific specialisation course, has received the expected response in terms of participation. Till July 2003, 1405 members have been enrolled for the Course. The region-wise fragmentation of the candidates follows:

Western	194
Southern	722
Eastern	92
Central	193
Northern	204
Total	1405

The candidates, on successful completion of the Technical Examination, would be provided with indoctrination in the form of an Orientation Course showcasing the knowledge ingredients and skills & instincts required to explore the professional avenues emerging in the insurance sector.

The Committee contemplates to explore and bring into force the more contemporary modes of study and training for the candidates, which facilitate imbibing the subjects effectively.

5.15.2 Modular Training Course for Surveyors and Loss Assessors:

The Committee on Insurance also envisages launching the Modular Training Course for Surveyors and Loss Assessors, for which the in-principle approval had been received from the Insurance Regulatory and Development Authority. During the period under report, the Committee concentrated on conceptualisation of the Modular Training Course and would come out with the Course in near future. The Course comprises the professional study and training relating to the practical and technical aspects of the insurance survey departments for which the Chartered Accountants can presently render their services. The Course would throw open ample professional opportunities for the Institute's members, as the successful completion of the Course would entitle the members to obtain the licence to act as the surveyors and loss assessors, from

the Insurance Regulatory and Development Authority.

industry, business, professionals, regulators and the society.

5.15.3 Seminars, Conferences, Workshops, etc.

The Committee has the dissemination of knowledge in insurance through seminars, conferences, workshops, etc, as one of its avowed objectives. In pursuance of the above objective, the members of the Committee actively participated in such programmes conducted by the Institute and disseminated insurance sector-specific knowledge among the members of the Institute. The dissemination was also aimed at imparting the lively sight of the indigenous and global insurance industry to the candidates for the post qualification course in Insurance and Risk Management.

The Committee also organised a Roundtable on Insurance Sector in the month of June 2003 at Hyderabad in which the Chief Executive Officers and Chief Financial Officers of the Indian insurance companies and insurance intermediaries viz., insurance brokers and third party administrators participated. The Chairman and members of the Insurance Regulatory and Development Authority and the Government officials also shared the brainstorming on varied insurance and risk management subjects in general and on Strategic Perspective on development of insurance sector, Corporate Governance issues and Audit Committees, Managing Risk in the insurance sector and Reforms in insurance sector in particular. The Committee looks forward to organising such more programmes which pave the advancement of the industry in the right regulated direction through shared thought process and facilitate the reform process by prolific contribution from all the concerned sections of the

6. INTERNATIONAL INITIATIVES

- ♦ The Institute continued to take initiatives in direction of rendering momentum to the process of building the brand image of the profession internationally. The initiatives taken by the ICAI during the year focussed upon expediting the process of establishing professional equivalence in terms of recognition of its qualification by the accountancy bodies abroad, providing strong representation of the profession at international forums like South Asian Federation of Accountants (SAFA), Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) and the International Federation of Accountants (IFAC), and strengthening the nexus of the Institute with its overseas members through its Chapters outside India with the view to empower the Indian chartered accountant community to render the professional services in diverse working environments.
- ♦ The Institute continued to ensure effective participation and significant technical contribution on matters of international significance to the accountancy profession. Shri Ashok Chandak, past President was elected as the President of SAFA during the year. The Institute was invited for the Hongkong XVI World Congress of Accountants in November 2002 and the International Auditing and Assurance Standards Board-National Standard Setters of the IFAC meeting at Paris in January 2003. An invitation has also been received to attend the International Accounting Standards Board Meeting with the World Standard Setters scheduled for September 2003.
- ♦ In the post-Enron scenario, the Institute, through the SAFA and CAPA forums, was able to project the high quality of Indian accountancy profession worldwide. The Institute's lead on the initiatives for the

overall development of the profession was recognised at global level.

- ♦ The Institute's nominees were appointed as the members of the Education Committee and the Compliance Committee of the IFAC.

- ♦ During the year, the Institute pursued vigorously with the foreign accounting bodies on the recognition of its qualification achieving the following:

- The Institute's members were given the advanced standing status by the Certified General Accountants Association of Canada (CGA). As a result thereof, the Institute's members will now have to appear only in five papers to pass the CGA examinations of Canada as against sixteen papers earlier.
- The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) also granted exemption to the members of the Institute in five out of six papers in the Professional Stage of their examination. The process of the recognition of the ICAI's students' training structure for exemption by the ICAEW is underway.
- The Institute of Chartered Accountants of New Zealand (ICANZ) has undertaken the complete review of the ICAI qualification, and is being pursued further for exemptions in their examinations to the members of the Institute.
- The members of the Institute, who are in good standing and wish to migrate to Uganda, may become the members of the Institute of Certified Public Accountants of Uganda (ICPAU).
- The Zambia Institute of Chartered Accountants has also informed that the holders of the ICAI qualification could be recognised as 'Licenciates'.
- The International Quality Appraisal Board (NASBA) of the USA had also been in the process of appraisal of the

Institute's qualification. The evaluation is in its advanced stages and the formal decision is expected soon.

- The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) and the NASBA decided to carry the evaluation of the ICAI's qualification jointly.
- The Institute also continued to pursue the matter of the recognition of the qualification of the Institute with the other foreign accountancy bodies.
- The Memorandums of Understanding were entered into with the accountancy bodies in Russia, Israel, Turkey and Egypt.
- ♦ The Institute continued to provide active advice to the Government on the implications of the GATS on the service sector in general and on accountancy profession in particular. The Institute participated in the bilateral meetings for negotiations on Request and Offers alongwith the Special Session of the Council for Trade in Services held in May 2003 at Geneva.
- ♦ The concerns in respect of the needs of the Small and Medium Practitioners (SMPs) in the accountancy profession were placed before the SMP Task Force of the IFAC and the Intergovernmental Working Group of Experts of the International Standards of Accounting and Reporting (ISAR) on SMEs, and the Institute played active role in suggesting best practices in accounting for SMEs.
- ♦ The Institute has also made a proposal to hold an IT Forum in India under the auspices of the IFAC.
- ♦ The initiatives were taken to organise localised international conferences and students' exchange programs for the accounting bodies in South Asian region. A series of programmes was organised by the Institute in association with the Institute of

Chartered Accountants of Sri Lanka and the Institute of Chartered Accountants of Nepal.

- ♦ The Institute opened a Chapter in Indonesia and explored the possibility of opening up of more chapters particularly in Canada and the USA. The Institute took proactive measures for encouraging the participation and interest of members abroad into its activities.
- ♦ The MOU was signed between CICPA (China) and ICAI in January 2002, which was further strengthened by a MOU entered into between the two Institutes in January 2003. In pursuance thereof, exchange of technical documentation took place with the Chinese Institute on issues having relation to the Interpretation, applicability and enforcement of the accounting and auditing standards prescribed by them. The visit of the Indian delegation, however, could not take place due to SARS problem in the host country.
- ♦ The ICAI delegation met H.E. Sheikh Nahyan, Minister of Higher Education and Scientific Research of the UAE when he had expressed his willingness to consider the prospects of the UAE Government entering into a technical co-operation agreement with the Institute to set up an Institute of Chartered Accountants of UAE.
- ♦ The first ever SAFA tele-conferencing was organised by the Institute in April 2003.
- ♦ A meeting of the CAPA Executive Committee (Ex-Com) has been scheduled to be organised in India in November 2003.
- ♦ The Institute would host the IFAC Board meeting proposed to be held in March 2004. On this occasion, an Ex-Com meeting of the CAPA and an Assembly meeting of SAFA are also being contemplated.

7. ICAI - VISION FOR 21ST CENTURY

The fast changing economic scenario worldwide, in the last decade of 20th Century created a need for revisiting the accounting

profession and the Institute for repositioning as a highly valued trustee and address the various concerns and expectations of regulators, industry, public at large amongst plethora of stakeholders.

The Council of the Institute had earlier constituted a Committee for formulating the Vision and Restructuring the profession. The draft responsibilities/vision statement was shared with the members at large and other stakeholders and brainstorming strategies were screened through the views and opinions received from all the stakeholders. While such strategies were being formulated, it was considered appropriate that translation of these strategies need actionable points for being helpful in the implementation phase.

The Report of the Committee on Vision and Restructuring titled "ICAI - Vision for 21st Century" was released at august hands of Hon'ble Shri Sharad Yadav, Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution on 5th January, 2003 during the valediction of 15th All India Conference of Chartered Accountants held at New Delhi. The Report eloquently deals with the Vision of the Institute and expectations of stakeholders in the 21st Century and, inter alia, deals with the need to evolve suitable combat strategies at the member level, firm level and the level of the Institute and profession and more so on the contemporary and emerging trends in the context of emerging trade order.

8. OTHER ACTIVITIES

8.1 Human Resource Development

8.1.1 HRD Training Programme

The Institute organised training programmes on following areas to cater to the requirements in view of changing pattern of members and students of the Institute regarding services offered :

- (i) Management Development Programme/
Development Programme for officers and staff of

the Institute dealing with various aspects of human approach such as striving for excellence, managing stress, inter-personal relations, team work, synergy in decision making, defensive and supportive communication etc.

- (ii) Programme on yoga therapy for all officers and staff dealing with yoga in daily routine, solutions for body problems and stress management.
- (iii) Programme for newly recruited officers dealing with overall view of the organisation and functioning of the Institute.
- (iv) Workshop on Organisational Excellence for senior Officers.
- (v) Regular computer courses including on Virtual Institute Project (VIP).

Thus, the regular HR training programmes including computer courses on VIP and others were held spanning more than 8200 man-hours at the headquarter and regional levels.

8.1.2 Human resources-welfare measures

The Institute considers that the Human Resources are the most important assets for achieving the goals of the organisation. It granted various welfare schemes for its employees such as revision of education allowances and ex-gratia payment, enhancement of subsidy for organising social get-togethers etc.

8.2 Use of Information Technology in Member's and Student's Services

The Institute has been using Information Technology (IT) effectively for its day-to-day operations for over a decade. In keeping with the premier nature of the Institute and considering the span of its regulatory and

promotional operations, it proposes to migrate its legacy from, distributed applications to a centralized Virtual Institute System. Accordingly, it has drawn up a comprehensive plan incorporating this vision into its IT road map. Hence, a suitable development initiative has started to implement the Virtual Institute Project (VIP) with a view to continue the process of technology upgradation in tune with changes in the business and technological environment.

8.2.1 Virtual Institute Project

The VIP, which was initiated during last year, is in its advanced stage of implementation. The system design based on user requirements has been completed and the project is under development/testing stage. VIP will integrate the Institute's operations spanning offices in India in a seamless mode and ensure online data access across the Institute's Offices. Business processes are reviewed and refined along with the VIP. It is expected to address consolidation issues as well.

The system will move the Institute towards a Home Institute and make the services available at the doorstep of members and students.

The VIP is expected to bring a paradigm shift in the functioning of the Institute by way of providing right information to right person (Member, Student, Institute Official) at the doorstep. The concept of the project is similar to Home Banking, Anywhere/Anytime Banking. The Project will achieve Home Institute, Anywhere/Anytime Institute with 7 X 24 X 365 services. It will enable the Institute to move towards paperless office with concepts such as Electronic Filing, Payment Gateway with online service facilities to Members and Students.

8.3 All India Conference of Chartered Accountants

The Institute organised its 15th All India Conference of Chartered Accountants on the Theme "Accountancy – Diverse Demands; Disciplined Approach" at New Delhi from 3rd – 5th January, 2003. While the Conference was named as the All India Conference, it veritably was an International Conference with heads of SAFA Member bodies from Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh participating at the Conference, in addition to delegation from the Chinese Institute of Certified Public Accountants. The Conference was a historic event in itself, as Sir David Tweedle, Chairman International Accounting Standards Board and Mr. Rene Ricol, President, International Federation of Accountants also addressed the august gathering much to professional enrichment of members of the fraternity.

The Conference was inaugurated on 3rd January, 2003 at Vigyan Bhawan by Hon'ble Shri Jaswant Singh, Union Minister of Finance and Company Affairs and was witness to an august gathering throughout the span of 3 days wherein persons of eminence like Shri Suresh Prabhu, Member of Parliament (Former Union Minister of Power), Hon'ble Shri Anandrao V Adsul, Union Minister of State for Finance, Shri Arun Jaitley, Former Union Minister of Law, Justice and Company Affairs, Shri Manishankar Iyer, Member of Parliament shared their words of wisdom with the participants. The Conference also saw galaxy of renowned authorities/experts including Chairman, SEBI, Chairman, IRDA, Secretary, Department of Company Affairs and other experts addressing and giving thought provoking issues for the development of profession. The Conference ended with valediction by Hon'ble Shri Sharad Yadav, Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution wherein the Report titled "ICAI - Vision for 21st Century" was also unveiled by the Hon'ble Minister.

It was a momentous occasion for the Chartered Accountancy profession and the Institute, as the Conference was held after a gap of about 6 years; and enabled the gathering to take stock

of prevailing socio-economic conditions of the country and the possible contribution of Chartered Accountants thereto. The Conference had lively participation on issues of contemporary significance such as crisis of corporate governance, realities of economic reforms for Chartered Accountants, re-visiting the relationship between the Accountant and the society, financial sector and issues and opportunities relating to Taxation and Corporate Laws. Not only these were lively and livid on account of their technical content; it had its extravagant moments as well when as a part of Conference package; the delegates had enthralling evening at the "Usha Mangeshkar Nite" on the 2nd Evening of the Conference.

The Conference was attended by over 1300 delegates with International delegations/participation from 9 countries and was well covered by the print media and actively participated by the corporate sectors in terms of Corporate/Public Sector delegates/sponsorship. The Conference had a mesmerizing and indelible effect on the Chartered Accountants fraternity.

8.4 Audit Committee

The Audit Committee was constituted by the Council in the year 2001-2002 with its avowed objectives, among others, of over-viewing the Institute's reporting process and disclosure practices in respect of financial information to ensure the true and fair nature thereof, reviewing the annual financial statements before submission thereof to the Council focussing primarily on the adherence to the accounting policies, compliance with accounting standards and applicable legal requirements, and reconciliation, etc., weighing the adequacy of internal control systems and efficacy of the data security, integrity, and financial & risk management policies.

The Committee continued to function within the framework of its terms of reference. The Committee reviewed, during the year, the accounting policies in respect of charge of depreciation on certain fixed assets and

allocation of entrance fee and admission fee received from the applicants for the associate and fellow membership of the Institute, into income and reserves. The Committee also recommended the presentation of the Institute's Income and Expenditure Account in a revised format to ensure the fairer exhibition of the activity based operational results.

The Committee placed greater emphasis on the compliance with the prudent and propriety-oriented governance procedures underlying the functioning of the Institute and its arms and for the purpose, it facilitated the pre-audit and post-audit reasoned discussion of the Institute's auditors with the management. Measures were also implemented to ensure the prolific contribution of the audit committees functioning at regional level in the Institute.

The Committee has, during the current year, committed itself to function in pursuance of its Action Plan for the year 2003-2004 and met at Institute's various office locations to take a view of their activities and recommend system improvement measures to enhance operational efficiency thereof and act as an invariably independent mechanism to facilitate the recognition and addressal to the system control issues including those in relation to information, integrity and security.

8.5 Financial Reporting Review Board

8.5.1 The Council of the Institute constituted the Financial Reporting Review Board as one of its non-Standing Committees in July 2002.

8.5.2 The Board comprises seven members of the Council of the Institute, of which two are nominees of the Central Government.

8.5.3 The Board would also consider seeking co-options from certain regulators. The presence of representatives of the regulators would be advantageous for the efficient and effective functioning of the Board. The envisaged composition would facilitate

the Board to obtain information about the companies and take follow-up action against the erring ones.

8.5.4 During the period under report, the Board finalised its Terms of Reference as under :

- (i) It would review the general purpose financial statements of certain enterprises with a view to determine, to the extent possible:
 - (a) compliance with the generally accepted accounting principles in the preparation and presentation of financial statements;
 - (b) compliance with the disclosure requirements prescribed by regulatory bodies, statutes and rules and regulations relevant to the enterprise; and
 - (c) compliance with the reporting obligations of the enterprise as well as the auditor.
- (ii) It may review the general purpose financial statements either *suo motu* or on a reference made to it by any regulatory body like, RBI, SEBI, IRDA, DCA, etc. It may also review general purpose financial statements of enterprises relating to which serious accounting irregularities in the general purpose financial statements have been highlighted by the media reports.
- (iii) Findings of the Board relating to non-compliance with the factors stated at paragraph (i) above would form the basis for initiating action against the auditor concerned under the Chartered Accountants Act, 1949. In so far as the management of the enterprise is concerned, pending the grant of relevant powers to the Board by the Central Government, the Board would inform irregularity to the regulatory

body relevant to the enterprise and would also communicate the same to the management.

(iv) The enterprises within the purview of the FRRB include:

(a) enterprises whose debt or equity securities are listed on a recognised stock exchange in India;

(b) public financial institutions and banks;

(c) non-listed and other commercial enterprises having a turnover of Rs. 50 crores or more; and

(d) such other category of enterprises which in the opinion of the Board make the public interest vulnerable due to susceptibility to non-compliance of generally accepted accounting principles in the preparation and presentation of financial statements, non-compliance of the disclosure requirements prescribed by regulatory bodies, statutes and rules and regulations relevant to the enterprise and non-compliance of the reporting obligations of the enterprise and the auditor.

(v) There could be accounting and auditing issues that may require a clarification. The Board does not have any power to issue such clarifications. However, if the Board is of the opinion that the issue may require a clarification, it may refer the issue to the appropriate Committee of the Council for consideration.

3.5.5 The Board is also in the process of finalising the detailed operating procedures to be followed in the conduct of reviews of general purpose financial statements. As soon as the

operating procedures are finalised, the Board would commence its reviews for the financial statements for year ending 31st March 2003.

8.5.6 Certain reviews based upon irregularities in the financial statements of some enterprises as pointed out by print media are also being taken up. Apart from this, the Board has also sought the general purpose financial statements of the top 500 companies in India, including those in banking, insurance, mutual funds and electricity business for the financial year ending 31st March 2003.

8.6 Committee for Review of Education and Training (CRET)

As part of the continuous policy of 'care and maintenance' approach to Education and Training, the Committee for Review of Education and Training (CRET) was constituted in May 2003.

The first meeting of the Committee was held on 15th July 2003. The Committee, inter alia, finalised the following terms of reference for consideration and approval by the Council :

- ♦ To review the existing system of education and training for membership of the Institute in order to determine and ensure its relevance and adequacy in the context of the changing environment and demands on the profession.
- ♦ To consider and adopt appropriate measures to ensure that the system meets the benchmarks and other prescriptions embodied in the International Education Standards, with reference to pre-qualification as well as post-qualification developed by International bodies such as the Education Committee of the IFAC.
- ♦ To review the existing curriculum in order to consider and adopt appropriate changes in the contents of Professional Education Programs for students.

- ♦ To consider and adopt measures to gain increasing international recognition, acceptance and application of existing education and training process and Mutual Recognition Agreements.
- ♦ To consider issues concerning Continuing Professional Education and Development for Members (including post-membership examinations).
- ♦ To consider such other matters arising from the foregoing as the Committee may determine.

The Committee also deliberated upon its broad aims and objectives and decided to adopt a multi-pronged strategy to review the present system of Education and Training. It would include, inter alia, an elaborate consultative process involving issue of specially designed questionnaires for members, students, users of services, academicians, through web-site, and other means, analysis of the responses received, setting up of separate study groups to consider different aspects of the Education and Training such as entry requirements, practical training, theoretical education and related aspects and post-qualification examinations, dialogue with selected persons and study of international trends in professional accounting education with particular reference to pronouncements of the International bodies like the Education Committee of IFAC, syllabi of leading professional accounting bodies of the world and other relevant centres of higher learning.

9. OTHER MATTERS

9.1 Annual Function of the ICAI

The 53rd Annual Function of the ICAI was held on 4th February, 2003 at Ashok Hotel, New Delhi. Hon'ble Shri Ramesh Bais, Union Minister of State for Mines was the Chief Guest. Shields and Plaques to the winners of the Institute's prestigious awards for the Best Presented Accounts and prizes and medals to the meritorious students in the examinations conducted by the Institute, shields and certificates of appreciation to the outstanding

Regional Council and Branches of the Institute, were awarded. The function was attended by a very large number of invitees including senior Government Officers, members, students, officers and staff of the ICAI. The Chief Guest showered flowers of appreciation on the profession of Chartered Accountants.

9.2 Chartered Accountants' Day

In commemoration of the Chartered Accountants Day, a function was organised on 5th July, 2003 at Ashok Hotel, New Delhi. Hon'ble Dr. Bimal Jalan, the then Governor, Reserve Bank of India delivered special address on 'Reforms in Financial Sector – Way Forward'. The Function was well attended by the membership at large. Besides this, the Branches at various places also organised the Function locally in a befitting manner.

9.3 Amendments in The Chartered Accountants Act, 1949 and The Chartered Accountants Regulations, 1988

A. Amendments in The Chartered Accountants Act, 1949

The Council of the ICAI at its meeting held in July, 2002 considered the recommendations of the Working Group constituted for review the amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 and the regulations framed thereunder. The Council finalised its recommendations on the amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 for consideration of the Central Government. The draft amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 as finalised by the Council of the ICAI have been submitted to the Central Government on 3rd August, 2002. The said amendments are under the active consideration of the Central Government.

B. Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

(i) Amendments approved by the Central Government

During the year under report, the Central Government accorded its final approval to

certain amendments in Regulation 204 by way of introduction of the following new post qualification course :

- ♦ Post Qualification Course in Insurance & Risk Management

(ii) Amendments proposed

The Council of the Institute approved the increased rates of stipend payable to articled clerks registering after passing Professional Education (Examination II) and completing 250 hours of Computer Training. The amendments in this behalf have been proposed in Regulation 43 to the Central Government. The other amendments proposed earlier in Schedules 'C', 'D' and 'E' seeking power with the Council to fix various fees and decide about the syllabus for these Courses are under consideration of the Government and the same after its in-principle approval would be notified for public comments.

9.4 Past Presidents' Meet

Encouraged by the overwhelming response received to the Past Presidents' Meet last year, it was felt to continue such meetings, to the extent possible, during the year also. Accordingly, meetings between the President, the Vice-President & Secretary and the past Presidents of the Institute/past Chairmen of the Regional Councils were held at Kolkata, Mumbai and Chennai on 27th March, 2003, 17th April, 2003 and 18th April, 2003 respectively. At the said meetings, invaluable inputs were received on matters of professional importance in general and on—(i) new avenues for professional development; (ii) strategies for strengthening small and medium practitioners (SMPs); (iii) positioning the Institute in the post Enron scenario; (iv) making the profession ready for global competitiveness and opportunities; and (v) other issue(s) concerning the regulation and development of the profession in particular.

9.5 Central Council Library

The Central Council Library provides Books, Journals, Newspapers and Reference facilities to Members, Students and Faculties of different Directorates of the Institute, alongwith a list of Articles compiled from various Professional Journals and Newspapers, a list of which is published every month in the Institute's Journal under the title Reference - "Accountant's Browser". Reference service is also provided to the Researchers and Foundation Course Students as a special case. Noida office of the Institute, has also been provided with Library facilities by the Central Council Library. Nucleus Libraries have also been provided to different Directorates at Headquarters. Networking through Delnet, a Network of Libraries in India and abroad is operational and the computerisation of Library material including Books, Journals, Articles Members record is available on Enquiry & Webmodule. A strong base of more than 10,000 articles including articles from ICAI Journal "The Chartered Accountant" is also available in Library Software. Besides the above, an appropriate version of LAN is in place providing the most reliable and empowered corporate database of 8000 companies. The database provides financial statements ratio analysis, fundsflows, product profiles, return & risks on the stock markets etc.

Besides the above, Library facilities are also provided at the regional centres and branches throughout the country. Efforts are on to link different Regional Libraries with Central Council Library Database after computerising these Libraries. Liberal Grants are provided to associations and study circles recognised by the Institute for development of the Libraries. The Council has taken a decision to provide special grants for strengthening Library facilities available at all Regional Councils and their Branches.

9.6 Editorial Board

The Editorial Board is continuously striving to fulfil its mission i.e., to convey regularly to the members professional knowledge, matters of

interest to professionals, matters relating to ICAI and its activities and such other matters as are deemed to be of educational/professional value through the Journal 'The Chartered Accountant'. The Journal continues to focus on developing the core competencies of the members in various areas. Renowned experts in the concerned areas have contributed columns on contemporary topics.

The Journal continued to maintain high professional standards and was well received throughout the period of the report, with its monthly circulation figure reaching to the 1,50,000 copies mark. Now the journal is increasingly being read by various institutions and persons related to accounting and allied professions, for example, universities/colleges, libraries and various organizations/ corporates, who are subscribing the Journal.

During the period under report, following were the significant activities of the Editorial Board:

- Publication of the Journal on the following themes:
 - Information Security Audit
 - Insurance Industry
 - VAT
- On the occasion of the Chartered Accountants' Day i.e., 1st July 2003, a special issue was brought out. Eminent personalities from diverse fields contributed their articles in this issue along with some internationally renowned experts.
- Publishing of a regular column on the 'Professional Opportunities' available to Chartered Accountants since April 2003.
- Publishing of a series of articles on 'Code of Ethics' since April 2003.
- Publication of various Government Circulars and Notifications.

The Editorial Board continues to take appropriate measures to improve the overall quality of the Journal so as to make it more

appealing not only among the members and students of the Institute but also others concerned with the accounting profession.

10. MEMBERS

10.1 Membership

During the year ended 31st March, 2003, 9177 new members were enrolled by the Institute bringing the total membership to 1,10,256 as on 1st April, 2003.

During the year ended 31st March, 2003, 2866 associates were admitted as fellows, compared to the figure of 2486 in the previous year.

Statistics of Members as on 1.4.2003

Category of Members	Associates	Fellows	Total of Column
	(1)	(2)	(1) + (2)
Holding COP	44512	30887	75399
Others	5125	29732	34857
Total	49637	60619	110256

10.2 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants' Benevolent Fund continues to provide financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institute and their dependents, for maintenance of the dependents, their educational and medical needs etc. The number of life members of the fund increased from 31370 as on 31st March, 2002 to 47752 as on 31st March, 2003. The financial particulars of the Fund are as follows :

	During the year ended 31.3.2002	During the year ended 31.3.2003
Total Assistance provided	26,97,200	34,50,500
Administrative Expenses	1,05,251	1,45,898
Surplus (Deficit) of the Fund	(3,91,944)	1,23,42,341
Balance of the Fund	22,33,335	1,45,75,676
Balance of Corpus	1,82,38,500	3,42,50,000

11. STUDENTS

11.1 New Scheme of Education & Training

The New Scheme of Education and Training introduced with effect from 1st October, 2001 successfully covered yet another milestone with the first batch of the students of Professional Education Course-I and Course II as well as the students of Final Course (New Syllabus) taking their Examinations in November, 2002.

As part of the new scheme the following steps were also taken:

11.1.1 Details of the Theoretical Education scheme for the Final (New Syllabus) students were finalised and circulated to the Regional Councils and Branches. Steps have been taken to give effect to the scheme.

11.1.2 Finalisation of the details of 15 days Course on General Management and Communication Skills, which students who have completed their practical training, have to undergo before applying for Membership of the Institute. The Course was conducted at all the five regional headquarters, for the benefit of students who passed the November, 2002 Final Examination under the new scheme. Subsequent to the declaration of results of the Final Examination held in May, 2003, the Course was conducted at the Regional headquarters as well as at several branches of the Regional Councils. The course will be conducted at periodic intervals at Regional Headquarters and Branches.

11.1.3 Compulsory Computer Training Course for 250 Hours : The Scheme for Compulsory Computer Training for 250 hours, prior to registration for practical training, has been implemented. In addition to certain leading Computer Training Institutions operating on a nation-wide basis specifically accredited

for this purpose – NIIT, APTECH, SSI, First Computers – the training is being imparted by Computer Training Centres of the certain Regional Offices and Branches as well as certain institutions already accredited for oral coaching classes for Professional Education (Courses I & II) and having the necessary infrastructural and other facilities. As on date, accreditation has been granted to Computer Centres of 2 Regional Councils, 3 Branches of Regional Councils and 5 accredited institutions for this purpose. The uniform course material for the 250 hours Compulsory Computer Training Programme has been released in three modules. The Board has recently reviewed the operation of the scheme based on the feedback received from the students and finalised guidelines for accreditation of more institutions operating at Regional and local levels.

11.2 Students' Services

11.2.1 The supply of comprehensive study materials covering the various subjects in the curriculum is continued. In addition, a separate supplementary study material containing typical problems and solutions for the subject of Management Accounting and Financial Analysis was released for the benefit of Final students. A free supplementary study material on amendments made by the Finance Act, 2001 was also released.

11.2.2 A booklet on Residential Status and Tax implications has been released to serve as a supplementary study material for the benefit of students.

11.2.3 A compilation of questions and answers in the subject of Business and Corporate Laws for PE-II students has been released.

11.2.4 Revision Test Papers and their answers for the Foundation/Intermediate under the

earlier scheme and New PE-I, PE-II and Final (New Syllabus) have been released.

11.2.5 Arrangements have been finalised with a private publisher, for the translation, printing and distribution of Final Study materials in Hindi. The Final Course (Group-I) study material in Hindi will be released shortly and the study material for Group-II will follow thereafter.

11.2.6 The suggested answers volumes for the questions set at the Foundation/Intermediate/Final Examination held in May, 2002 and as well as Foundation/Intermediate/Final of the old course and PE-I/PE-II and Final of the new course held in November, 2002 were released.

11.2.7 It has been decided to make Sunday Tests compulsory at all places where there are Branches as well as Examination centres. Steps are being taken to implement the same soon.

11.2.8 Free counselling services have been introduced at the Regional Offices to help the students for removing their doubts and difficulties relating to different subjects in their curriculum, arising during the course of their preparation for Examinations.

11.2.9 A consultative group of faculty members of the Board has been constituted to provide on-line help to students pursuing professional education and final course by replying to their academic queries.

1.3 Training Guide and Code of Conduct

The Training Guide brought out in 1994 has been thoroughly revised having regard to the requirements of the new scheme of Education and Training and with a view to ensuring that the articled/audit trainees received a well-structured and systematic training. The revised Training Guide includes, inter

alia, revised formats of training records/Report of Practical/Industrial Training. The revised Training Guide is effective from 1st January, 2003.

A Code of Conduct for Chartered Accountancy students has been released. The Code seeks to govern the conduct of articled/audit trainees during the period of their practical training as well as students pursuing Professional Education Course prior to registration for practical training.

11.4 Self-Development Booklet Series

Self-development booklets on selected topics like "Time and Stress Management", and "Skills for General Correspondence" were brought out during the year.

11.5 Students' Statistics

11.5.1 The total number of students enrolled for the PE-I, PE-II and Final Course during the year ended 31st March, 2002 and 31st March, 2003 are as under :

Course	2002-2003	2001-2002
PE-I	35524	5006 (1.10.2001 to 31.3.2002)
PE-II	24786	11848 (1.10.2001 to 31.3.2002)
PE-II with articles	8497	17555
FINAL	11102	11524

11.5.2 The total number of students on the rolls of the Board of Studies as on 31st March, 2003 (excluding those students who are registered for Professional Education Course I) was 2,80,399 as against 2,58,995 (2,47,147 + 11,848 students

registered for Professional Education Course II) as on 31st March, 2002.

11.6 Accreditation Scheme

During the year ended 31st March, 2003 accreditation was granted to 70 Institutions (including 1 Regional Council and 8 Branches) for organising the classes for students of PE (Course-I) and 44 Institutions (including 1 Regional Council and 6 Branches) for PE (Course-II). As on date, the total number of accredited Institutions for PE (Course-I) is 70 and PE (Course- II) is 44. 14 Institutions organised classes for the benefit of PE (Course- I) students for November 2002 Examinations and 66 Institutions for May, 2003 Examinations. 10 Institutions organised classes for the PE (Course- II) students for November, 2002 Examinations and 24 Institutions for May, 2003 Examinations.

Accreditation has been granted to an overseas Institution in Dubai for the purpose of organizing Oral Coaching Classes for the benefit of students preparing for PE (Course I).

11.7 Seminars and Conferences

11.7.1 The 15th All India C.A. Students' Conference was held on 29th & 30th November, 2002 at Kolkata with the theme "Excellence Through Value Based Knowledge". 742 students from all parts of the country attended the Conference. The Conference was addressed by eminent personalities and professionals. 17 Technical Papers on 11 selected topics contributed by the students were discussed in the four technical sessions.

11.7.2 During the year under report, the Board continued its policy of promoting organisation of one-day Seminars, Elocution/Quiz Contests and Regional/State Level Conferences.

(i) 10 Branches organised one-day Seminars as per the guidelines of the Board. The Northern India Regional Council organised a one-day Seminar on 6th October, 2002 which was attended by 738 students.

(ii) The Indore Branch of the CICASA organised a half-day Seminar on 5th December, 2002.

(iii) The Calicut Branch of SICASA conducted All Kerala Students' Conference on 21st December, 2002.

(iv) The Eastern India C.A. Students' Conference took place on 6th July, 2002 at Kolkata.

(v) The Aurangabad Branch of WICASA organised two-day Regional Conference on 20th & 21st December, 2002.

(vi) The Southern India Chartered Accountants' Association organised a two-day Regional level Conference on 4th & 5th January 2003 at Bangalore.

(vii) The 6th Central India C.A. Students' Conference took place at Raipur on 13th & 14th July, 2002.

(viii) The Kottayam Branch of SIRC organised a two-day Students' Conference on 6th & 7th July, 2002.

(ix) The 8th All India Elocution Contest and 2nd All India Quiz Contest were held on 8th January 2003 at Ernakulam. During the year, 19 Branches including 5 Regional Councils organised Elocution Contest at Branch and Regional levels and 20 Branches including 5 Regions organised Quiz Contest at the Branch and Regional levels. Winners from Regional Level Contests participated in the Final Contest.

- (x) A Sub-Regional Conference of Western India Students was organized in Goa on 26th to 28th June, 2003.

- (xi) The Ernakulam Branch of SICASA and the Ernakulam Branch of SIRC organized a two-day All Kerala C.A. Students' Conference at Ernakulam on 4th and 5th July 2003.

- (xii) The Calicut Branch of SICASA also organized a one-day All Kerala Students' Conference on 12th July 2003 at Calicut, with the theme 'Striving Ahead, towards epitome'.

- (xiii) The Eastern India Chartered Accountants' Students' Association and the EIRC organized a one-day Eastern India C.A. Students' Conference, with the theme 'Education and Value Addition' on 13th July 2003 at Kolkata.

11.7.3. The 16th All India C.A. Students' Conference with its theme "Expanding the Horizons of Knowledge, Skills and Values" was held in Chennai on 20th and 21st June, 2003. A record number of 1550 delegates from different parts of the country including 9 students from the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka participated in the Conference. The Conference was addressed by eminent personalities and professionals.

23 technical papers contributed by the students on 12 topics selected from the areas of accounting and auditing, corporate laws, direct and indirect tax laws, professional ethics were discussed in the four technical sessions. There were also special sessions on 'Body, Mind and

Intellect', 'Approach to Examinations' and 'Health and Humour'.

11.8 Scholarships

During the year ended 31st March, 2003, Scholarships were granted to 145 students out of the funds of the Institute (8 Merit-cum-Need based scholarships, 37 Merit Scholarships, 100 Need-based scholarships). Further, scholarships were awarded to 43 students out of the income from various endowments set up for the purpose.

11.9 Students' Newsletter

The monthly C.A. students' newsletter – 'The Chartered Accountant Student' containing useful articles, academic updates, write-ups and other relevant announcements continued to prove useful to the students. The publication proved to be popular among the students as well as members.

The first prize (Rs.2000/-) for the best article in Volume V was awarded to Shri Vijay P. Mandloi for his article on 'Avenues of Investment' published in November, 2001 issue.

The second prize (Rs.1000/-) was awarded to Ms. Neha Mehta for her article 'Tips to Improve Studying Process' published in Baroda Branch of WICASA's Newsletter Volume No.11-2002.

11.10 Student Exchange Programme

Pursuant to the decision taken by the SAFA Committee on Education, Examination, Training and CPE, a Student Exchange programme with Sri Lanka was organised in June, 2002. A nine member student delegation from Sri Lanka participated in the 16th All India CA Students' Conference held in Chennai on 20th and 21st June, 2002 and also visited a few firms of Chartered

Accountants, Industrial organisations like Infosys and HAL and certain other places of interest.

A similar delegation of 10 Indian students will also be visiting Sri Lanka during 27th August to 7th September, 2003 and be participating in their Students' Conference and other students events and also visit firms of Chartered Accountants.

11.11 Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involve students of the Chartered Accountancy Course in the development of a spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the Council of the Institute has always been encouraging students to set up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, so far 34 branches of Students' Association have already been set up.

11.12 S. Valdyanath Aiyar Memorial Fund

During the year ended 31st March, 2003, 60 scholarships of the value of Rs. 200 each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy course. The membership of the Fund was 340 as on 31st March, 2003 as against 324 as on 31st March, 2002. The balance in the credit of the Fund was Rs. 4,69,857/- as on 31st March, 2003 as against Rs. 4,89,829/- as on 31st March, 2002.

11.13 Recognition of CA Course for Ph. D. Programme

With constant follow-up with various Universities, the Committee on Commerce Education & Career Counselling has been successful in obtaining recognition for CA Course from 73 Universities besides the 3

Indian Institutes of Management and the Association of Indian Universities for the purpose of PHD/Fellow Programme.

12. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

12.1 The Institute has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively.

12.1.1 The total number of branches of Regional Councils is 97.

12.1.2 Currently, there are 11 Chapters of the Institute outside India.

12.1.3 During the year under report, one new reference library has been set up at Bundelkhand. With this, 38 reference libraries have been set up all over the country.

12.2 Branch Building

During the period under report, a number of branches of Regional Councils continued to evince interest in having their own premises. In all, 50 branches have their own premises.

12.3 Rotating Shield

Since 1986-87, the Institute awards each year Rotating Shield to the Best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance. Similarly, a separate Rotating Shield is awarded to the Best Branch each year. The award is given on the basis of established norms. Rotating Shields to the Best C.A. Students' Association on all India basis and Best Branch of Students' Association on Regional basis have been instituted from the year 1999. For the year 2002, these shields were awarded at the Annual Function held on 4th February, 2003 to the following winners:-

1. Best Regional Council - Western India Regional Council
2. Best Branch of Regional Council - Jointly to Nagpur Branch of Western India Regional Council and Bangalore Branch of Southern India Regional Council
3. Best Students' Association - Western India Chartered Accountants Students' Association
4. Best Branch of Students' Association
 - Western Region - Baroda Branch of WICASA
 - Southern Region - Ernakulam Branch of SICASA
 - Central Region - Raipur Branch of CICASA

Considering their good performance, the following branches were separately awarded certificates for highly commended performance:-

- (i) Baroda Branch of Western India Regional Council
- (ii) Belgaum Branch of Southern India Regional Council
- (iii) Raipur Branch of Central India Regional Council

12.4 New Decentralised Offices

Considering the increasing volume of work/activities at the regional level and recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of the Institute has already set up five more decentralised Office at Bangalore, Hyderabad in Southern Region, Ahmedabad, Pune in Western Region and Jaipur in Central Region besides the decentralised offices already functioning from Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi and new initiatives have been recently taken by the Council to make them more effective and useful.

13. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2003 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

14. APPRECIATION

14.1 The Council is grateful to all members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees and to the non-members who assisted the Council during the year 2002-2003 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

14.2 The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2002-2003.

14.3 The Council wishes to place on records its heartfelt gratitude to His Excellency the Vice-President of India, Shri Bhairon Singh Shekhawat. The Council also expresses its deep sense of gratitude to Hon'ble S/Shri Jaswant Singh, Sharad Yadav, Suresh Prabhu, Arun Jaitley, Vijay Goel, Rajiv Pratap Rudy, Anandrao V. Adsul, Ramesh Bais who were kind enough to grace the various programmes of the Institute as Members of Council of Union Ministers or otherwise at the relevant time. The Council also desires to place on records its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced the programmes organised by the organs of the Institute.

14.4 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/being initiated by them, pursuant to such initiatives.

14.5 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2002-2003 by all officers and staff of the Institute.

STATISTICS OF MEMBERS (FROM 1.4.1997)**TABLE I**

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1.4.1997	Associate	14649	11013	4906	3972	6971	41511
	Fellow	11042	8975	4369	4560	8049	36995
	Total	25691	19988	9275	8532	15020	78506
1.4.1998	Associate	16160	11564	5187	4351	7406	44668
	Fellow	11501	9420	4558	4909	8733	39121
	Total	27661	20984	9745	9260	16139	83789
1.4.1999	Associate	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	Fellow	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	Total	29968	22457	10341	10220	17375	90366
1.4.2000	Associate	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	Fellow	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	Total	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1.4.2001	Associate	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	Fellow	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	Total	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1.4.2002	Associate	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	Fellow	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	Total	34311	24704	11168	11893	19654	101730

STATISTICS OF MEMBERS (FROM 1.4.1950)**TABLE II**

	As on 1.4.1950	As on 1.4.1951	As on 1.4.1961	As on 1.4.1971	As on 1.4.1981	As on 1.4.1991	As on 1.4.2001
Fellows	569	672	1,590	3,326	8,642	22,136	44,789
Associates	1,120	1,285	4,059	7,901	16,796	36,862	51,603
Total	1,689	1,957	5,649	11,227	25,438	58,998	96,392

STUDENTS REGISTRATION GROWTH PROFILE (FROM 31.3.1996)

	As on 31.3.96	As on 31.3.97	As on 31.3.98	As on 31.3.99	As on 31.3.2000	As on 31.3.2001	As on 31.3.2002
Foundation/ PE (Course I)	29,015	28,209	37,052	43,809	44,180	35,999	34,215*
Intermediate /PE (Course II)	19,288	21,354	24,652	28,253	27,508	23,405	29,403**
Final	8,675	9,275	9,394	12,227	10,787	9,026	11,524
Total	56,978	58,838	71,098	84,289	82,475	68,430	75,142

* includes PE(Course I) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 5006

** includes PE(Course II) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 11848

	As on 31.3.2003
PE (Course I)	35524
PE (Course II)	24786
PE (Course II) with Articles	8497
Final	11102
Total	79909

COMPOSITION OF EIGHTEENTH COUNCIL (2003 – 2004)**PRESIDENT**

Shri R. Bupathy, FCA

VICE-PRESIDENT

Shri Sunil Goyal, FCA

PERIOD5th February, 2003 onwards**SECRETARY**

Dr. Ashok Haldia

MEMBERS OF THE EIGHTEENTH COUNCIL (2003 – 2004)**ELECTED MEMBERS:**

Shri Abhijit Bandyopadhyay	Kolkata
Shri Amarjit Chopra	New Delhi
Shri Ashok Chandak	Nagpur
Smt. Bhavna G. Doshi	Mumbai
Shri Gopal Prasad Dokania	Kolkata
Shri J. P. Gokhale	Mumbai
Shri K.S. Vikamsey	Mumbai
Shri Manoj Fadnis	Indore
Shri N. Nityananda	Bangalore
Shri N.D. Gupta	New Delhi
Shri N.V. Iyer	Mumbai
Shri Niranjan Saha	Kolkata
Shri P.P. Pareek	Jaipur
Shri Pankaj Inderchand Jain	Mumbai
Shri R. Bupathy	Chennai
Shri R.S. Adukia	Mumbai
Shri S. Gopalakrishnan	Hyderabad
Shri S. Santhanakrishnan	Chennai
Shri S.H. Talati	Ahmedabad
Shri Shantilal Daga	Hyderabad
Shri Sunil Goyal	Jaipur
Dr. Sunil Gulati	New Delhi
Shri T.N. Manoharan	Chennai
Shri Vinod Jain	New Delhi

NOMINATED MEMBERS:

Shri G.C. Srivastava	New Delhi
Shri Rajiv Mehrishi	New Delhi
Shri K.B. Sharma	Jammu
Shri R.C. Chandiwala	New Delhi
Shri Sunil Bhargava	Jaipur


AUDITORS

Shri A.C. Bubber, FCA	New Delhi
Shri Rajiv Rastogi, FCA	New Delhi

AUDITORS' REPORT

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Chartered Accountants of India as at 31st March, 2003 and also the annexed Income and Expenditure Account for the year ended on the date incorporating the accounts of the Institute's offices, Regional Councils and their branches audited by other auditors. The unaudited accounts of three branches who have not sent the audited accounts have also been incorporated. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted the audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We further report that :-
 - a) We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit;
 - b) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account dealt with the report are in agreement with the books of accounts;
 - c) In our opinion the accounts are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949;
 - d) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements together with the schedules attached and read with the Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts give a true and fair view:
 - i) In the case of Balance Sheet of the state of affairs as at 31st March, 2003 and
 - ii) In the case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date:


A.C. BUBBER
CHARTERED ACCOUNTANT


RAJIV KUMAR RASTOGI
CHARTERED ACCOUNTANT

Place : New Delhi

Date : 18th September, 2003

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2003

	Schedule	Amount 31-03-2003	Rs. In lacs Amount 31-03-2002
SOURCES OF FUNDS:			
Capital Reserves	I	3031.50	2898.91
General Reserve	II	1609.96	1294.09
Other Reserves	III	77.14	82.83
Earmarked Funds	IV	<u>4543.05</u>	<u>3698.79</u>
TOTAL		<u>9261.65</u>	<u>7774.62</u>
APPLICATION OF FUNDS:			
<u>Fixed Assets:</u>			
Gross Block	V	3913.30	3424.35
Less: Depreciation		<u>(1565.51)</u>	<u>(1302.19)</u>
Net Block		2347.79	2122.16
<u>Investments :</u>			
Earmarked Fund Investments	VI	4543.05	3898.79
Other Investments		<u>2448.69</u>	<u>1433.12</u>
		6991.74	5131.91
<u>Current Assets, Loans & Advances :</u>			
Inventories	VII	218.76	188.68
Accounts Receivables	VIII	1153.71	813.49
Cash & Bank Balances		1093.29	1910.34
Loans & Advances	IX	579.98	484.05
Sub - Total		<u>3045.74</u>	<u>3396.56</u>
<u>Less: Current Liabilities & Provisions</u>			
Fees/Income Received in Advance	X	2029.52	2110.92
Creditors for Expenses		574.06	449.41
Provision for Gratuity		179.88	97.95
Other Liabilities		342.01	227.70
Sub - Total		<u>3125.27</u>	<u>2885.98</u>
Net Current Assets		(79.53)	510.58
Miscellaneous expenditure—Software Development (To the extent not written off or adjusted)	XI	1.65	9.97
TOTAL		<u>9261.65</u>	<u>7774.62</u>
Statement of significant accounting policies			
Notes forming part of Accounts.	XV XVI		

DEEPAK DIKSHIT
JOINT SECRETARY

G.O KHURANA
DIRECTOR

ASHOK HALDIA
SECRETARY

SUNIL GOYAL
VICE PRESIDENT

R.BUPATHY
PRESIDENT

As per our Report of even date attached

A.C. BUBBER
CHARTERED ACCOUNTANT

RAJIV KUMAR RASTOGI
CHARTERED ACCOUNTANT

Place : New Delhi

Date: 18/9/03

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2003

	Schedule	Amount 2002-2003	Rs. in lacs Amount 2001-2002
INCOME			
Fees	XII	5285.87	4005.55
Publications		533.56	345.74
Seminars		513.05	486.71
Interest on Investments		414.97	401.84
Provisions no longer required written back		12.71	7.76
Other Income	XIII	473.16	320.74
Prior Period Income		<u>5.32</u>	<u>17.80</u>
TOTAL		<u>7238.64</u>	<u>5586.14</u>
EXPENDITURE			
Salaries & Allowances		1646.00	1297.11
Examination Expenses		786.76	661.75
Information System Audit Course		357.34	89.21
CAAT Course Expenses		3.54	1.75
Distant Education Expenses		494.02	398.75
Publications		126.11	85.78
Journal Expenses		279.14	285.08
Seminar Expenses		559.70	453.24
General & Administrative Expenses	XIV	1210.58	933.23
Travelling & Conveyance-Inland		382.33	309.28
Overseas Relations:			
- Travelling		75.38	51.77
- Fees and Other Expenses		57.83	49.62
Deferred Revenue Expenditure [Policy No VII]		9.58	6.67
Audit Fee			
- Head Office		1.73	1.57
- Other Offices		4.65	2.66
Provision for decline in value of investments		-	27.20
Provision for decline in value of Stock		20.92	4.18
Depreciation		263.93	170.50
Prior Period Expenses		<u>23.10</u>	<u>39.29</u>
TOTAL		<u>6302.64</u>	<u>4868.64</u>
NET SURPLUS		<u>936.00</u>	<u>717.50</u>
Appropriation to Funds/Reserves :			
Education Fund [Policy No. III (b)]		583.22	452.30
Employees Benevolent Fund [Policy No. III (c)]		9.21	8.56
Computerisation Fund			200.00
General Reserve		343.57	56.64
TOTAL		<u>936.00</u>	<u>717.50</u>

Statement of significant accounting policies

XV

Notes forming part of Accounts.

XVI


DEEPAK DIKSHIT
JT. SECRETARY


G.D. KHURANA
DIRECTOR


ASHOK HALDIA
SECRETARY


SUNIL GOYAL
VICE-PRESIDENT


R. BUPATHY
PRESIDENT

As per our Report of even date attached


A.C. BUBBER
CHARTERED ACCOUNTANT


RAJIV KUMAR RASTOGI
CHARTERED ACCOUNTANT

Place: New Delhi

Date : 18/01/03

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE I
CAPITAL RESERVES**

	Rs. in lacs	
	Amount 31-03-2003	Amount 31-03-2002
(A) General:		
Opening balance	1009.89	948.53
Add:		
-Membership Fees [Policy No III (a)]	23.73	14.05
-Donations for Buildings	119.93	38.41
Transferred from:		
- General Reserves	6.82	5.60
- Other Reserves	-	-
- Earmarked Funds - Others	2.70	3.10
Less:		
- Adjustments towards Chandigarh land	(65.37)	-
TOTAL (A)	1097.50	1009.69
(B) Education:		
Opening balance	1689.22	1500.81
Add: Transfer from Education Fund [Policy No. III (d) (iii)]	244.78	188.41
TOTAL (B)	1934.00	1689.22
GRAND TOTAL (A) + (B)	3031.50	2698.91

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE II
GENERAL RESERVES**

	Rs. in lacs	
	Amount 31.03.2003	Amount 31.03.2002
Opening balance	1294.09	1256.31
Add:		
Appropriation from Income and Expenditure Account	343.57	56.64
Transfer from:		
-Earmarked Funds -Golden Jubilee Fund	-	16.62
-Earmarked Funds -Medals & Prizes Fund	-	0.45
-Other Reserves	5.61	73.71
Less transfer to:		
- Earmarked Funds -Research	0.83	0.75
-Earmarked Fund - Others	25.66	20.50
-Other Reserves	-	9.08
-Capital Reserves -General	6.82	(35.93)
TOTAL	1609.96	1294.09

SCHEDULE III
OTHER RESERVES*

	Amount 31.03.2003	Rs in.lacs Amount 31.03.2002
Opening balance	82.83	73.93
Add transfer from:		
- General Reserves	-	9.08
- Earmarked Funds -Others	-	0.10
Less transfer to:		
- General Reserves	5.61	
Net Depletion during the year	0.08 (5.69)	0.28 (0.28)
TOTAL	77.14	82.83

* Other Reserves are reserves such as Library Reserves and Coaching Classes Reserves as appearing in the books of Regional Councils and Branches .

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE IV

EARMARKED FUNDS

	Amount 31.03.2003	Rs. In lacs Amount 31.03.2002
RESEARCH FUNDS		
Opening Balance	361.07	321.69
Transfer from General Reserve	0.83	0.75
Additions during the year	6.86	8.48
Income during the year	29.95 37.64	30.15 39.38
SUB-TOTAL (A)	398.71	381.07
ACCOUNTING RESEARCH FOUNDATION AND BUILDING FUND		
Opening Balance	220.33	201.03
Income during the year	18.24	19.30
SUB-TOTAL (B)	238.57	220.33

COMPUTERISATION FUND

Opening Balance		343.45		130.89
Appropriation from Income & Expenditure Account			200.00	
Income during the year	28.44	28.44	12.56	212.56
SUB-TOTAL (C)		371.89		343.45

GOLDEN JUBILEE CELEBRATION FUND

Opening Balance		-		15.18
Income during the year		-		1.44
Less: Payments during the year		-		-
Transfer to General Reserve		-		(16.62)
SUB-TOTAL (D)		0.00		0.00

EDUCATION FUND

Opening Balance		1819.42		1419.28
Appropriation from Income & Expenditure Account [Policy No. III(b)]	583.22		452.30	
Income during the year	150.64	733.86	136.25	588.55
Less: Transfer to Capital Reserves - Education [Policy No. III(d)(iii)]		(244.78)		(188.41)
SUB-TOTAL (E)		2308.50		1819.42

MEDALS AND PRIZES FUNDS

Opening Balance		54.86		41.59
Additions during the year	0.95		13.08	
Income during the year	4.62	5.57	3.93	17.01
Less: Payments during the year	2.56		3.23	
Transfer to General Reserve		-	0.45	
Adjustments	0.39	(2.95)	0.06	(3.74)
SUB-TOTAL (F)		57.48		54.86

contd...

5

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE IV****EARMARKED FUNDS (Contd)**

	Amount 31.03.2003		Rs. in lacs Amount 31.03.2002	
STUDENTS SCHOLARSHIP FUNDS				
Opening Balance		24.54		23.62
Additions during the year		-		-
Income during the year	2.03	2.03	2.26	2.26
Less: Payments during the year		(1.23)		(1.34)
SUB-TOTAL (G)		25.34		24.54

PENSION FUND

Opening Balance		455.45		419.23
Additions during the year	161.59		28.03	
Income during the year	37.71	199.30	40.25	68.28
Less: Payments during the year		(40.90)		(32.06)
SUB-TOTAL (H)		613.85		455.45

LEAVE ENCASHMENT FUND

Opening Balance		221.52		195.16
Additions during the year	72.49		36.93	
Income during the year	18.34	90.83	18.73	55.66
Less: Payments during the year		(34.23)		(29.30)
SUB-TOTAL (I)		278.12		221.52

EMPLOYEES BENEVOLENT FUND

Opening Balance		36.02		26.07
Appropriation from Income & Expenditure Account [Policy No.III (c)]	9.21		8.56	
Income during the year	2.98	12.19	2.51	11.07
Less: Payments during the year		(1.35)		(1.12)
SUB-TOTAL (J)		46.86		36.02

OTHER FUNDS (Regional Councils & Branches)

Opening Balance		162.13		127.10
Add/Less: Adjustments	(0.31)		0.10	
Additions during the year	9.61		15.63	
Income during the year	11.96		11.64	
Transfer from General Reserve	25.66		20.50	
		46.92		47.87
Less: Transfer to Capital Reserves- General	2.70		3.10	
Transfer to Other Reserves			0.10	
Payments during the year	2.62	(5.32)	9.64	(12.84)
SUB-TOTAL (K)		203.73		162.13
GRAND TOTAL		4543.05		3698.79

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE "V"
FIXED ASSETS

ASSETS	G R O S S B L O C K			D E P R E C I A T I O N B L O C K			N E T B L O C K	
	Cost as at 1.4.2002	Additions during the year	Adjustments /Transfers / Sale	Cost as at 31.3.2003	Upto 1.4.2002	Adjustments For the year	Upto 31.3.2003	W.D.V as on 31.3.2003
1. Land - Free Hold (Note No. 9)	169.67	31.48	(59.62)	141.53	0.00		0.00	141.53
2. Land - Lease Hold	9.69			9.69	2.12	0.22	2.34	7.35
3. Land (A.R.F) - Lease Hold	289.45			289.45	15.49	3.22	18.71	270.74
4. Buildings	884.10	33.64		917.74	291.17	31.31	322.48	595.26
5. Electric Installations & Fittings	142.43	18.80	(0.48)	160.75	66.76	7.17	74.93	85.82
6. Air Conditioning	100.40	35.29	0.45	136.14	58.45	8.87	67.50	68.64
7. Furniture & Fixtures	340.02	43.64	(0.53)	383.13	153.88	20.89	174.47	208.66
8. Lifts	41.63	18.05		59.68	13.29	3.72	16.99	42.69
9. Office Equipments	251.16	39.99	(0.69)	290.46	124.50	22.59	147.17	143.29
10. Vehicles	22.92	5.89	(3.28)	25.53	7.88	3.79	9.27	16.26
11. Library Books	218.38	29.28	(0.06)	247.60	165.02	82.43	247.60	0.00
12. Computers	503.19	45.27	(3.07)	545.39	403.63	79.72	484.05	61.34
SUB-TOTAL	2973.04	301.33	(67.28)	3207.09	1302.19	263.93	1565.51	1641.58
13. Building Work in Progress	451.31	270.12	(15.22)	706.21	0.00		0.00	706.21
TOTAL	3424.35	571.45	(82.50)	3913.30	1302.19	263.93	1565.51	2347.79
Previous Year	3054.86	386.65	(17.16)	3424.35	1139.03	170.50	1302.19	2122.16

Rs in lacs

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE "VI"
INVESTMENTS

	Amount 31-03-2003	Rs in lac Amount 31-03-2002
LONG TERM INVESTMENTS		
(I) Units with Unit Trust of India:		
(i) Unit Scheme for Charitable & Religious Trust Registered Societies (CRTS - 81)	114.36	448.31
Less: Decline in Value of Investments	<u>28.96</u> <u>85.40</u>	<u>105.62</u> <u>342.69</u>
	15.29	15.29
(ii) Units 1964 Scheme	<u>2.80</u>	<u>6.95</u>
Less: Decline in Value of Investments	12.49	8.34
(iii) Institutional Investors Special Fund Unit Scheme(IISFUS- 98)	<u>442.09</u>	<u>387.80</u>
	539.98	738.83
(II) Fixed Deposits with scheduled Banks	6451.76	4393.08
Total Investments	<u>6991.74</u>	<u>5131.91</u>
ALLOCATED TO:-		
Earmarked Fund Investments	4543.05	3698.79
Other Investments	2448.69	1433.12
Total	<u>6991.74</u>	<u>5131.91</u>

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE VII:

INVENTORIES

	Amount 31.03.2003	Rs.in lacs Amount 31.03.2002
Publications and Study Materials	210.35	150.08
Paper for Study Materials & Publications (Including Stock of Paper with Printers - Rs.54.71lacs Previous year Rs.59.19 lacs)	59.22	68.03
Stationery & Other Items	19.29	19.75
Sub-total	<u>288.86</u>	<u>237.86</u>
Less : Provision for obsolete stock	<u>(70.10)</u>	<u>(49.18)</u>
Total	<u>218.76</u>	<u>188.68</u>

SCHEDULE VIII:**ACCOUNTS RECEIVABLE**

	Amount 31.03.2003	Rs.in lacs Amount 31.03.2002
Interest Accrued on Investments	998.77	644.98
Other Receivables	162.54	175.98
Less: Provision for doubtful receivables	(7.60)	(7.47)
	154.94	168.51
Total	1153.71	813.49

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE IX:****LOANS & ADVANCES (Considered Good)**

	Amount 31.03.2003	Rs.in lacs Amount 31.03.2002
Advances to Staff (Housing, Vehicle & Other loans)	190.59	182.70
Interest Recoverable from Staff Loans	68.36	64.27
Security Deposits	14.67	15.24
Other - Advances & Pre-payments	306.36	221.84
Total	579.98	484.05

SCHEDULE X:**FEES/INCOME RECEIVED IN ADVANCE**

	Amount 31.03.2003	Rs.in lacs Amount 31.03.2002
Examination Fees	742.80	773.03
Journal Subscription	11.25	37.92
Membership Fee	252.01	247.26
Students' Fee	41.96	79.78
Tuition Fee	811.23	885.03
Information System Audit Course Fee	132.02	55.08
Seminar Fees & Other Collections	38.25	32.82
Total	2029.52	2110.92

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE XI:****MISCELLANEOUS EXPENDITURE - SOFTWARE DEVELOPMENT**

(To the extent not written off or adjusted)

	Amount 31.03.2003	Rs.in lacs Amount 31.03.2002
Opening balance	9.97	14.59
Addition during the year	1.26	2.05
Less: Charged to Income & Expenditure during the year	(9.58)	(6.67)
TOTAL	1.65	9.97

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE XII****FEES :**

	Amount 2002-2003	Rs.in lacs Amount 2001-2002
Entrance Fee	9.01	4.61
Membership Fee	1262.56	1156.22
Students' Registration Fee	19.44	55.90
Students' Association Fee	3.24	9.32
Distant Education Tuition Fee	1815.66	1282.67
Examination Fee	1685.54	1385.70
Information System Audit Course Fee	479.31	109.16
CAAT Course Fee	11.11	1.97
TOTAL	5285.87	4005.55

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XIII

OTHER INCOME

	Amount 2002-2003	Rs. in lacs Amount 2001-2002
Students' Newsletter	7.21	3.43
Income From Journal -- Advertisement	0.61	0.50
Income from Journal -- Subscription	86.86	66.13
News Letters (Regional Councils & Branches)	28.76	19.22
Computer Centres	32.56	13.75
Fees for filing Disciplinary Cases	0.26	0.09
Campus Interview	36.04	28.16
Expert Advisory Committee Fee	7.55	3.45
Interest on Staff Loans	15.54	12.72
Income from Coaching Classes (Regional Councils & Branches)	178.51	115.36
Others	79.26	57.93
Total	473.16	320.74

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XIV

GENERAL & ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Amount 2002-2003	Rs.in lacs Amount 2001-2002
Printing & Stationery	136.28	106.84
Postage, Telegrams & Telephones	218.01	193.19
Rent, Rates & Taxes	166.40	137.08
Repairs & Maintenance	232.77	115.01
Professional Fees	43.01	24.62
Computer Centres	14.14	7.36
Students' Newsletter	50.83	47.41
News Letters (Regional Councils & Branches)	72.44	61.14
Campus Interview	17.66	12.27
Bank Branch Audit Empanelment	7.20	6.30
Merit Scholarship	2.93	3.70
Grants to Students' Associations and Reference Libraries	1.52	1.74
Expenses for Coaching Classes (Regional Councils & Branches)	96.63	68.03
Other Expenses	150.76	148.54
Total	1210.58	933.23

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE XV****STATEMENTS ON SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES****I. ACCOUNTING CONVENTION**

The accounts are drawn up on historical cost basis and have been prepared in accordance with the applicable Accounting Standards.

II. REVENUE RECOGNITION

A) 1/3rd portion of the Entrance Fees from Associate members is treated as Income.

B) Tuition/Course Fee received are recognised as Income on the following basis :-

1) Pre-Training (Foundation/PE-I/PE-II) PE-II with Articles.

- 100% of fees from the Students registered during the first quarter of the year; &
- 50% of fees alongwith registration fee from the Students registered thereafter, the balance being treated as Income in the succeeding year.

2) Others (Inter and Final).

a) Fees Received in lump sum

1/3rd of fees from the Students registered in the year of receipt and the balance 2/3rd in the following two years on equated basis.

b) Fees received in installments

- i) First instalment – 50% of fees from the students registered in the year of receipt and the balance of 50% in the following two years on equated basis.
- ii) Second Instalment – 100% in the year of receipt.

3) General Management Skills & Compulsory Computer Training Course

In the year of receipt.

4) Information System Audit Course/CAAT

- i) Information System Audit Course Fee and the direct expenses attributable to the same are recognised in the year in which the practical training is commenced.
- ii) CAAT Course Fee – In the year of receipt.

C Examination Fee

Fees and direct expenses attributable to examinations are recognised in the year in which the examinations are held.

D Income from Investments.

- i) Dividend on investments in units is recognised as income on the basis of entitlement to receive.
- ii) Income on Interest bearing securities and fixed deposits with banks is accounted for on accrual basis.
- iii) Income from investments is allocated to Earmarked Funds on opening balances of the respective Earmarked Funds on the basis of weighted average method.

E Journal Subscription

- i) 1/3rd of the Journal Subscription received from students under the old scheme for a period of three years is treated as Income in the year of receipt and the balance 2/3rd in the following two years on equated basis.
- ii) Yearly subscription received from others on account of Journal is booked in the year of receipt.

III ALLOCATIONS/TRANSFER TO CAPITAL RESERVE AND EARMARKED FUND

- a) Admission Fee from Fellow Members and 2/3rd portion of the Entrance Fee from Associate Members are directly taken to Capital Reserve – General.
- b) 50% of the surplus arising out of students related activities is transferred to Education Fund.
- c) 0.75% of Membership Fee (Associate and Fellow and Certificate of Practice Fee) received from the members during the year is allocated to the Employees' Benevolent Fund.
- d) Transfer to Capital Reserve – Education, from the following Earmarked funds :-
 - i) From Computerisation Fund 100% of the cost of purchase of computers and related accessories in relation to Decentralised Offices and Head Office Computerisation Project.
 - ii) From Accounting Research Foundation & Other Building Fund 100% of the cost of Fixed Assets relating to Accounting Research Foundation.
 - iii) From Education Fund 50% of the cost of additions (net of deductions) of other Fixed Assets.

IV FIXED ASSETS/DEPRECIATION

- a) Fixed Assets are stated at original cost less depreciation.
- b) Leasehold lands are being amortised over the leased period.
- c) During the year, the rates of depreciation charged on Computers and Library Books were changed. Due to this, the Depreciation charged is more by Rs.59.49 Lacs to Income & Expenditure Account.
- d) Depreciation on addition is provided on monthly pro-rata basis.
- e) Depreciation is provided on the written down value method at the following rates:-

Buildings	5%
Air-conditioners & Office Equipments	15%
Lifts, Electrical Installations & Furniture and Fixtures	10%
Vehicles	20%
Computers	60%
Library Books	100%

V INVESTMENTS

- a) Investments held or intended to be held for a period of more than one year are treated as long term investments.
- b) Other investments are treated as short-term investments.
- c) All investments are valued at cost. Permanent decline in value is provided for.

VI INVENTORIES

- a) Stock of paper, Stationery and Other Items are valued at cost, Publications and Study Material at cost on FIFO Method.
- b) A provision of 100% is made on the cost of stock of old study material and Institutes publications older than one year. Further a provision of 25% is made on the cost of remaining stock of BOS publications except new syllabus.

VII DEFERRED REVENUE EXPENDITURE

Computerisation expenses towards software development charges including cost of software purchased are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off equally over a period of three years.

VIII TERMINAL/RETIREMENT BENEFITS

- a) Liability determined towards Gratuity based on actuarial valuation done by LIC is charged to Income & Expenditure Account.
- b) Liability determined towards Pension and Leave Encashment based on actuarial valuation is charged to Income and Expenditure Account and separate Earmarked Funds are maintained for the same.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE XVI****NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS**

1. CONTINGENT LIABILITY : A sum of Rs.22.98 Lacs towards disputed amount being Property/Building Tax in respect of four branches has not been provided for (Previous year Rs.18.25 Lacs),
2. Claims of Rs.9.02 Lacs (Previous year Rs.9.02 Lacs) from various parties have not been acknowledged by the Institute.
3. Exemption in respect of Income Tax has been granted under Section 10 (23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961 upto the Assessment Year 2002-03. Application for renewal of exemption is under consideration of the tax authorities.
4. Estimated amount of capital commitment (net of advances) is Rs.274.13 Lacs (Previous year Rs.449.47 Lacs).
5. Interest accrued on Investments amounting to Rs.998.77 lacs (Previous year Rs.644.98 lacs) has been included under Accounts Receivables.
6. Land Freehold includes Rs.2.62 Lacs relating to the land at Hubli which is under litigation
7. Previous year figures have been re-grouped and re-classified wherever considered necessary.

CASH FLOW STATEMENT					
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2003					
(Rs. in lacs)					
	2002-2003		2001-2002		
A. Cash flows from operating activities					
Net Surplus		936.00			717.50
Adjustments for:					
Depreciation	263.93		170.50		
Interest received from other investments	(414.97)	(151.04)	(401.84)	(231.34)	
Operating profit before working capital changes		784.96			486.16
Increase in Inventories	(30.08)		(58.02)		
Decrease/Increase in Amounts Receivables	(340.22)		(12.99)		
Increase/Decrease in Loans & advances	(95.93)		4.61		
Decrease/Increase in Fees/Income received in advance	(81.40)		344.19		
Increase/Decrease in Creditors for Expenses	124.65		(6.64)		
Increase/Decrease in Provision of Gratuity Fund	81.73		(12.91)		
Increase in Other Liabilities	114.31		67.71		
Decrease in Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off or adjusted)	8.32		4.62		
		(218.62)			330.57
Net cash from operating activities		566.34			816.73
B. Cash flows from investing activities					
Acquisition of Fixed Assets	(488.95)		(376.83)		
Acquisition of Investments	(1859.83)		(157.05)		
Interest received from other investments	414.97		401.84		
Income from Earmarked Funds Investments	304.30		278.41		
Capital Receipts	246.12		78.29		
Net Cash from Investing Activities		(1383.39)			224.66
Net increase/Decrease in cash and cash equivalents		(817.05)			1041.39
Cash and Cash equivalents at the beginning of period		1910.34			868.95
Cash and Cash equivalents at the end of period		1093.29			1910.34

DR. ASHOK HALDIA, Secy.

[No. ADVT/III/IV/104/03-Ext.]